राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 188

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, सोमवार, 16 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

लारा बोले, विराट कोहली के डीएनए में है आक्रामकता

>>12

नागरिकता कानून पर जामिया और एएमयू में उपद्रव

अराजकता ▶ विरोध के नाम पर हिंसा की आग बंगाल के बाद दिल्ली और अलीगढ़ में फैली, राजधानी में बसें फूंकीं, पुलिस व राहगीरों पर हमला

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के नाम पर असम और बंगाल से शुरू हुई हिंसा की लपटों ने रविवार को राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को भी चपेट में ले लिया। दिल्ली के जामिया मिल्लिया विवि और अलीगढ़ के एएमयू में उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा बवाल किया। दिल्ली में कई बसें और पुलिस चौकियां फूंक दी गईं। यहां छात्रों, पुलिसकर्मियों और दमकलकर्मियों समेत करीब 40 लोग घायल हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में डीआइजी समेत 50 लोग घायल हो गए।

दिल्ली में सीएए के विरुद्ध जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तीन दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। रविवार को छात्रों के प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के शामिल हो जाने के बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। उत्पातियों ने पूरे दिन दिल्ली-नोएडा रोड और मथुरा रोड को ठप रखा। शाम करीब पांच बजे मथुरा रोड पर सूर्या होटल के सामने चार बसों और बटला हाउस मेन चौक पर बनी पुलिस चौकी को फूंक दिया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में टकराव के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस के दो वाहनों में आग लगा दी। हिंसा में छह पुलिसकर्मी और दो दमकलकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई मोटरसाइकिलें फूंक दी गईं। हिंसा में कई राहगीर घायल हो गए। पुलिस ने लाठी भांजकर हिंसा पर उतारू भीड़ को खदेड़ा। सूत्रों के अनुसार, 31 छात्र भी नजदीकी अस्पतालों में लाए गए, जिनमें से 11 को भर्ती किया गया है। हिंसा के बाद जामिया के चीफ प्रोक्टर वसीम अहमद खान ने पुलिस पर जबरन कैंपस में घुसने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि हालात काबू करने के लिए कैंपस में जाना पड़ा। फिलहाल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद कर दी गई हैं और पांच जनवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है।

कानून पर बवाल (विशेष) पेज>>5

- एएमयू में छात्रों ने हवाई फायरिंग की, देसी बम फोड़े
- हालात पर काबू पाने दोनों विवि में घुसी पुलिस

नागरिकता कानून को लेकर नई दिल्ली में रविवार को प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस दौरान वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। नई फ्रेंडस कॉलोनी के समीप उपद्रवियों ने बस और कार को आग के हवाले कर दिया। संजय

मेट्रो के कई स्टेशन बंद

हिंसा और आगजीन के कारण दिल्ली में जीटीबी नगर, शिवाजी स्टेडियम, पटेल चौक, विश्वविद्यालय, वसंत विहार, मुनिरका, आरके पुरम, सुखदेव विहार, आश्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ओखला विहार और जसोला विहार मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

एएमयू में रैली से बिगड़े हालात

जामिया विवि में हुई पुलिस कार्रवाई पर आक्रोश जताने के लिए देर शाम निकाली गई एएमयू छात्रों की रैली हिंसक टकराव में बदल गई। एएमयू सर्किल पर रोके जाने पर छात्रों ने पथराव के साथ हवाई फायरिंग की और देसी बम फोड़े। इस दौरान प्रॉक्टोरियल टीम, डीआइजी डॉ. प्रीतेंदर सिंह, एसपी सिटी के अलावा बीस जवान घायल हो गए। पुलिस आंसू के गोले छोड़ते हुए कैंपस में अंदर घुस गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब एएमयू के अंदर वज्र वाहन गए। एएमयू के अंदर से आठ युवकों को हिरासत में लिया गया है। जिले में इंटरनेट सेवा सोमवार रात दस बजे तक के लिए बंद कर दी गई।

नहीं बुझ रही बंगाल की आग, रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी

बंगाल में तीसरे दिन भी उत्पातियों ने मुर्शिदाबाद के पास रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। रेल पटरी पर टायर जलाकर ट्रेनों को रोका और पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस के वाहन को भी फूंक दिया। एहतियातन कई ट्रेनों को रद कर दिया गया। छह जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

बिहार, आंध्र व तमिलनाडु में भी प्रदर्शन

बवाल की आग से बिहार भी अछूता नहीं रहा। पटना के अशोक राजपथ से लेकर कारगिल चौक तक जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने एक दर्जन वाहनों को फूंक दिया। पथराव में डीएसपी समेत एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। कारगिल चौक के पास दो पुलिस पोस्ट फूंक दी गईं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को 15 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ।

असम में सुधर रहे हालात

असम में भड़की हिंसा का दौर थमता दिख रहा है। रविवार को गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए राज्य पर्यटन विभाग ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। कर्फ्यू में ढील के बाद राशन की दुकानों व पेट्रोल पंपों पर लोगों की कतारें दिखीं। यहां पिछले दिनों हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या चार हो चुकी है। मेघालय में भी हालात सामान्य हो रहे हैं।

कांग्रेस भड़का रही अशांति : मोदी

'कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं विरोध के नाम पर आग लगाने वाले'

राज्य ब्यूरो, रांची

- कहा-नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष का विरोध बताता है कि हमारा फैसला हजार फीसद सही है
- जो काम पाक नागरिक और पाकिस्तानी पैसों पर पलने वाले करते थे, वह अब कांग्रेस कर रही है
- शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को साधुवाद दिया, कहा- यही है लोकतंत्र

नागरिकता संशोधन कानून पर देश में कुछ राज्यों में भड़की हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सीधे-सीधे आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि जो हिंसा और आगजनी में लिप्त हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। झारखंड के दुमका में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, विपक्षी दलों की करतूत बताती है कि नागरिकता संशोधन कानून एक हजार फीसद सही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सीएए को लेकर नार्थ ईस्ट में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विरोध करते-करते कांग्रेस अब देश का ही विरोध करने लगी है। लंदन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'अब तक यह काम पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तानी पैसों पर पलने वाले लोग किया करते थे, लेकिन अब कांग्रेस भी यही करने लगी है। अगर कोई गिला शिकवा है तो बंद कमरे में बात होती, चाय पीते और अपनी बात रखते। अब कांग्रेस वालों से कोई उम्मीद नहीं बची। वे सिर्फ अपने परिवार के लिए सार्वजनिक जीवन में आए हैं। देश और समाज के हित में काम करने वालों को यह कभी स्वीकार नहीं करते हैं।'

असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए साधुवाद देते हुए मोदी ने कहा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन जो लोग असम व बंगाल में आग लगा रहे हैं, उनकी पहचान कपड़ों से ही हो जा रही है। हमारा विरोध करते-करते विपक्षी दल तमाम सीमा रेखा लांघ जाते हैं और देश का विरोध करने लगते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड के दुमका जिले के हवाई अड्डे पर चुनावी सभा को संबोधित किया और पहली बार सीएए का जिक्र किया। जागरण

देश को बदनाम करने का काम हो रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि लंदन में प्रदर्शन से हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम हो रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट अब ऐसा व्यवहार कर रहा है, जिससे देश का मान सम्मान बढ़े। यही तो लोकतंत्र है। लंदन में भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तान वालों ने उस समय प्रदर्शन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर फैसला दिया। इसी प्रकार, अनुच्छेद 370 पर हमारे निर्णय के बाद भी प्रदर्शन किया गया।

भाजपा देती है आपके अधिकार को सुरक्षित रखने की गारंटी

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से झारखंड में डबल इंजन की सरकार को फिर से स्थापित करने की बात करते हुए कहा कि आपके जल, आपके जंगल और आपके अधिकार को सुरक्षित रखने की गारंटी भाजपा देती है। झामुमो, कांग्रेस और वामपंथियों के लिए आदिवासी क्षेत्रों का विकास प्राथमिकता में कभी भी नहीं रहा है। यही कारण है कि आजादी के इतने वर्षों तक आदिवासी क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा, कि सड़क, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं से आदिवासी वंचित रहे हैं। यह भाजपा को मंजूर नहीं है।

सरोकार

हरपुरा के हर आंगन में खिलखिलातीं हैं बेटियां

टीकमगढ़ (मप्र) : भ्रूण लिंग परीक्षण और अजन्मी कन्याओं को मार डालने की चिंताओं की बीच मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ का हरपुरा मड़िया गांव मिसाल पेश कर रहा है। यहां बेटियों के जन्म पर मंगल गीत गाए जाते हैं। 2300 की आबादी वाले गांव में एक हजार पुरुषों पर 1096 महिलाएं हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

कॉफी बढ़ाएगी हिमाचल प्रदेश में किसानों का जायका

ऊना : हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी इलाके में जंगली जानवरों व बेसहारा पशुओं के कारण खेती से मुंह मोड़ चुके किसानों के लिए कॉफी की खेती नई उम्मीद लेकर आई है। इससे बंजर खेत लहलहाने लगे हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने की आस जगी है। धर्मसाल महंता इलाके में किसानों ने कॉफी के दो हजार पौधे लगाए हैं। इनमें से 90 फीसद पूरी तरह से ठीक हैं। (पेज-13)

डॉक्टरों की सुरक्षा वाला विधेयक ठंडे बस्ते में

- गृह मंत्रालय ने कहा, इस संबंध में अलग कानून की जरूरत नहीं
- दूसरे पेशे से जुड़े लोग भी कर सकते हैं अलग कानून की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया विधेयक गृह मंत्रालय की आपत्तियों के बाद ठंडे बस्ते में चला गया है। मंत्रालय इस विधेयक को 13 दिसंबर को खत्म हुए शीतकालीन सत्र में रखना चाहता था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'कानून मंत्रालय ने बिल के प्रारूप पर सहमति दे दी थी, लेकिन अंतर मंत्रालय परामर्श के दौरान कहा गया कि किसी पेशा विशेष के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।' 'गृह मंत्रालय ने किसी खास पेशे से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाने के लिए अलग कानून बनाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम है। ऐसा हुआ तो वकालत व पुलिस आदि पेशे से जुड़े लोग भी सुरक्षा के लिए विशेष कानून की मांग करने लगेंगे।'

3-10 साल सजा, 2-10 लाख तक के जुर्माने का था प्रावधान : ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए हेल्थ सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट (प्रोहिबिशन ऑफ व्यॉलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी) नामक बिल का प्रारूप तैयार किया गया था। इसके तहत डॉक्टरों या स्वास्थ्यकर्मियों को घातक नुकसान पहुंचाने पर 3-10 साल तक की सजा और 2-10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर छह माह से पांच साल तक की सजा और 50 हजार से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। सूत्रों ने कहा कि विधेयक के प्रारूप में क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए बाजार मूल्य से दोगुना तथा मारपीट व चोट पहुंचाने की स्थिति में 1-5 लाख रुपये तक के मुआवजे का भी प्रावधान था। मुआवजा न देने पर दोषी से मुआवजे की राशि भूराजस्व संग्रह कानून-1890 के तहत राजस्व बकाया के रूप में वसूली जाती। इस विधेयक के दायरे में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल छात्र, जांच सेवाएं और एंबुलेंस के चालकों को रखा गया है।

विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए बनी थी आठ सदस्यीय उप समिति पेज>>3

अविवाहित और विधवा कर्मियों की जोड़ियां भी बनवाएगा आइटीबीपी

- वैवाहिक पोर्टल की शुरुआत करने वाला पहला अर्धसैनिक बल बना आइटीबीपी
- एलएसी पर चीन के साथ लगती सीमा की सतर्क निगरानी के लिए जाना जाता है यह बल

प्रतीकात्मक फोटो

अर्धसैन्य बलों में 2.5 लाख से ज्यादा अविवाहित आंकड़ों के आधार पर गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अर्धसैन्य बलों की कुल क्षमता करीब 10 लाख में से 2 .5 लाख से ज्यादा अविवाहित हैं। अर्धसैन्य बलों में एनएसजी और एनडीआरएफ के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसएफ, एसएसबी और आइटीबीपी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आइटीबीपी की यह शुरुआत प्रशंसनीय है। हालांकि, यह एक वैकल्पिक सुविधा है।

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आइटीबीपी) अब अपने अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा कर्मचारियों की जोड़ियां भी बनवाएगा। इस क्रम में उसने खास वैवाहिक वेबसाइट लांच की है। इसके जरिये आइटीबीपी के सदस्यों को अपने बल के भीतर जोड़ी तलाशने में मदद मिलेगी। यह पहला मौका है जब किसी अर्धसैन्य बल ने ऐसी पहल की है।

आइटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अर्धसैन्य बल के सदस्य दुर्गम पहाड़ी सीमा क्षेत्र में तैनात होते हैं। कठिन ड्यूटी के दौरान जीवन साथी की मौजूदगी से थोड़ा सुकून मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को वैवाहिक पोर्टल विकसित करने को कहा था। यह पोर्टल अर्धसैन्य बल में काम करने वाले दंपती की अलग-अलग तैनाती की समस्या को कम करने में भी मदद करेगा। आइटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर नौ दिसंबर को इस वैवाहिक पोर्टल का लिंक भी साझा किया गया है।

आइटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडेय ने बताया, 'पोर्टल पर अब तक 150 पंजीकरण हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि और भी जरूरतमंद सदस्य इस पर पंजीकरण कराएंगे। इसका इस्तेमाल अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा कर्मचारी कर सकेंगे।' उन्होंने बताया कि पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति अथवा महिला कर्मी की व्यक्तिगत सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें उसकी रैंक, आइटीबीपी में सेवा शुरू करने की तारीख, वर्तमान तैनाती, गृहनगर की लोकेशन व तस्वीर शामिल होगी। जब कोई पुरुष या महिला रुचि दिखाएगा तो उसके पास ई-मेल और एसएमएस पहुंच जाएंगे।

आइटीबीपी के 25 हजार जवान व एक हजार युवतियां अविवाहित : वर्ष 1962 में चीन से युद्ध के बाद 90 हजार क्षमता वाले आइटीबीपी की स्थापना की गई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में दक्ष यह अर्धसैन्य बल चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा करता है। आइटीबीपी में फिलहाल 25 हजार अविवाहित पुरुष व एक हजार महिलाएं विभिन्न पदों पर तैनात हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अर्धसैन्य बल की 333 जोड़ियां ऐसी हैं, जिनके दोनों सदस्य आइटीबीपी का हिस्सा हैं। बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य भी हैं जिन्हें समान बल में जीवन साथी की तलाश रहती है। सरकारी नियम भी ऐसी जोड़ियों के लिए एक ही जगह पर तैनाती को प्राथमिकता देता है।

कई जन्म लेने के बाद भी राहुल नहीं बन सकते सावरकर : संघ

नई दिल्ली : भाजपा के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कई जन्म लेने के बाद भी राहुल सावरकर नहीं हो सकते। भले ही उन्होंने अनादर या अपमान करने के लिए ही कहा है, लेकिन उनका कहना सही है कि वे सावरकर नहीं हैं। (पेज-3)

सात साल पहले हुई दरिंदगी, अब तक देश को है इंसाफ का इंतजार

नई दिल्ली : दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में बेटी निर्भया छह दरिंदों का शिकार हुई थी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश सड़क पर उतरा था। इसके बाद न सिर्फ सरकार ने कानून बदला बल्कि कोर्ट ने भी चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। एक दोषी ने जेल में खुदकशी कर ली थी, जबकि छठा आरोपित नाबालिग था। विडंबना ही है कि अब भी देश को इंसाफ का इंतजार है। (पेज-7)

इस महीने के अंत तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कहा है कि इस माह के अंत तक पैन को आधार से लिंक करना ही होगा। आइटी विभाग ने कहा है कि बेहतर कल के निर्माण व बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवाएं पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करें। तय समय-सीमा के भीतर यह लिंकिंग प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। (पेज-10)

बड़ी बहस

सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, संविधान पीठ कह चुकी है, विदेशियों का मौलिक अधिकार सिर्फ जीवन और स्वतंत्रता तक सीमित

आसान नहीं होगा नागरिकता कानून को खारिज कराना

माला दीक्षित, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून पर काफी हंगामा मचा है। सुप्रीम कोर्ट में भी दर्जन भर से ज्यादा याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई है। बुधवार को इन पर सुनवाई की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि संशोधित कानून क्या कहता है और कोर्ट में कानून की वैधानिकता परखने का क्या मानदंड है? क्या यह कानून उन पर खरा उतारता है? कानून का विश्लेषण करने, तय मानदंड व पूर्व के फैसलों को देखने से लगता है कि कोर्ट में इसे खारिज कराना बहुत आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोर्ट यह देखेगा कि इस कानून से किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताते हुए संविधान की धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे और अनुच्छेद 14 में दिए गए बराबरी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि अनुच्छेद 14 तर्कसंगत वर्गीकरण की इजाजत देता है और इस कानून में भी तर्कसंगत वर्गीकरण है। कानून किस उद्देश्य से लाया गया है यह कानून के उद्देश्य में ही स्पष्ट है। इसमें धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। यह कानून हर तरह के शरणार्थी को नागरिकता देने की बात नहीं कर रहा। धार्मिक रूप से सताए शरणार्थियों और अपने बेहतर जीवन और निवास की सुविधा की आस में आए शरणार्थियों में अंतर है। तर्कसंगत वर्गीकरण के आधार पर ही अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था या आरक्षण की अवधारणा टिकी है।

संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का है पूर्ण अधिकार : कानून को चुनौती देने के दो आधार होते हैं। पहला संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है कि नहीं और दूसरा कि कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं करता। मौजूदा मामला देखें तो संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का पूर्ण और अबाधित अधिकार देता है।

कोर्ट देखेगा किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है : अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन पर रिट दाखिल करने का अधिकार देता है। यदि पीड़ित स्वयं कोर्ट नहीं आ सकता तो उसकी ओर से कोई और याचिका दायर कर सकता है। ज्ञानंत कहते हैं कि इस मामले में कोर्ट यह देखेगा कि किसके और किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। जिनके मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही जा रही है क्या वे भारतीय नागरिक हैं? किसी विदेशी का नागरिकता पाने का मौलिक अधिकार कैसे हो सकता है? अगर किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जा रही हो तो कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। ज्ञानंत कहते हैं कि यह संसद का विवेकाधिकार है कि वह किसे नागरिकता दे और किसे न दे। संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन का तर्क गलत है, क्योंकि यहां संविधान में संशोधन नहीं किया गया है।

विदेशियों को देश में बसने का मौलिक अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हंस मुलर ऑफ न्यूनबर्ग बनाम प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता मामले में 1955 में दिए गए फैसले में कहा था कि विदेशियों का मौलिक अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक ही सीमित हैं। उन्हें अनुच्छेद 19 (1)(ई) के तहत देश में कहीं भी बसने और रहने का मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। कोर्ट ने कहा था कि भारत सरकार को विदेशियों को बाहर निकालने का असीमित और पूर्ण अधिकार है। संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जो सरकार के इस अधिकार पर रोक लगाता हो।

संविधान पीठ के इस फैसले पर 1991 में मिस्टर लुइस डे रेड्ट बनाम भारत सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर मुहर लगाई। 1995 में डेविड जॉन होपकिंग मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने उद्धृत किया। साथ ही कहा कि भारत सरकार के पास नागरिकता देने से मना करने की असीमित शक्ति है। सरकार बिना कारण बताए नागरिकता देने से मना कर सकती है। विदेशी नागरिक अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय नागरिकों से बराबरी के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

अगप का यूटर्न, जाएगी सुप्रीम कोर्ट पेज>>5

126 करोड़ के भूमि घोटाले में आरोपित सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले मामले में ग्रेटर नोएडा बीटा दो कोतवाली पुलिस ने प्राधिकरण के तत्कालीन एसीईओ व सेवानिवृत्त पीसीएस सतीश कुमार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सतीश कुमार मूलरूप से शामली के अछौया गांव के रहने वाले हैं और ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक जार सोसायटी में रह रहे थे।

गौरतलब है कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 2013-14 में हुए भूमि घोटाले के संबंध में तीन जून 2018 को बीटा दो कोतवाली में प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ सेवानिवृत्त आइएएस पीसी गुप्ता समेत 21 आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपित पीसी गुप्ता को 22 जून 2018 को मध्य प्रदेश के दतिया से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मास्टर प्लान से बाहर जाकर प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदी गई थी। इसके बाद उसी जमीन का मुआवजा अपने रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह बांटा गया।

सीबीआइ के संपर्क में थे आरोपित : सीबीआइ केस को अपने हाथ में लेने से पहले प्राथमिक पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान गाजियाबाद में आरोपितों से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ इंस्पेक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस मामले में सीबीआइ के एसआइ की भी गिरफ्तारी हुई थी।

> आरोपित सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। घोटाले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
>
> -रणविजय सिंह, एसपी देहात, ग्रेटर नोएडा

9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा रविवार को राजधानी में। इसके चलते रविवार को सुबह कोहरा भी दिखाई दिया। सुबह आठ बजे पालम इलाके में पारदर्शिता 200 मीटर दर्ज की गई तो वहीं सफदरजंग में पारदर्शिता 300 मीटर दर्ज की गई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

अनशन से स्वाति की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली : महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अनशन कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद की तबीयत 13वें दिन खराब हो गई। इसके चलते डॉक्टरों ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया। दुष्कर्म के मामले में दोषी को छह माह में फांसी की सजा देने का कानून बनाने की मांग को लेकर राजघाट के समता स्थल पर स्वाति अनशन कर रही थीं। अस्पताल में उन्हें आइसीयू में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया। अब उनकी हालत स्थिर है। हालांकि स्वाति ने ग्लूकोज चढ़वाने से इन्कार किया था। डॉक्टरों के मुताबिक, स्वाति की हालत अब पूरी तरह से स्थिर है। उन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। स्वाति को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। कुछ जरूरी दवा दी गई है। उनका अनशन भी टूट चुका है। रक्तचाप और मधुमेह अब पूरी तरह से सामान्य है। (जासं)

फिर खराब होने लगी हवा की गुणवत्ता

नई दिल्ली : पश्चिमी विक्षोभ के चलते जोरदार बारिश व तेज हवाओं के चलते तीन दिन साफ-सुथरी रही वायु गुणवत्ता अब बिगड़ने लगी है। हवा की रफ्तार कम होने के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) सामान्य से बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। वहीं, कई स्थानों पर यह खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता स्तर 84 अंक रहा, जो कि सामान्य स्थिति में होता है, लेकिन सोमवार को यह बहुत खराब की श्रेणी में जा सकता है। दरअसल, हवा की गति कम होती जा रही है। दिल्ली में हवा रविवार की सुबह चार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन दिन में दस किलोमीटर की रफ्तार होने की वजह से वायु गुणवत्ता स्तर में सुधार हुआ। शाम को हवा की गति फिर छह किलोमीटर प्रतिघंटा हो गई। ज्ञात हो कि हवा की गति कम होने की वजह से प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक बने रहते हैं और उनका बिखराव धीमा हो जाता है। (जासं)

तिहाड़ में विचाराधीन कैदी ने की खुदकशी

नई दिल्ली : तिहाड़ जेल संख्या आठ में एक कैदी ने फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। घटना का पता रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे चला। मृतक की पहचान मुनाजिर (25) के रूप में हुई। जेल प्रशासन के अनुसार, मुनाजिर हत्या के मामले में बंद था। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल में रखवा दिया गया है। हरिनगर थाना में इस बाबत खुदकशी का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी हो रही है। जेल अधिकारियों का कहना है कि मुनाजिर 27 जुलाई से हत्या के एक मामले में जेल नंबर आठ के सेल में बंद था। सेल में बंद तीन अन्य कैदी भी मुनाजिर के इस कदम से हैरान हैं। पुलिस के अनुसार, फंदा कई कपड़ों से जोड़कर बनाया गया था। (जासं)

रोहिणी में 540 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत आज

नई दिल्ली : रोहिणी में 540 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली विभिन्न परियोजनाओं का केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र, खेल परिसर, उत्सव पंडाल शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अधिकारी के मुताबिक रोहिणी के सेक्टर-10 में 350 करोड़ रुपये की लागत से सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। इसके जरिये कला व कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा। आंतरिक व बाहरी मनोरंजक गतिविधियों के लिए उचित स्थान के अलावा इस केंद्र में सभागार भी बनेगा। इसका निर्माण कार्य 42 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सेक्टर 33 में 110 करोड़ रुपये की लागत से खेल परिसर बनाया जा रहा है। शादी समारोह के लिए सेक्टर-24 में उत्सव पंडाल बनाने पर 7.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे नौ माह में पूरा किया जाएगा। सेक्टर 24 और 25 में 70 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त ड्रेन बनाए जाएंगे। इसका काम 18 माह में पूरा हो जाएगा जिसके बाद सेक्टर 34, 35, 36 और 37 में बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। (राब्यू)

अनधिकृत कालोनियों में सक्रिय हुई भाजपा

चुनाव की तैयारी ▶ पीएम की 22 की रैली को सफल बनाने को चल रहा हस्ताक्षर अभियान

पुरी ने कहा, लोगों को आप सरकार के झूठे व खोखले वादों से छुटकारा चाहिए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होगी जिसे सफल बनाने के लिए भाजपा नेता हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही इन कॉलोनियों में जनसभाएं कर रहे हैं। लोगों से रैली में पहुंचकर इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को महरौली और मुंडका विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित हुईं।

महरौली में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री व दिल्ली चुनाव सह प्रभारी हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अब दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार के झूठे और खोखले वादों से छुटकारा चाहिए। सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में असफल रही है और मुख्यमंत्री फिर से नई-नई घोषणाओं के जरिये लोगों को भटकाने की कोशिशें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि वादों पर भरोसा करके जनता सत्ता दिलाती है और जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो वही जनता सत्ता से बाहर भी कर देती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होने वाला है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा गरीबों और जरूरतमंदों की पीड़ा को समझती है और उसे दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने और जहां झुग्गी वहीं मकान देने के वादे से भाजपा पीछे नहीं हटी। कांग्रेस और आप मोदी सरकार के फैसलों में अड़ंगा डालने के साथ ही जनता के सामने गलत तरीके से पेश कर रही हैं। मालिकाना हक देने सहित अन्य फैसलों में विरोधी पार्टियों ने अड़ंगा डाला, लेकिन जनता सरकार के साथ खड़ी है।

महरौली में आयोजित जनसभा में (दाएं से) भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सांसद रमेश बिधूड़ी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। सौ. भाजपा कार्यालय

झुग्गी बस्तियों में जनाधार बढ़ाने को उतरेंगे कार्यकर्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए झुग्गी झोपड़ी (जेजे) प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है। झुग्गी वालों को पक्का मकान देने सहित केंद्र सरकार के अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में जेजे प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के वोट से सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने इनके हित में कोई काम नहीं किया है। साढ़े चार वर्षों तक अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाते रहे। अब चुनाव नजदीक देखकर रोज नई-नई घोषणाएं कर रहे हैं। झुग्गी बस्ती में रहने वाले अब इनके झांसे में नहीं आएंगे।

दिल्ली की सत्ता में नहीं होने के बावजूद भाजपा यहां के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग सम्मान से अपने घर में जी सकेंगे। अब योजनाबद्ध तरीके से इन कॉलोनियों का विकास होगा।

शीला सरकार की उपलब्धियों पर फोकस करेगी कांग्रेस

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भले ही अब इस दुनिया में न हों, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें साथ रखने की योजना बनाई है। पार्टी अपने पूरे प्रचार अभियान में उनकी फोटो और दिल्ली के विकास में उनकी उपलब्धियों के साथ उन्हें तरजीह देगी। इसके लिए पूरी रणनीति बना ली गई है। प्रचार अभियान समिति भी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब एक माह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। शनिवार को रामलीला मैदान में हुई रैली की भीड़ देखकर तो पार्टी और भी उत्साहित है। पार्टी नेता अब इस माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए पार्टी ने प्रचार अभियान समिति को भी अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

जहां तक चुनाव प्रचार की रणनीति का सवाल है तो पार्टी 15 साल के शीला सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को ही केंद्र में रखेगी। विभिन्न क्रिएटिव के जरिये पार्टी देश की राजधानी की जनता को याद दिलाएगी कि शीला दीक्षित सरकार ने किस तरह से दिल्ली को संवारा था और इसका विकास किया था। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विकास के नाम पर दिल्लीवासियों को केवल धोखा दिया है, जबकि कांग्रेस ने हर क्षेत्र में दिल्ली का विकास किया था। साथ ही केजरीवाल सरकार के चुनावी वादों की हकीकत भी जनता के सामने लाई जाएगी।

गत सप्ताह प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भी शीला दीक्षित को याद किया था। इस ट्वीट में बताया गया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला ने बाकायदा अभियान चलाया- माई दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। इस अभियान में दिल्लीवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान दिया। केजरीवाल प्रदूषण के नाम पर कुछ भी ठोस करने की बजाये केवल पराली का राग अलापते रहते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। (फाइल)

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार हो गई है। मुख्य आधार शीला दीक्षित वर्सेज केजरीवाल सरकार का कार्यकाल ही रहेगा। अभियान के क्रिएटिव जल्द ही तैयार हो जाएंगे। कैंपेन कमेटी भी कुछ दिनों में सक्रिय हो जाएगी।
-कीर्ति आजाद, अध्यक्ष, कैंपेन कमेटी, दिल्ली कांग्रेस

विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय को पकड़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक को करीब एक करोड़ दो लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया है। वह शनिवार को एयर इंडिया की फ्लाइट से बैंकॉक जाने वाला था। उसकी पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है।

सीआइएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार की रात में करीब नौ बजे आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर एक यात्री को संदिग्ध हालत में देखा गया। उसके बैग की स्क्रीनिंग पर उसके अंदर विदेशी मुद्रा के कुछ बंडल देखे गए। उसे चेक-इन के लिए जाने दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ ही सीआइएसएफ ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। इमीग्रेशन पूरा करने और इसकी मंजूरी के बाद भी यात्री ने उच्च मात्रा में विदेशी मुद्रा ले जाने के संबंध में कस्टम की कोई घोषणा नहीं की और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा होल्ड एरिया में प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक की ओर रुख कर लिया। यहां उसे रोककर मामले की सूचना सीआइएसएफ के उच्च अधिकारी और कस्टम अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बैग की जांच की तो कपड़ों के पैकेटों में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा छिपाई गई थी। विदेशी मुद्रा गिनने पर 80,450 यूरो और 33,150 पाउंड मिले।

बच्चियों के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले बढ़े

लोकेश चौहान, नई दिल्ली

- **2018-19 में हुए दुष्कर्म के मामलों में से 63 फीसद मामलों में बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हुई हैं**
- **बच्चियों से दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले रोहिणी और उत्तरी पश्चिमी जिले में सामने आए**

राजधानी में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को कम करने और रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जाने के बाद महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाओं में तो कमी आई है, लेकिन बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 में दुष्कर्म के कुल मामलों में से 1,137 मामले पोक्सो एक्ट में दर्ज किए गए थे। 2018-19 में इनकी संख्या बढ़कर 1,237 हो गई। वर्ष 2018-19 में हुए दुष्कर्म के मामलों में से 63 फीसद मामलों में बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हुई हैं।

राजधानी में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले रोहिणी और उत्तरी पश्चिमी जिले में सामने आए हैं। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात है कि नई दिल्ली जिले में दुष्कर्म के 18 मामले दर्ज किए गए, ये सभी मामले बच्चियों के साथ हुए थे। प्रजा फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वे और दिल्ली पुलिस में लगाई गई आरटीआइ के जरिये ये आंकड़े मिले हैं। आरटीआइ से मिली सूचना के अनुसार, वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2018-19 में बच्चों और बड़ों के अपहरण के मामलों में कमी तो आई, लेकिन महिलाओं और बच्चियों के अपहरण के मामले बढ़े हैं। वर्ष 2018-19 में राजधानी में 5,555 मामले अपहरण के दर्ज किए गए। इनमें से 70 फीसद मामलों में बच्चियों का अपहरण किया गया। वहीं महिला व पुरुषों के अपहरण के 365 मामले सामने आए। इनमें से 75 फीसद मामलों में महिलाओं का अपहरण किया गया। बीते चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बच्चियों और महिलाओं के अपहरण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2015-16 में बच्चों के अपहरण में 56 फीसद मामले बच्चियों के साथ हुए थे, जबकि 2018-19 में यह आंकड़ा 70 फीसद पहुंच गया। वहीं वर्ष 2015-16 में हुए मामलों में 53 फीसद महिलाओं के अपहरण हुए थे, जबकि वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत तक पहुंच गया।

अभिभावक नहीं, दोस्त बनकर बच्चों को कराएं पढ़ाई : जावडेकर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि अभिभावक बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न डालें बल्कि उन्हें दोस्त बनकर पढ़ाएं। इससे वह ज्यादा अच्छा सीखेंगे और नाम रोशन करेंगे। वह अंबेडकर स्टेडियम में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित सहभागिता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में निगम ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बुलाया था। इसमें छात्रों को तनाव मुक्त पढ़ाई के साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूक किया गया।

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि निगम की इस पहल से शिक्षाविदों और अभिभावकों को एक मंच मिला है। इस अनोखे प्रयोग से अभिभावकों और शिक्षकों में संवाद बढ़ेगा, जिसका फायदा उनके बच्चों पर पड़ेगा। उन्होंने निगम के शिक्षकों को सुझाव दिया कि पीटीएम मीटिंग हो तो वह बच्चों की अच्छाई से भी अभिभावकों को अवगत कराएं, जिससे वह प्रोत्साहित होंगे। दक्षिणी निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों से मिले बहुमूल्य सुझाव शिक्षा पद्धति को अधिक बेहतर बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अभिभावकों का उत्साह और सहभागिता यह दर्शाता है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कितने सजग हैं। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी चिंता है।

शिक्षा समिति की अध्यक्ष नंदिनी शर्मा ने कहा कि अभिभावकों और शिक्षकों के बीच ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे निरंतर विचारों का आदान-प्रदान होता रहे। इससे अभिभावकों को भी बच्चों के विकास की सही जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में महापौर सुनीता कांगड़ा, स्थायी समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, नेता सदन कमलजीत सहरावत और शिक्षा निदेश आरती मौजूद रहीं।

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर। (फाइल)

प्राथमिक चिकित्सा का दिया गया प्रशिक्षण

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सहभागिता कार्यक्रम में शिक्षकों और अभिभावकों को प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसमें डॉ. केके अग्रवाल ने दुर्घटना की स्थिति में बेहोश व्यक्ति को ठीक करने के लिए सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटैशन) का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा आग लगने की स्थिति में दम घुटने से बचने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने जरूरी जानकारी दी।

भाजपा की टीम ने अनाज मंडी अग्निकांड स्थल का किया दौरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भाजपा द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रविवार को फिल्मिस्तान स्थित अनाज मंडी का दौरा किया। टीम ने जिस अवैध फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड में 43 मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके आसपास की अवैध फैक्ट्री में जाकर जमीनी हालत जानी। उस फैक्ट्री के आस-पास की सात इमारतों और 50 से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की।

यह टीम घटनास्थल की पड़ताल कर आग लगने के कारणों और इसमें विभिन्न विभागों की लापरवाही को इंगित कर अपनी रिपोर्ट जल्द ही दिल्ली भाजपा संगठन को सौंपेगी। वैसे, प्रारंभिक निरीक्षण में टीम ने लटकते बिजली के तारों और छोटे-छोटे कमरों में मजदूरों की अधिकता पर सवाल उठाए हैं। इसी तरह रिहायशी इलाके में चल रहीं अवैध फैक्ट्रियों को लेकर नगर निगम भी सवालों के घेरे में है। टीम के सदस्यों के मुताबिक यह निष्पक्ष जांच होगी और इसकी रिपोर्ट जल्द ही दिल्ली भाजपा आलाकमान को सौंपा जाएगा।

इस टीम का गठन दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया है। इस टीम में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मूलचंद गर्ग, पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा, पूर्व संयुक्त सचिव यशपाल चंद्र डांगे, पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भैरों सिंह गुर्जर और अधिवक्ता संकेत गुप्ता शामिल हैं।

एक और मजदूर ने दम तोड़ा

जासं, नई दिल्ली : फिल्मिस्तान की अनाज मंडी अग्निकांड मामले में झुलसे एक और मजदूर ने शनिवार देर रात लोकनायक अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वाले का नाम मोहम्मद मुकीम है। घटना वाले दिन 43 लोगों की मौत हुई थी। अब मरने वालों की संख्या 44 पहुंच गई है।

दिव्या दत्ता बोलीं, दिल्ली मुझे घर जैसी लगती है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जश्न-ए-रेख्ता के तीसरे दिन सुखान-जार हॉल में आयोजित 'कुछ दिल की कुछ दुनिया की' सत्र में अभिनेत्री व लेखिका दिव्या दत्ता ने कहा कि दिल्ली मुझे घर जैसी लगती है और रेख्ता में आना बहुत खास है। हाल में लैंगिक समानता पर मेरी कविता वाली एक वीडियो खूब वायरल हुई। लोगों को लगता है कि वह कविता मैंने ही लिखी है, लेकिन वह मेरे भाई राहुल की लिखी कविता है। उन्होंने कहा कि अब लैंगिक समानता पर बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए भाई ने इस पर एक कविता लिख दी। उन्होंने दर्शकों के लिए वह कविता पढ़ी 'तुमने कहा था हम एक ही हैं तो अपने बराबर कर दो न, नैपी जब मैं बदलती हूं तुम दूध की बोतल भर दो न, बस यूं ही एक हैं एक हैं करके कहां जिंदगी चलती है, कभी तुम भी सिर दबा दो मेरा, यही कमी एक खलती है।'

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित जश्न-ए-रेख्ता में दिव्या दत्ता ने अपनी पुस्तक 'मी एंड मां' पर बात करते हुए कहा, मैं लिखने के लिए अपनी मां से ही प्रेरित हुई। मां अक्सर लिखती थीं और उसी के जरिये अपने विचारों को प्रस्तुत करती थीं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात है खुद को अभिव्यक्त करना। अगर दोनों किरदार एक लेखक और एक अभिनेत्री के रूप में अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मेरा बचपन से सपना था यश चोपड़ा की फिल्म में काम करना। मुझे लीड रोल तो नहीं मिला, लेकिन 'वीर जारा' में जारा की सहेली के किरदार से खूब प्रशंसा मिली। मैं बचपन में अमिताभ के डांस की कॉपी करती थी। दिल्ली में राजेंद्र नगर के आर ब्लॉक में जब मैं रहती थी तब मैं मां के दुपट्टे व साड़ियां फाड़कर 'खइके पान बनारस वाला' गाने पर डांस करती थी। आस-पड़ोस के बच्चों को बुलाकर कहती थी कि आओ समोसे और गुलाब जामुन की पार्टी है और तुम मेरा डांस भी देख सकते हो। वे मेरे लिए तालियां बजाते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट बहुत अच्छी लगती थी।

दिव्या दत्ता ने कहा आज मैं एक बात का खुलासा करती हूं। लोगों को लगता है कि मैं दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टाइर्स एक पत्रिका है। उसमें 50 हजार बच्चों में से तीन लड़कियां चुनी गई थीं, जिनमें मैं और मेरे साथ सोनीली बिंद्रे थी। वहीं से मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद जिंदगी आवाज से अंदाज तक सत्र में बॉलीवुड अभिनेता व संगीतकार पीयूष मिश्रा ने अपनी कविता सुनाई। उन्होंने कहा 'वो काम भला क्या काम हुआ, जिस काम का बोझा सिर पे हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिस इश्क की चर्चा घर पे हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें अमरीका बाप बने, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो वियतनाम का शाप बने।' इसके बाद उन्होंने सुनाया, 'ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, जो हर घड़ी में, हर सदी में सौ बार होता है'। इन कविताओं को सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

रविवार को जश्न-ए रेख्ता में लेखक हीरेंद्र झा की पुस्तक 'एक ख्वाब' का विमोचन हुआ। इस मौके पर अजित अंजुम, संजीव पॉलीवाल, शैलेश सिंह, शायर इरशाद खान सिकंदर, शमीम अब्बास आदि मौजूद रहे। मॉय बुक्स प्रकाशन की ओर से प्रकाशित इस पुस्तक में करीब 70 कविताओं का संकलन है। इस मौके पर हीरेंद्र झा ने कहा कि ये सभी कविताएं सहज ही मेरे मन की अभिव्यक्ति हैं।

जश्न-ए-रेख्ता में अपने जीवन के किस्से साझा करतीं अभिनेत्री दिव्या दत्ता। जागरण

मुश्किल

स्मारक को जनता के लिए खोलने में जुटे एएसआइ के लिए खड़ी हुई मुसीबत, बाकी हिस्से को बचाने के लिए नई सिरे से बनेगी योजना

फिर ढही राष्ट्रीय स्मारक शेरशाह सूरी गेट की दीवार

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

देश को सबसे लंबी सड़क देने वाले शेरशाह सूरी के गेट स्मारक को जनता के लिए खोलने में जुटे एएसआइ के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस स्मारक के जिस गेट का संरक्षण कार्य चल रहा था, उसी गेट से कुछ दूरी पर स्मारक की दीवार का एक हिस्सा ढह गया है। अब इसे बचाने के लिए एएसआइ नए सिरे से सोच रहा है। एएसआइ के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि गेट का संरक्षण कार्य चल रहा है। इसी बीच दीवार गिर जाने से काम बढ़ गया है। दीवार का संरक्षण कराए जाने के लिए मुख्यालय से रुपये मांगे गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पैसा मिल जाएगा और संरक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।

जर्जर होने के कारण इस स्मारक पर सात साल से ताला लगा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) इस स्मारक का संरक्षण कार्य करा रहा था। एएसआइ की योजना थी कि इस कार्य के पूरा होने पर स्मारक को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस कार्य के पूरा होने में छह से सात माह लगने थे, लेकिन दीवार का संरक्षण कार्य शुरू होने से लेकर इसके पूरा होने में अब अधिक समय लग सकता है।

पुराना किला के ठीक सामने यह गेट लाल दरवाजा के नाम से भी मशहूर है। शेरशाह द्वारा निर्मित मथुरा रोड स्थित इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारक शेरशाह सूरी गेट का 2010 में बड़े स्तर पर संरक्षण कार्य कराया गया था। मगर 2012 में हुई तेज बारिश में इस ऐतिहासिक गेट का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे गेट खतरनाक स्थिति में आ गया था। उस समय एएसआइ ने आनन फानन में इस गेट के आधे हिस्से में ईंटों की दीवार खड़ी कर गेट को बचा लिया था। मगर इस गेट से ईंटों की दीवार को छह साल बाद भी एएसआइ नहीं हटा सका है। पांच साल बाद दिसंबर 2017 में इस गेट के संरक्षण का काम शुरू किया गया था। मगर कुछ माह बाद ही बंद हो गया। बंद होने का कारण था कि एएसआइ इस कार्य को अपने कर्मचारियों से करा रहा था। मगर एएसआइ द्वारा निकाले गए अस्थायी कर्मचारियों के कारण यह कार्य भी बंद हो गया। उसके बाद एएसआइ ने इस कार्य के लिए टेंडर निकाले थे। मगर कोई कंपनी काम लेने नहीं आई। अब दो माह से इस स्मारक में फिर से संरक्षण कार्य शुरू कराया गया है। गेट के नजदीक के ढहे हिस्से की दीवार का काफी काम कराया जा चुका है।

पुराना किला के पास शेरशाह सूरी गेट की एक तरफ की ढही दीवार (लाल घेरे में) संजय

एएसआइ के पूर्व निदेशक पदमश्री डा. केके मोहम्मद कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में एएसआइ में ट्रेंड बदला है। अब सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। मगर संरक्षण कार्य पर उतना ध्यान नहीं है, जो ठीक नहीं है। इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। संरक्षण कराने के लिए कम पैसा नहीं दिया जा रहा है।

दिल्ली के मशहूर 13 दरवाजों में से एक है यह दरवाजा : दिल्ली के मशहूर 13 दरवाजों में से एक इस गेट को शेरशाह सूरी ने वर्ष 1540 में बनवाया था। इसकी ऊंचाई 15.5 मीटर है।

आज से दिल्ली में शुरू होगी मुफ्त वाई-फाई की सुविधा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- **मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आइटीओ बस स्टैंड पर शुभारंभ करेंगे**
- **पहले फेज में राजधानी में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे**

राजधानी में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा का सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आइटीओ बस स्टैंड पर शुभारंभ करेंगे। शुरू में 100 हॉट स्पॉट की शुरुआत होगी। पहले फेज में दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। सोमवार को सराय काले खां बस स्टैंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी बस स्टैंड, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट आइएसबीटी, आइटीओ बस स्टैंड, मंडी हाउस बस स्टैंड, दिल्ली सचिवालय बस स्टैंड और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन समेत सात विधानसभा क्षेत्रों में 100 हॉट स्पॉट की शुरुआत होगी। इसमें आदर्श नगर, बादली, मालवीय नगर, मोती नगर, सीमापुरी व शाहदरा विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे।

एक महीने में 15 जीबी डाटा एक यूजर को मुफ्त मिलेगा। यूजर को एक दिन में डेढ़ जीबी डाटा तक उपयोग करने की छूट रहेगी। हॉट स्पाट 100 मीटर की रेडियस तक काम करेगा। इसकी स्पीड 100 से 200 एमबीपीएस तक होगी। सात हजार हॉट स्पॉट आरडब्ल्यूए के सुझाव पर पार्क, मार्केट सहित अन्य जगहों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा चार हजार हॉट स्पॉट बस स्पॉट पर लगाए जाएंगे। 100 हॉट स्पॉट शुरू होने के बाद प्रति सप्ताह 500 हॉट स्पॉट शुरू होते जाएंगे। छह माह में पूरे 11 हजार हॉट स्पॉट शुरू हो जाएंगे। इनके मेंटेनेंस का काम सरकार ही करेगी।

सरकार मुफ्त वाई-फाई के उपयोग के लिए एप शुरू करेगी। इस एप पर यूजर को केवाईसी भरना होगा। मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद यूजर इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। एक हॉट स्पॉट से दूसरे हॉट स्पॉट की रेडियस में जाने पर यूजर वाई फाई का निरंतर उपयोग कर सकेंगे।

565 राजघरानों के शासित प्रांतों को एक साथ लाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संयुक्त भारत के सपने को साकार किया था। देश के प्रथम गृह मंत्री पटेल ने 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में अंतिम सांस ली थी

कई जन्म लेने पर भी राहुल गांधी नहीं बन सकते सावरकर : संघ

नसीहत ▶ गांधी उपनाम रखकर महात्मा गांधी का अपमान न करें कांग्रेस के नेता

सावरकर के पोते ने की सरकार से आपराधिक मामला चलाने की मांग

इंद्रेश कुमार फाइल फोटो

नई दिल्ली, एएनआइ : सावरकर का नाम लेकर तंज कसने के मामले में भाजपा के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा कि कई जन्म लेने के बाद भी राहुल गांधी सावरकर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासक सावरकर से डरते थे। इसी वजह से उनको दो बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। राहुल सावरकर के व्यक्तित्व के नजदीक तक नहीं पहुंच सकते। भले ही उन्होंने अनादर या अपमान करने के लिए ही कहा है, लेकिन उनका कहना सही है कि वे सावरकर नहीं हैं।

कुमार ने आगे कहा कि राहुल के साथ गांधी उपनाम का जुड़ना गांधी शब्द का अपमान है। उन्हें गांधी उपनाम रखकर महात्मा गांधी का अनादर नहीं करना चाहिए। वे कभी गांधी या सावरकर नहीं हो सकते। उल्लेखनीय है कि शनिवार को कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। मेरा नाम राहुल गांधी है। भाजपा ने रेप इन इंडिया बयान के लिए राहुल से माफी मांगने को कहा था।

इस बीच सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने सरकार से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, यह देश तोड़ने का प्रयास करने जैसा है। यदि हम देश के प्रतीकों का आदर नहीं करेंगे, तो युवा पीढ़ी के पास कोई आदर्श नहीं रहेगा। जिस देश के पास कोई आदर्श नहीं रहता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं। हालांकि, यह उनके परिवार की परंपरा है। नेहरू ने भी शिवाजी महाराज को लुटेरा कहा था। इससे पूरे महाराष्ट्र में नाराजगी फैल गई। इसके बाद नेहरू को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। राहुल अपने पूर्वजों की गलतियां दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे राहुल की टिप्पणी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। रंजीत ने कहा कि कांग्रेस शिवसेना को अपमानित करने के लिए सावरकर का अनादर कर रही है। उन्होंने शिवसेना से कांग्रेस नेताओं को महाराष्ट्र सरकार से बर्खास्त करने की मांग भी की। सावरकर के समर्थकों ने सरकार से राहुल के राष्ट्रविरोधी बयान के लिए उनको जेल भेजने की मांग की है। एक समर्थक ने कहा कि हम वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। राहुल को इटली जाकर बस जाना चाहिए। इस समर्थक ने बताया कि राहुल जब बच्चे थे, तब अपने पिता राजीव गांधी के साथ अंडमान और निकोबार गए थे। उस समय राजीव गांधी ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी थी। इंदिरा गांधी ने भी उन पर डाक टिकट जारी किया था।

नागरिकता कानून का विरोध कर रही सरकारें करेंगी आंबेडकर का अनादर

नई दिल्ली, आइएएनएस : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के नेता इंद्रेश कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिन राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में कानून को लागू नहीं करने की धमकी दी है, वे आंबेडकर का अनादर करने का जोखिम उठाएंगी। कांग्रेस इस कानून का विरोध करके मुस्लिम विरोधी होने का संदेश दे रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर देश की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया।

शिवसेना नेता एकनाथ खडसे ने भी कांग्रेस नेता को दी नसीहत

मुंबई, एजेंसियां : शिवसेना के सांसद संजय राउत के बाद पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा, राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर का सम्मान करना चाहिए। सावरकर ने देश के लिए जो बलिदान दिया, उसके बारे में हर कोई जानता है। इस बीच, भाजपा ने भी कांग्रेस नेता पर हमला जारी रखा है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, वीर सावरकर का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को देश कभी माफ नहीं करेगा। राहुल और सावरकर में कोई तुलना नहीं है, जिनका उपनाम तक उधार का है। शाहनवाज ने कहा, शिवसेना को सत्ता और स्वतंत्रता सेनानी में किसी एक को चुन लेना चाहिए। सावरकर के अपमान पर सिर्फ एक ट्वीट कर देने से काम नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे को तय करना होगा कि क्या वे कांग्रेस के साथ सत्ता में साझीदार होंगे, जिसने स्वतंत्रता सेनानी का अनादर किया है? बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को फर्जी गांधी बताते हुए कहा, सावरकर जैसे देशभक्त के खिलाफ बोलना कांग्रेस की कुंठा को दिखाता है।'

नेहरू-गांधी परिवार पर विवादित टिप्पणी करने पर अभिनेत्री पायल रोहतगी हिरासत में

जागरण संवाददाता, जयपुर

पायल रोहतगी का फाइल फोटो। इंस्टाग्राम से

सोशल मीडिया में किया था पोस्ट, राजस्थान पुलिस ने अहमदाबाद में की कार्रवाई

नेहरू-गांधी परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी को राजस्थान पुलिस ने अहमदाबाद से हिरासत में लिया है। राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में उनके खिलाफ 10 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पायल ने छह और 21 सितंबर को एक वीडियो अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी किया था। इसमें नेहरू-गांधी परिवार को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं। मामले की जांच के बाद बूंदी सदर थाने के प्रबारी लोकेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में एक टीम शुक्रवार रात अहमदाबाद पहुंची और रविवार को उन्हें हिरासत में ले लिया। पायल ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने पीएमओ और गृह मंत्रालय को टैग करते हुए बताया कि, 'मुझे राजस्थान पुलिस ने मोतीलाल नेहरू पर वीडियो बनाने को लेकर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में जानकारी मैंने गूगल से ली थी।' उन्होंने यह भी लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मजाक है।

बूंदी एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि पायल का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज कराया गया था। नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद पुलिस टीम उनके मुंबई स्थित घर पहुंची थी। वहां से पायल के अहमदाबाद में होने की जानकारी मिली। हालांकि पुलिस अभी उन्हें हिरासत में लेने की बात कह रही है लेकिन स्वयं पायल गिरफ्तारी की बात कह रही हैं। पायल की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी भी लगाई गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए बनी थी आठ सदस्यीय उप समिति

प्रथम पृष्ठ से आगे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सकों की सुरक्षा से संबंधित विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय उप समिति का गठन किया था। इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा संगठन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुभवी व्यक्ति शामिल थे। सरकार की ओर से सितंबर में इस मुद्दे पर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं ली गई थीं।

कोलकाता में डॉक्टर पर हमले के बाद हुआ देशव्यापी आंदोलन : इसी साल जून में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकारी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने रेजिडेंट्स डॉक्टर पर प्राणघातक हमला कर दिया था। इसके विरोध में रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने देशव्यापी आंदोलन किया था। उसी समय स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग उठी थी।

प्रतीकात्मक फोटो

मोदी बोले, देश सरदार पटेल की विशिष्ट सेवाओं से प्रेरित है

- 69वीं पुण्यतिथि पर देश ने लौहपुरुष को दी श्रद्धांजलि
- शाह बोले, पटेल से प्रेरित होकर केंद्र ने भ्रष्टाचार व तुष्टिकरण खत्म किया

देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल। फाइल फोटो

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 69वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने ट्वीट किया कि महान सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। देश लौहपुरुष की विशिष्ट सेवाओं से प्रेरित हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर मोदी की पोस्ट को 5.4 हजार रीट्वीट और 32.5 हजार लाइक्स मिले। 1,467 ट्वीट् के साथ भारतीय राजनीति के लौह पुरुष हैशटैग आयरनमैन ने ट्रेंड किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के विभिन्न गणमान्य और जनसाधारण ने भारत के प्रथम गृह मंत्री को याद करते हुए ट्वीट किए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरदार पटेल अकेले ऐसे स्रोत हैं जिन्होंने हम सब को एक संयुक्त भारत के विचार के लिए प्रेरित किया है। वह सच्चे मायनों में भारत रत्न थे। उन्होंने नासिर्फ देश को आजादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया बल्कि आजादी मिलने के बाद भी देश को जोड़ने का काम किया। उन्होंने ट्वीट किया कि सरदार पटेल के आदर्शों और लौह नेतृत्व से प्रेरित होकर ही मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में देश से भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टिकरण का खात्मा किया है।

देश के प्रथम गृह मंत्री का निधन 15 दिसंबर, 1950 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने भारतीय गणराज्य की स्थापना में अहम योगदान निभाते हुए सभी 562 राजाओं की सत्ता को भारत में समाहित किया था। सत्तारूढ़ दल भाजपा का मानना है कि पटेल ने अगर जम्मू और कश्मीर के का जिम्मा अपने हाथ में लिया होता तो वहां के हालात बेहतर होते। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल गुजरात में सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची लौह प्रतिमा का अनावरण किया था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि देश के लौह पुरुष, भारत रत्न, सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन। उन्होंने भारत को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। उनके दर्शन, प्रतिबद्धता और जीवन से प्रेरणा ने हमें देश को सर्वोपरि रखते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया है।

एक अन्य यूजर ने लिखा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री को श्रद्धांजलि जिन्होंने 565 राजघरानों के शासित प्रांतों को एक साथ लाकर संयुक्त भारत के सपने को साकार किया। एक अन्य यूजर ने दिवंगत राजनेता के एक पुराने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि सन् 1948 में कलकत्ता मैदान में महान वक्ता सरदार पटेल का दुर्लभ भाषण। उनके पूरे भाषण में उनके प्रखर विचारों की स्पष्टता और दूरदर्शिता साफ झलकती है। एक अन्य ट्वीट में लिखा गया कि लौह पुरुष को सलाम। हम सब हमारे देश के लिए उनकी अनूठी सेवाओं को याद करते हैं। ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरित हों।

पास पर नहीं था फोटो तो लगा दी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में कानपुर जिला प्रशासन कठघरे में है। पुलिस जांच में पता चला है कि प्रशासन ने सारे पास राघवेंद्र सिंह को ही सौंप दिए थे और उन पर किसी का फोटो न होने का लाभ आरोपित ने उठाया। पुलिस ने देर रात उसे पकड़ा, लेकिन थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया। अब प्रशासन जांच की बात कहकर लीपापोती में जुट गया है।

चकेरी एयरपोर्ट पर पीएम को विदाई देने वाले 22 वीवीआइपी की सूची में नमामि गंगे प्रकल्प के कानपुर-बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवबोधन मिश्र का भी नाम था। वह नहीं आ सके और उनके नाम के पास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के गंगा विचार मंच के क्षेत्रीय संयोजक राघवेंद्र सिंह अपना फोटो लगाकर एयरपोर्ट पहुंच गया था। एसपीजी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह गायब हो गया। मामले में एआइजी एसपीजी कृष्णपाल यादव ने थाना चकेरी में राघवेंद्र के खिलाफ दूसरे के परिचय पत्र का प्रयोग कर एयरफोर्स क्षेत्र में घुसने की कोशिश के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देर रात पुलिस ने आरोपित राघवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि किसी भी पास में फोटो नहीं था तो शिवबोधन मिश्र के पास पर अपना फोटो चस्पा कर लिया और एयरपोर्ट पर पहुंच गया था।

लालू परिवार में सास-बहू का झगड़ा ढाई माह बाद फिर सड़क पर आ गया

- रोते हुए लालू के घर से निकलीं ऐश्वर्या, कहा- राबड़ी ने बाल पकड़कर पीटा
- लालू प्रसाद के बड़े बेटे की पत्नी का आरोप, सास ने सुरक्षा गार्ड से भी पिटवाया
- ऐश्वर्या के पिता ने कहा, लालू परिवार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे

पटना में रविवार को तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या फिर मीडिया के सामने रोती-बिलखती रहीं। उन्होंने आरोप लगाए कि राबड़ी ने उन्हें पीटा है। इस दौरान पिता चंद्रिका राय(दाएं)भी थे। जागरण

राज्य ब्यूरो, पटना

लालू परिवार में सास-बहू का झगड़ा ढाई महीने बाद रविवार को फिर सड़क पर आ गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर बाल खींचकर मारने-पीटने और घर से धक्का देकर निकालने का आरोप लगाया। मीडिया कैमरे के सामने रोती हुई ऐश्वर्या इतने गुस्से में थी कि वह अपनी सास को उनके नाम राबड़ी से संबोधित कर रही थी। खास बात यह है कि ऐश्वर्या ने अपने देवर को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मारपीट के दौरान तेजस्वी घर पर नहीं थे। ऐश्वर्या ने कहा, लालू परिवार में कोई कानून नहीं है। उनका अपना कानून है। तेजस्वी से भी कुछ नहीं होगा। अगर करना होता तो अब तक करते नहीं क्या? ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने कहा है कि सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब आरपार होगा। तेजस्वी ने पूरे मामले में नपुंसकता का परिचय दिया है। अब राबड़ी को जेल भिजवा कर रहूंगा। ऐश्वर्या की मां पूर्णिमा राय ने कहा कि पूरे परिवार की मानसिकता विकृत है।

पटना में राबड़ी आवास के बाहर करीब डेढ़ घंटे तक हुए हंगामा और फैमिली ड्रामा के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ऐश्वर्या ने अपने दादा और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बारे में कहा कि उन्होंने ही लालू यादव को आगे बढ़ाया। आज उनकी पोती के साथ ही लालू परिवार ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये लोग किसी के नहीं हैं। ऐश्वर्या ने पिछली बार मीसा भारती पर भी आरोप लगाया था।

पोस्टर के बाद विवाद : मामले की शुरुआत सुबह में पटना कॉलेज में लगे एक पोस्टर से हुई। ऐश्वर्या का आरोप है कि उसके पति तेजप्रताप ने यह पोस्टर लगवाया था, जिसमें चंद्रिका राय के परिवार का चरित्र हनन किया गया था। पोस्टर की जानकारी मिलने पर ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी से शिकायत की और पूछा कि आप लोगों ने मेरे माता-पिता को क्यों घसीटा? ऐश्वर्या के मुताबिक इसी बात पर राबड़ी ने उन्हें बाल खींचकर मारा। सुरक्षा गार्ड ने भी हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। मेरे गहने और मोबाइल भी छीन लिए।

बताया जान का खतरा : ऐश्वर्या ने कहा कि 17 दिसंबर को कोर्ट में तलाक मामले पर फैसले की उम्मीद है। उसके पहले राबड़ी चाहती हैं कि मैं घर छोड़ दूं। ऐश्वर्या ने जान पर खतरा बताते हुए कहा, जब घर में मारा-पीटा जा रहा है। बाहर हमें ये जीने नहीं देंगे। अब तो इंतिहा हो गई है। पिछली बार 29 सितंबर को मुझे केवल घर से बाहर निकाला था और खाना पीना बंद किया था। इस बार मारा-पीटा भी है।

तेजस्वी ने दिया राजनीतिक रंग: तेजस्वी यादव ने मामले को यह कहकर सियासी रंग देने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ही उनके परिवार में झगड़ा हो रहा है। नीतीश नहीं चाहते हैं कि लालू परिवार सुकून से रहे।

2018 में 12 मई को हुई थी शादी: लालू के बड़े पुत्र तेजप्रताप के साथ ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। उसी साल 2 नवंबर को तेज प्रताप ने अदालत में तलाक की अर्जी दी।

यह था पर्चे में : पटना कॉलेज के भाषा भवन पर 'सच्ची खबर' के नाम से चिपकाए गए पर्चे में तेजप्रताप का पक्ष लेते हुए उनके ससुर चंद्रिका राय, सास पूर्णिमा सिंह आदि पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। पर्चे में कहा गया है कि एक सीधे-सादे इंसान को सिर्फ सारण सीट के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। लालू की परंपरागत सीट शादी की शर्त के अनुसार चंद्रिका राय को दे दी गई। जिन लोगों ने यह बेमेल शादी कराई, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। राज परिवार का बड़ा बेटा भगवान राम की तरह वन-वन भटक रहा है।

भाजपा का गढ़ बन सकता है कर्नाटक

आशुतोष झा, नई दिल्ली

विश्लेषण

- जदएस के क्षेत्र में प्रभावी सेंध की संभावना दिखाता केआर पेट
- अब तक एक बार भी भाजपा को राज्य में नहीं मिला है अपने दम पर बहुमत

महाराष्ट्र और हरियाणा की घटना के बाद कर्नाटक में एक दर्जन विधायकों की जीत के साथ स्थायी सरकार सुनिश्चित तो हुई ही, इसने भविष्य के दरवाजे की चाबी भी दिखा दी है। दरअसल इसमें से एक सीट -केआर पेट की जीत ने यह संभावना जगा दी है कि भाजपा और कोशिश करे तो कर्नाटक इसके लिए गुजरात, मप्र, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य बन सकता है, जहां लगातार जीत का आधार बना था। भाजपा भविष्य की रोशनी के आलोक में बढ़ी तो अपने दोनों बड़े नेताओं की शिथिलता के कारण जदएस का प्रभाव कम होना तय है।

नौ दिसंबर को उपचुनाव के नतीजों में भाजपा कांग्रेस और जदएस के बागी नेताओं के जरिये 12 सीटें जीतने में सफल रही थी। तय माना जा रहा है कि इनमें से नौ-दस विधायक बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री भी बनेंगे। अगले डेढ़ दो हफ्ते में इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि इससे इन्कार किया जा रहा है कि इनमें से किसी को उपमुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। मंत्री बनने वालों में केआर पेट सीट से जीते जदएस के बागी भी शामिल होंगे। सूत्रों की मानी जाए तो ओल्ड मैसूर क्षेत्र के केआर पेट सीट का महत्व येदियुरप्पा की सरकार में काफी दिखेगा। एक तरफ जहां यह येदियुरप्पा का जन्मस्थान है, वहीं केआर पेट को भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दरअसल, जदएस के गढ़ रहे इस क्षेत्र को येदियुरप्पा के पुत्र विजयेंद्र ने जिस रणनीति के साथ फतह किया उसने यह रास्ता दिखा दिया है कि सब कुछ मुमकिन है। केआर पेट के सवा दो लाख वोटरों में वोकालिगा की संख्या करीब एक लाख है। वोकालिगा पर देवेगौड़ा परिवार का एकछत्र राज रहा है। यही कारण है कि ओल्ड मैसूर क्षेत्र की 89 विधानसभा सीटों से ही जदएस को सर्वाधिक सीटें मिलती रही हैं। भाजपा कभी भी 28 से ज्यादा नहीं जीत पाई है। वह भी तब जबकि बेंगलुरु से ही भाजपा को 17 सीटें मिली थीं। ध्यान रहे कि 224 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को 2008 के चुनाव मे 210 सीटें मिली थीं और 2018 में 104 सीटें। अगर जदएस के गढ़ में भाजपा कुछ सेंध लगाने में कामयाब हो जाए तो कर्नाटक में भाजपा का भविष्य स्थायी हो सकता है।

बताया जाता है कि केआर पेट को लेकर विजयेंद्र ने खास रणनीति बनाई थी। उस अकेले क्षेत्र के लिए अलग से मेनिफेस्टो भी जारी किया गया था और विकास की भूख जगाई थी। वह रणनीति काम आ गई। यानी विकास की ललक देवेगौड़ा की जातिगत पकड़ को भी कम कर सकती है। इसकी संभावना इसलिए ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि खुद देवेगौड़ा 86 के पार हो चुके हैं। जबकि उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बीमार हैं।

वैसे भी यह चर्चा आम है कि देवेगौड़ा से विपरीत उनके स्वभाव के कारण पार्टी के अंदर ही खिंचाव है। देवेगौड़ा के बड़े पुत्र एचडी रेवण्णा में कभी नेतृत्व की क्षमता नहीं दिखी। दूसरी ओर से फिलहाल कांग्रेस नेतृत्वविहीन है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की भी दखल है लेकिन सिद्दरमैया को पार्टी के अंदर से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे नेता डीके शिवकुमार का प्रभाव उनके गृह जिले तक सीमित माना जाता है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, केआर पेट की जीत से पार्टी उत्साहित है और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से मशविरा के बाद इस क्षेत्र में अभी से सक्रियता बढ़ाने की कोशिश होगी और केआर पेट का विकास दूसरे क्षेत्रों के लिए उदाहरण बनेगा।

अवैध कालोनी के मंजूर होने वाली फाइल निदेशालय से गायब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- लोकायुक्त के पास पहुंचा मामला, पूर्व प्रधान सचिव की देखरेख में हुआ फर्जीवाड़ा
- मौजूदा प्रधान सचिव ने लोकायुक्त से मांगा फाइल ढूंढने के लिए 15 दिन का समय

हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में एक अवैध कालोनी को मंजूर करने संबंधी फाइल शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय से गायब हो गई है। इस कालोनी में एक विधायक का आवास है। लोकायुक्त के पास शिकायत आने के बाद जब फाइल तलब की गई तो वह गायब मिली। लोकायुक्त की सख्ती के बाद फाइल ढूंढने के लिए शहरी निकाय विभाग के मौजूदा प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने 15 दिन की मोहलत मांगी है। यह फाइल निवर्तमान प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण के कार्यकाल की बताई जा रही है।

कालोनी की मंजूरी संबंधी फर्जीवाड़े में समालखा नगर पालिका के पांच अफसरों को पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है। इसी केस में तत्कालीन दो डीसी व मौजूदा डीसी से लोकायुक्त ने जवाब तलब कर रखा है।

लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल केस की सुनवाई आठ जनवरी को करेंगे। लोकायुक्त को एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने 19 अगस्त 2014 को शिकायत देकर कहा था कि समालखा की न्यू दुर्गा कालोनी में अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसे सरकार किसी दूसरी कालोनी के नाम से अप्रूव करने जा रही है। लोकायुक्त के निर्देश पर हुई दो अलग-अलग जांच में पाया गया कि शिकायत सही है, जिसके बाद शहरी निकाय विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने लोकायुक्त को सूचित किया कि नगरपालिका समालखा के दोषी पांच अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अब यह प्रधान सचिव बदल चुके हैं।

शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने लोकायुक्त को बताया कि 28 सितंबर 2018 को कालोनी को स्वीकृत करने की फाइल निदेशालय को मिली थी और उसी दिन कालोनी स्वीकृत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसके पश्चात से यह फाइल बार बार ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। निदेशालय के चीफ टाउन प्लानर को यह फाइल तत्काल ढूंढ कर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन में फाइल नहीं मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

पासवान बोले

केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा, अगड़ी जाति के नेताओं ने पिछड़ों और दलितों को आगे बढ़ाया, मोदी सरकार ने ऊंची जाति के गरीबों को सरकारी नौकरियों में दिया आरक्षण

सामाजिक न्याय की लड़ाई में हर वर्ग का रहा है साथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राम विलास पासवान का फाइल फोटो। प्रेट्र

दलितों-पिछड़ों के हितों की लड़ाई में जहां अक्सर केवल पिछड़े वर्ग के नेताओं का ही उल्लेख होता रहा है, केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान का मानना है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगड़े वर्ग के नेताओं की भूमिका शुरू से अहम रही है। पिछले दिनों लोकसभा और विधानसभाओं में एससी, एसटी के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने के संविधान संशोधन पर चर्चा में पासवान ने भगवान बुद्ध से लेकर विवेकानंद और वीपी सिंह तक का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का कभी विरोध नहीं हुआ है। जहां अगड़ी जाति के नेताओं ने पिछड़ों और दलितों को आगे बढ़ाया, वहीं अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससी, एसटी हितों का संरक्षण करते हुए ऊंची जाति के गरीब परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण दिया। सच्चे अर्थों में यही सामाजिक समरसता है।

संसद के शीतकालीन सत्र में जहां दोनों सदनों ने यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ, वहीं दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप भी कम नहीं हुए। लेकिन, पासवान ने कहा कि 1990 में मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय पासवान श्रम मंत्री थे और उससे पहले तक संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर की तस्वीर नहीं थी। पासवान ने कहा कि 1977 में जब मैं पहली बार जीतकर लोकसभा आया था, तो यह मुद्दा उठाया था। सरकार की ओर से कहा गया था कि सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है। यह जगह तब मिली जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी। इसी तरह पासवान ने यह भी याद दिलाया कि मोदी के शासन में अंबेडकर से जुड़े स्थानों को यादगार बना दिया। महू जहां उनका जन्म हुआ था, वहां शानदार स्मारक बना दिया। 26 अलीपुर रोड जहां वह रहते थे वहां म्यूजियम बना दिया। अमेरिका और ब्रिटेन में जहां रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी, वहां उस मकान को खरीदकर स्मारक बनाया। मोदी काल में अंबेडकर की यादों को संजोया गया है।

पासवान ने कहा कि चार क्रांतियां हैं। सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति। सामाजिक क्रांति को हमने हासिल कर ली है और अब तीन को हासिल करना बाकी है। इसमें हर किसी का योगदान चाहिए होगा।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
राजनीति विज्ञान (Optional)
सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा)
सामाजिक न्याय
नीतिशास्त्र (ETHICS)
OFFLINE / ONLINE CLASSES
9999421659-58

THE STUDY
विश्व इतिहास
से नया बैच प्रारंभ
-मणिकांत सिंह
OPEN LECTURE
19th DECEMBER
8:00 AM
210, VIRAT BHAWAN, NEAR POST OFFICE MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
9999516388, 9999278966, 42870015

लोकतंत्र की मशाल आज मेहनतकशों के हाथ

आरपीएन मिश्र, रांची

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

खनिज, उद्योग, पर्यटन और राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हैं चौथे चरण की 15 सीटें

विकास में जनभागीदारी का लक्ष्य लेकर निकली चुनावी मशाल झारखंड के 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए अब चौथे चरण के उन 15 इलाकों में जा पहुंची है जो खनिज, उद्योग और वन संपदा के बल पर राज्य की अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत की खूबियों से इसका गौरव भी बढ़ाते हैं। विकास की इस मशाल को राज्यभर की 81 विधानसभा सीटों की परिक्रमा करते हुए विधानसभा के द्वार तक पहुंचना है। फिलहाल मशाल थामे धनबाद, झरिया, सिंदरी, बाघमारा, टुंडी, निरसा, बोकारो, चंदनकियारी, गिरिडीह, जमुआ, गांडेय, डुमरी, बगोदर, देवघर और मधुपुर की जिम्मेदारी है कि वे मशाल की ज्योति को अपने बुलंद इरादों की अग्नि से इतनी प्रज्ज्वलित और प्रखर कर दें कि अगले चरण के चुनाव वाले इलाकों के लोग भी इसे संदेश, सबक और चुनौती के रूप में लें। अपने खनिजों और उद्योगों से राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हाथ में आज एक बार फिर मतदान के अमोघ अस्त्र से नया झारखंड गढ़कर अपने सपनों का राज्य बनाने का अवसर आया है। अच्छी बात ये है कि इन इलाकों के लोगों ने पिछले चुनावों में जागरूकता का परिचय देते हुए मतदान का आंकड़ा 65-70 फीसद तक और कहीं कहीं तो उसके भी पार पहुंचा दिया था।

अपने अथाह भंडार से रोज हजारों टन कोयला उगलने वाले धनबाद, झरिया, निरसा, टुंडी, बोकारो, गिरिडीह समेत इन तमाम इलाकों की इस समृद्ध पहचान के साथ झारखंड के अन्य हिस्सों की तरह गरीबी, बेकारी और बदहाली भी साथ-साथ चलती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, पत्थर और अन्य खनिज स्थानीय लोगों की समृद्धि का आधार नहीं बन सके हैं। दीपक तले अंधेरा वाली कहावत की तरह। फिर भी मेहनत और संघर्ष के बल पर मंजिल हासिल करने का जज्बा, सीमित आवश्यकताएं, कभी भी हार न मानने की जीवटता, गिर-गिर कर संभलने का जज्बा और विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त व ऊर्जावान बने रहने की खासियत यहां के लोगों को बाकियों से अलग करती है। जरूरत इस ताकत और क्षमता को सही दिशा देने की है। लोकतंत्र के महापर्व पर सोमवार को हमें अपनी इस ऊर्जा को मतदान की ताकत में बदलना है।

समृद्धि के द्वारों से लेकर आस्था और संस्कृति के सेतु तक : क्षमताओं की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में फैले कोयला उद्योग के अलावा स्टील सिटी के रूप में विख्यात बोकारो और खाद कारखाने के लिए मशहूर सिंदरी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक गौरव के चिह्नों की भी कमी नहीं। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर का वैद्यनाथ धाम जहां देश-दुनिया में भक्ति और अध्यात्म की धारा बहा रहा है, वहीं गिरिडीह में स्थित जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ से सत्य और अहिंसा का संदेश दुनियाभर में फैल रहा है। धनबाद, चंदनकियारी और निरसा के इलाके बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण अभी भी दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं।

झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए धनबाद में चुनाव सामग्री ले जाते मतदानकर्मी। प्रेट्र

221 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे 47.85 लाख मतदाता

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को चौथे चरण का मतदान होगा। इसमें कोयलांचल की 13 व संताल की दो सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्वच्छ व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण के चुनाव में दो मंत्री, सात पूर्व मंत्री तथा 14 वर्तमान विधायकों का भाग्य तय होगा। कुल 47,85,009 मतदाता 221 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। कुल प्रत्याशियों में 198 पुरुष तथा 22 महिला हैं। पहली बार एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 6,101 मतदान केंद्रों में 4,203 संवेदनशील तथा अति संवेदनशील हैं। 1,898 मतदान केंद्र ही सामान्य हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा में 50 सीटों पर चुनाव हो चुका है। चौथे चरण के तीन विधानसभा क्षेत्रों में 1,216 दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान अपने घर पर ही किया। बोकारो में 351, धनबाद में 767 तथा देवघर में 98 ने इस सुविधा का लाभ उठाया। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 1,367 ऐसे मतदाताओं ने इच्छा जाहिर कर फार्म भरे थे, जिनमें 30 को छोड़कर सभी के फार्म सही पाए गए। चुनाव आयोग द्वारा गठित टीम ने 1,216 मतदाताओं के घरों में जाकर मतदान कराया। इससे पहले उन्हें वीडियो दिखाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बाकी मतदाता अपने घरों में नहीं पाए गए। बता दें कि भारत में पहली बार झारखंड से यह व्यवस्था शुरू की गई है।

स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई में शामिल होगा नदी संरक्षण

फैसला ▶ कानपुर में हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में बनी सहमति

प्राथमिकता के आधार पर मानव संसाधन मंत्रालय और राज्य शैक्षिक संस्थानों में करेंगे लागू

बृजेश दुबे, कानपुर

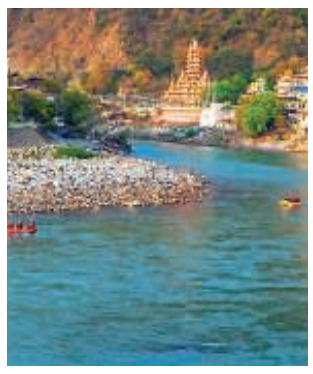

प्रतीकात्मक

सूचना, शिक्षा और संचार से करेंगे जागरूक

पाठ्यक्रम में नदी संरक्षण को शामिल करने के अलावा स्कूलों में इससे संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के आइईसी (इन्फार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन यानी सूचना, शिक्षा और संचार) मोड का सहारा लिया जाएगा। इसके तह सूचना इकट्ठा कर शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा पाने वाले लोगों में व्यावहारिक परिवर्तन के लिए उसका प्रचार करेंगे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होने पर छात्र नदी संरक्षण के बारे में लोगों को बेहतर तरीके से जागरूक कर पाएंगे।

स्कूल-कॉलेज में जल्द ही नदी संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य प्राथमिकता के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार कराकर इसे विश्वविद्यालय और स्कूलों में लागू कराएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल इस एजेंडे पर सहमति बन गई है।

नमामि गंगे से अर्थ गंगा की ओर बढ़ रहे गंगा सफाई अभियान में जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर है। शनिवार को कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तय समय से डेढ़ घंटे तक अधिक चली परिषद बैठक में यह दिखा भी। 14 प्रमुख एजेंडे में जन भागीदारी, आय, पर्यटन और शिक्षा भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बिंदु प्रमुखता से सामने आया कि अभियान से विद्यार्थियों को जोड़ने की बेहद जरूरत है, जो शिक्षा एवं शैक्षिक गतिविधियों से संभव है।

इसके पीछे की मंशा साफ है। चूंकि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों में नदियों के प्रदूषण को लेकर शोध होते रहते हैं, सो इस दिशा में तो काम हुआ लेकिन नदी व पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के विज्ञान और इंजीनियरिंग में ही बंधे होने के कारण आमजन का विषय नहीं बन पाए।

बैठक में जोर दिया गया कि नदी संरक्षण से आमजन को जोड़ना बहुत जरूरी है। इस पर स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक, नदी संरक्षण को पाठ्यक्रम के प्रमुख हिस्से के रूप में शामिल करने पर सब सहमत हुए। हालांकि राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यकारिणी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है और शनिवार की बैठक में उनका प्रतिनिधित्व नहीं था फिर भी माना जा रहा है कि गंगा केंद्रित सोच के साथ हुई परिषद की बैठक में हुआ निर्णय सभी लागू करेंगे। एक उच्चपदस्थ सूत्र के अनुसार, इस एजेंडे पर मानव संसाधन मंत्रालय से पहले ही चर्चा हो चुकी है, उनकी सैद्धांतिक सहमति भी है, इसलिए इस प्रस्ताव पर लागू करने के मोड में ही चर्चा हुई, जिसे सभी ने माना।

छात्रों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ेगा विवि अनुदान आयोग

नईदुनिया, भोपाल

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को अब सामाजिक सरोकार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाएगी। अब तक अभियान में सिर्फ तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अच्छा प्रतिसाद मिलने पर अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इससे जोड़ने की तैयारी है।

उन्नत भारत के तहत शुरू की गई इस योजना में यूजीसी ने सामाजिक सरोकारों को लेकर पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस पूरी कवायद के पीछे यूजीसी का मकसद है कि पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में न सिर्फ जानकारी मिल सके, बल्कि उसका समाधान भी किया जा सके। साथ ही केंद्र सरकार की नए भारत निर्माण की योजना को साकार किया जा सके। यही वजह है कि यूजीसी ने इस अभियान को पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित रखा है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फाइल

अपने संस्थानों से दो शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। इन सभी का प्रशिक्षण कुछ दिन में शुरू होगा, जो 30 जनवरी तक चलेगा। इसके साथ ही संस्थानों से इसे लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने आसपास के पांच गांवों को गोद लेना होगा। जहां वह छात्रों की मदद से उन्हें सरकार से जुड़ी योजनाओं और डिजिटल पेमेंट आदि की जानकारी देंगे। साथ ही उनके रहन-सहन और स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। फैकल्टी और छात्र महिलाओं और बच्चों को आ रही परेशानियों के बारे में भी जानेंगे। इस बारे में ये लोग अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय यूजीसी के जरिये केंद्र सरकार तक भेजेंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रो. डीपी सिंह का कहना है कि सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में दिखेगी 2022 की झलक

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- नए साल में राज्य में भाजपा को मिलेगा नया प्रधान
- जिला प्रधान चुनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा चुनाव

पंजाब में संगठन चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी में 2022 के विधानसभा चुनाव की कमान किसके हाथों में होगी, इसका पता नए साल में ही चल पाएगा। नए प्रदेश प्रधान के चयन के साथ ही भाजपा का अगले विधानसभा चुनाव को लेकर रुख स्पष्ट हो जाएगा। जिला प्रधानों के चुनाव की प्रक्रिया में देरी के कारण प्रदेश प्रधान के चुनाव में देरी हो गई है। पहले जिला प्रधानों के चुनाव की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी थी। अब यह 25 दिसंबर तक पूरी होगी। इसके बाद ही प्रदेश प्रधान का चुनाव होगा।

गठबंधन निभाना बड़ी चुनौती : भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि वह अकाली दल के साथ गठबंधन को भी निभाना चाहती है। साथ ही भाजपा में उठ रही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग को भी पूरा करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत और राज्य में अकाली दल के गिरते ग्राफ के बाद से ही भाजपा में यह मांग उठती रही है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में 23 से ज्यादा सीटें दी जाएं।

नए-पुराने चेहरों के बीच द्वंद्व : 2022 के लिए भाजपा में इन दिनों नए और पुराने चेहरों के बीच में द्वंद्व चल रहा है।

नए चेहरे : पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, पार्टी के महासचिव राकेश राठौर, प्रवीण बांसल, उप प्रधान जीवन गुप्ता, नरेंद्र परमार।

पुराने चेहरे : मौजूदा प्रदेश प्रधान श्वेत मलिक, मनोरंजन कालिया, अश्विनी शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ।

दोबारा दावा ठोक रहे मलिक : श्वेत मलिक दोबारा एक पारी खेलने के लिए दावा ठोंक रहे हैं, जबकि मनोरंजन कालिया और अश्विनी शर्मा पहले भी पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अकाली दल-भाजपा की सरकार में अनिल जोशी ऐसे मंत्री रहे, जिन्होंने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक अकाली दल के साथ दो-दो हाथ किए। सदन में 'मैं आतंकवादी हूं' कहने पर जोशी ने अकाली दल के विरसा सिंह वल्टोहा को आड़े हाथ लिया था। अपने छोटे भाई पर गोली चलने के बाद जोशी अकाली दल के खिलाफ डट कर खड़े हुए थे। तीक्ष्ण सूद सरकार और संगठन के कामकाज में संतुलन बनाने वाले नेता हैं। राकेश राठौर, जीवन गुप्ता, प्रवीण बांसल और तरुण चुघ को संगठन के कामकाज की अच्छी समझ है।

आगरा बैठक में कृष्णा सर्किट के विस्तार का बुना जाएगा ताना-बाना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मनोहर लाल फाइल

योगी आदित्यनाथ फाइल

हरियाणा व उत्तर प्रदेश सीमा पर जमीन और आगरा नहर के सिंचाई पानी संबंधी विवादित मुद्दों पर चर्चा के बाद अब इस माह के अंत में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आगरा में कृष्णा सर्किट के विस्तार का ताना-बाना बुनेंगे। इसके लिए शनिवार को लखनऊ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।

कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्किट विकास योजना के प्रथम चरण के तहत केंद्र सरकार से अब तक हरियाणा को 95 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। अब इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र को मथुरा-वृंदावन से जोड़ने की योजना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोनों राज्यों ने अनेक विवादित मुद्दे खत्म करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर जहां पहले ही लखवाड़, रेणूका और किशाऊ बांध परियोजना पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री समझौता कर चुके हैं। तीनों बांध परियोजनाओं से हरियाणा को सबसे ज्यादा 47.82 फीसद पानी मिलेगा। इसके अलावा दो फरवरी, 2018 को दोनों राज्यों के बीच सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार करने के लिए भी समझौता हो चुका है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन व्यवस्था की खामियां दूर करने के लिए 35 वर्ष बाद समझौता हुआ था। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश ने फरीदाबाद के सूरजकंड में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भी थीम स्टेट के रूप में भागीदारी की थी।

राज्य में पर्यटन विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में भी कृष्णा सर्किट के विकास में तेजी लाने सहित विस्तार की बाबत विषय शामिल किया था। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत और पानीपत जिलों के ऐतिहासिक स्थल इस कृष्णा सर्किट में शामिल होंगे। राज्य में सिंघु घाटी सभ्यता के अहम स्थलों को विकसित करने के लिए हड़प्पा सर्किट विकसित करने पर भी काम किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों पर पर्यटन से लेकर फार्म हाउस पयर्टन पर भी जोर दिया जाएगा।

मप्र में किसानों को अब एक लाख रुपये तक कर्जमाफी

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार जय किसान ऋण मुक्ति योजना के दूसरे चरण में 50 हजार से एक लाख रुपये तक किसानों की कर्जमाफी करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कमलनाथ 17 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने पर करेंगे। इससे लगभग पांच लाख किसान लाभान्वित होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, अब करीब 12 लाख किसान कर्जमाफी के लिए बचे हैं। इनमें पांच लाख किसान ऐसे हैं, जिन पर चालू खाते में 50 हजार से एक लाख रुपये का कर्ज है। झाबुआ और आलीराजपुर में यह दौर पूरा हो चुका है। बाकी जिलों में 17 दिसंबर से कर्जमाफी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिलेवार लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची बैंकों को दे दी गई है। जिलों से बैंकों को अब यह आदेश जारी होंगे। प्रदेश में अभी तक 20 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार कर्जमाफी दे चुकी है। इसमें दो लाख रुपये तक एनपीए लोन माफ करने के साथ चालू खाते पर 50 हजार रुपये तक कर्जमाफी दी गई है। इसमें किसानों को सात हजार 154 करोड़ से ज्यादा की कर्जमाफी मिली है।

उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए अलग से बजट की तैयारी

केदार दत्त, देहरादून

- बड़ा कदम-गांवों से पलायन थामने को चल रही कवायद के दौरान आया सुझाव
- बीते 19 वर्षों में 1702 गांव हो चुके हैं निर्जन

पलायन को गंभीरता से लिया गया है। पलायन रोकने को अलग से बजट की व्यवस्था के मद्देनजर ग्राम्य विकास विभाग इसका प्रस्ताव देगा। परीक्षण के बाद इस व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा।

-अमित नेगी, सचिव वित्त, उत्तराखंड

गांवों से निरंतर हो रहे पलायन को थामने की कवायद में जुटी उत्तराखंड सरकार अब एक अहम कदम उठाने जा रही है। पलायन रोकने के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर पर परीक्षण के बाद नए साल में ये व्यवस्था अमल में आएगी। इससे पलायन रोकने को चलने वाली तमाम योजनाओं के लिए विभागवार धन मुहैया कराया जाएगा, ताकि कार्य तेजी से हो सकें।

उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। खासकर, पर्वतीय क्षेत्र के गांव पलायन से निरंतर खाली हो रहे हैं। बीते 19 वर्षों में 1702 गांव निर्जन होना इसकी तस्दीक करता है। सैकड़ों गांवों में जनसंख्या अंगुलियों में गिनने लायक रह गई है। इसे देखते हुए पलायन आयोग ने अगले पांच साल गांवों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है। हालांकि, पलायन रोकने को सरकार कवायद में जुटी है। प्रभावित गांवों के लिए अब विभागवार कार्ययोजनाएं तैयार हो रही हैं। उच्च स्तर पर इसे लेकर मंथन का दौर जारी है। नीति आयोग ने भी पलायन रोकने के उपायों को लेकर विशेष रुचि ली है। इस बीच हाल में मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने पलायन रोकने को अलग से बजट की व्यवस्था का सुझाव रखा। बजट प्रविधान होने से पलायन रोकने को चलने वाली गतिविधियों को धन की दिक्कत नहीं रहेगी। उधर, इसे लेकर शासन स्तर पर गहनता से मंथन चल रहा है। उम्मीद है नए साल में ये व्यवस्था अमल में आ जाएगी।

झारखंड में राहुल गांधी की चुनावी सभाओं पर लग सकती है रोक

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभाओं पर रोक लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के गोड्डा और साहिबगंज की जनसभाओं में 12 दिसंबर को दिए गए वक्तव्य पर चुनाव आयोग ने ब्योरा तलब किया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने साहिबगंज और गोड्डा के उपायुक्त से राहुल गांधी के भाषण के अंश को लेकर रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव आयोग से राहुल के गोड्डा में दिए भाषण को आधार बना शिकायत की थी। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर राहुल गांधी की चुनावी सभाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया था कि 12 दिसंबर को गोड्डा की सभा में राहुल गांधी ने अपमानजनक और शर्मसार करने वाला बयान दिया था। कहा था कि आज भारत मेक इन इंडिया के बजाय रेप इन इंडिया बन गया है। राहुल के इस बयान को लेकर संसद में भी काफी हंगामा हुआ था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी झारखंड में अब तक पांच सभाएं कर चुके हैं।

तलाश जारी

ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई नाम चर्चा में, सभी गुटों की तरफ से अपने नेताओं के नाम किए जा रहे आगे

मप्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला नए साल में ही संभव

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब नए साल में ही नया अध्यक्ष मिल पाएगा। प्रदेश में सरकार बने एक साल हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोहरी जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए हाईकमान गंभीर है। नए अध्यक्ष को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कमलनाथ सरकार के सदस्यों सहित कुछ हारे हुए पूर्व मंत्रियों के नामों की चर्चा है।

विधानसभा चुनाव के छह महीने पहले कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ संगठन की जवाबदारी से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन विधानसभा में संतुलन बनाए रखने के लिए संगठन की कमान किसी और को सौंपकर नया शक्ति केंद्र बनाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा आलाकमान ने कमलनाथ को ही सत्ता के साथ-साथ संगठन की जवाबदारी सौंपे रखी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया फाइल

सरकार-संगठन में सामंजस्य की जद्दोजहद

सूत्रों के मुताबिक, अधिकांश नेताओं की यह कोशिश है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो सरकार के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करे। इससे जहां संगठन का काम सुगमता से चल सकेगा, वहीं सत्ता को भी मुश्किलें कम आएंगी। हालांकि, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सरकार के सही-गलत फैसलों पर सही राय रखने वाले व्यक्ति को नया प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, जिससे संगठन को मजबूती मिले और सरकार भी सही दिशा में चल सके।

विधानसभा में कमलनाथ सरकार के आरामदायक स्थिति में आने के बाद अब हाईकमान पर संगठन का नया मुखिया बनाने के लिए सभी गुटों का दबाव है। दिल्ली में भारत बचाओ रैली के बाद प्रदेश के अधिकांश नेताओं ने हाईकमान के सामने जल्द से जल्द नए अध्यक्ष पर फैसले की बात भी रखी है।

इन नामों की चर्चा : नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधायक कांतिलाल भूरिया व बिसाहूलाल सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, गृह मंत्री बाला बच्चन व वन मंत्री उमंग सिंघार के नाम शामिल हैं। सिंधिया के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा शुरू हो गई थी। चुनाव में हार के बाद भी उनके क्षेत्र व मालवा में सक्रियता के कारण प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम गाहे-बगाहे चर्चा में आता रहा है। उनके समर्थक मंत्री, विधायक, पदाधिकारी भी लगातार उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की मांग उठाते रहे हैं। हालांकि उनके खेमे से पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का नाम भी चर्चा में आया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खेमे की तरफ से विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले कांतिलाल भूरिया को एक बार और यह जिम्मेदार देने को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी की जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के विश्वस्त बाला बच्चन भी इस दौड़ में लगातार बने हुए हैं और उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री समर्थक करते रहे हैं। इधर, विधानसभा व लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए एक साल में अप्रत्यक्ष तौर पर कई बार शक्ति प्रदर्शन हो चुके हैं।

नीति और बुनियादी ढांचे की तैयारी में शीर्ष पर छत्तीसगढ़

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ नीति और बुनियादी ढांचा तैयार करने और मिशन मोड वाली परियोजनाओं के प्रदर्शन में देश में शीर्ष पर रहा है। गुरुग्राम की एक निजी सर्वे एजेंसी ने रविवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। भारत के डिजिटल राज्य रिपोर्ट 2019 नाम से जारी इस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश पांचवें स्थान पर है। वहीं, महाराष्ट्र दूसरे, हरियाणा तीसरे और आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है।

रिपोर्ट जारी करते हुए सर्वे एजेंसी कोएस एज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल देव सिंह ने कहा देशभर में डिजिटल इंडिया रफ्तार पकड़ रहा है। पहले यह केवल कुछ बड़े राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम के राज्यों तक सीमित था। अब इसमें उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हो रहे हैं।

हरियाणा की ऊंची छलांग

मध्य प्रदेश 2017 में इस सूची में शीर्ष पर था। इस साल के अध्ययन में वह फिसलकर पांचवें स्थान पर आ गया है। सबसे ऊंची छलांग हरियाण ने लगाई है जो 2017 में दसवें स्थान पर था और अब तीसरे स्थान पर आ गया है। जो अन्य राज्य और संघ शासित प्रदेश लंबी छलांग लगाने में सफल रहे हैं उनमें गोवा, बिहार, चंडीगढ़ और असम शामिल हैं।

यह रिपोर्ट राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दो व्यापक मानकों नीति और बुनियादी ढांचे की तैयारी (पीआइआर) व मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) के प्रदर्शन के आकलन के आधार पर तैयार की गई है। इस आकलन में पीआइआर और एमएमपी के 128 मानकों को शामिल किया गया है।

1951 में भारत की कुल आबादी में 84.10 फीसद हिंदू और 9.80 फीसद मुस्लिम थे, जबकि 2011 में देश में हिंदू आबादी 79.80 फीसद और मुस्लिम आबादी 14.20 फीसद हो गई।

असम गण परिषद का यूटर्न, सुप्रीम कोर्ट जाएगी

संजय मिश्र, गुवाहाटी

- नागरिकता कानून विरोधी असम आंदोलन में पार्टियों की बढ़ाई सियासी दिक्कत
- भाजपा कर रही हिमायत, लेकिन आंदोलन के तेवर से अभियान धीमा
- कांग्रेस कर रही मुखर विरोध, मगर आंदोलन में कूदने से कर रही परहेज

सुप्रीम कोर्ट फाइल

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ असम में जारी आंदोलन ने यहां के राजनीतिक दलों को बड़ी सियासी दुविधा में डाल दिया है। कानून का समर्थन कर रही सत्तारूढ़ भाजपा जनांदोलन के तेवर से रक्षात्मक हो रही है तो उसकी सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) ने यूटर्न लेते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। जबकि कांग्रेस नागरिकता कानून का विरोध के बावजूद सड़क पर उतरने से परहेज कर रही है।

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट डालने वाली एजीपी ने अपनी पार्टी में विद्रोह को देखते हुए रविवार को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का एलान किया। सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी पार्टी एजीपी के नेता कुमार दीपक दास ने बताया कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी जिसमें नागरिकता संशोधन कानून को रद करने की अपील की जाएगी। राज्यसभा के पूर्व सांसद दास ने कहा, 'हम संशोधित कानून लाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे क्योंकि असम के स्थानीय लोग आशंकित हैं कि उनकी पहचान, भाषा खतरे में आ सकती है।' सूत्रों ने बताया कि दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करने के लिए रविवार की शाम दिल्ली रवाना हो गया। इस मामले पर सुनवाई 18 दिसंबर को हो सकती है। वहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआइयूडीएफ ने भी कानून के विरोध का मोर्चा खोल दिया है, लेकिन मैदान में उतरने से बच रही है। केवल वामपंथी दलों का मोर्चा ही सीधे आंदोलन में उतर कर विरोध प्रदर्शन में साथ दे रहा है।

कांग्रेस आंदोलन में कूदने से इसलिए भी बच रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह यहां हुए हिंसक आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। असम विधानसभा में नेता विपक्ष देवब्रत सैकिया ने 'दैनिक जागरण' से बातचीत में कहा कि गृहमंत्री के आरोप गलत है क्योंकि जनता खुद सड़क पर उतर गई है। कांग्रेस 2016 से ही नागरिकता संशोधन बिल (कैब) का विरोध कर रही थी और अब भी हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हर आंदोलन को राजनीति की नजर से नहीं देखना चाहिए। वैसे स्थानीय विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कांग्रेस आंदोलन में इसलिए नहीं उतर रही है कि पूर्व में बांग्लादेशियों के साथ बरती गई उसकी नरमी को लोग भूले नहीं हैं। जबकि कानून के खिलाफ असम में विरोध की सबसे बड़ी चुनौती से सत्तारूढ़ भाजपा रूबरू हो रही है। मगर असम की भाजपा सरकार बेशक नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में तर्क देते हुए इसके खिलाफ आंदोलन को दुष्प्रचार बता रही है, मगर लोगों की उत्तेजना के चलते भाजपा नेता लोगों के बीच अपना रुख बताने से परहेज कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में शनिवार देर रात भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक में इस दुष्प्रचार के खिलाफ रविवार से अभियान चलाने का फैसला हुआ। लेकिन रविवार को मुख्यमंत्री के अखबार में प्रकाशित संदेश के अलावा भाजपा की जमीनी सक्रियता गुवाहाटी या असम के दूसरे हिस्से में नहीं दिखी। स्थानीय भाजपा नेताओं ने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि अधिक सक्रियता दिखाना ठीक नहीं। आंदोलनकारियों के दबाव के चलते भाजपा के कई जिलों के स्थानीय नेताओं को इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया है। इसीलिए भाजपा ने रणनीतिक संयम की नीति अपनाई है। केवल मुख्यमंत्री सोनोवाल, वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ही बयान देने के लिए अधिकृत हैं।

असम में हिंसा थमी, मगर जोर पकड़ रहा आंदोलन

गुवाहाटी में रविवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनस्थल पर म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इसमें यह बालिका हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में नजर आई। एएफपी

संजय मिश्र, गुवाहाटी

- केंद्र व राज्य के आश्वासन पर भरोसा करने को राजी नहीं स्थानीय लोग

असम में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा का दौर लगभग थम गया है मगर शांतिपूर्ण आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस कानून से असम के लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं होने के केंद्र व राज्य सरकार के आश्वासन पर यहां के लोग भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। गुवाहाटी में एक बड़े म्यूजिकल कार्यक्रम के जरिए विरोध प्रदर्शन से सूबे के बौद्धिक व कला जगत के लोगों ने भावी आंदोलन की तस्वीर भी पेश कर दी है। सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि रविवार को गुवाहाटी में कर्फ्यू के दौरान कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। राज्य के दूसरे हिस्सों से भी स्थिति सामान्य होने की खबर है। एहतियातन शाम से कर्फ्यू लागू है।

पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती से भी गुवाहाटी में आंदोलन के हिंसात्मक होने का भय कम हुआ है। शायद यही वजह रही कि रविवार को गुवाहाटी में असम इंजीनियरिंग कालेज ग्राउंड पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अभी तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटी। साहित्य, कला व बौद्धिक जगत के यहां के चर्चित लोगों ने इस विरोध आंदोलन में शामिल हुए और नागरिकता संशोधन कानून को रद करने की मांग उठाई गई। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान सुबह 11 से शाम पांच बजे तक गीत-संगीत के जरिए असम व भारत की संस्कृति का गुणगान करते हुए नए नागरिकता कानून को यहां के लोगों के साथ किया गया एक बड़ा विश्वासघात करार दिया गया। बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग व मान रोबिन जैसे स्थानीय चर्चित कलाकारों ने अपने गीतों से लोगों को परिवार सहित इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ आती-जाती रही मगर मैदान कभी खाली नहीं रहा। विरोध आंदोलन में जुटी भीड़ के स्वरूप पर निगाह रख रही केंद्र व राज्यों की एजेंसियों के लिए आम लोगों की बड़ी हिस्सेदारी चिंता का कारण हो सकती है क्योंकि इसमें जुटी भीड़ में मध्यम वर्ग व छात्रों की संख्या काफी ज्यादा थी। खास बात यह थी कि लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते देखे गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान एक ही नारा लगाया 'कैब आमी नै मानो'' (कैब हम नहीं मानेंगे)।

गुवाहाटी के राजनीतिक विश्लेषक सुशांत तालुकदार ने कहा कि कैब आंदोलन को हिंदू बनाम मुस्लिम जोड़ कर देखने वाले गलत कर रहे हैं। असम के स्थानीय हिंदू या मुसलमान दोनों बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों या मुस्लिम घुसपैठियों को नागरिकता देने के विरोध में हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा हमला मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर किया जा रहा है। मंच से हेमंत को असमिया समुदाय से बाहर तक करने की मांग की गई। जबकि सोनोवाल के असम की भाषा व संस्कृति को कोई खतरा नहीं होने के वादे पर यह कहा गया कि अगर बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या ज्यादा नहीं है तो मुख्यमंत्री उन्हें ट्रेन में बिठा कर गुजरात क्यों नहीं भेज देते। मुख्यमंत्री ने जनता के नाम जारी संदेश में कहा कि दिसंबर, 2014 के बाद बांग्लादेश से आने वाले किसी हिंदू शरणार्थी को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि असम में एक या डेढ़ करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं के होने को दुष्प्रचार करार दिया है। मगर मुख्यमंत्री का यह संदेश विरोध प्रदर्शन की आंच कम करने में सहायक नहीं साबित हो रहा।आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सूबे के कई स्थानीय सामाजिक व राजनीतिक संगठन एक समन्वय समिति के जरिए संगठित तौर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई के संगठन कृषक मुक्ति संग्राम संगठन, वामपंथी दलों का मोर्चा, उल्फा के अनूप चेतिया का ग्रुप व पूर्वोत्तर के सभी छात्र संगठनों ने रविवार को गुवाहाटी प्रेस क्लब में इस उद्देश्य से बैठक भी की। अनूप चेतिया ने दैनिक जागरण से कहा कि आंदोलन का अभी कोई नेतृत्व नहीं है मगर आम जनता के दिल में जो गुस्सा है उसे देखते हुए यह हम सभी का दायित्व है कि इस आंदोलन को किसी मुकाम पर पहुंचाया जाए। शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद सोमवार को पूरे प्रदेश में सत्याग्रह के अंदाज में तीन दिनों तक विरोध प्रदर्शन चलेगा।

जामिया में उपद्रव के बाद छात्रों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

बढ़ा विवाद ▶ सैकड़ों की संख्या में जमा छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जामिया की घटना को लेकर आइटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करते छात्र व मौजूद पुलिसकर्मी। जागरण

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिंसक उपद्रव के बाद रविवार रात नौ बजे सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं आइटीओ स्थित पुराना दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में जामिया के अलावा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय व एनएसयूआइ के छात्र-छात्राओं के आलावा कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी थे।

जामिया में हिंसक प्रदर्शन व आगजनी की घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने जब प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े व हल्का लाठी चार्ज किया तब उसके विरोध में शाम के वक्त सोशल मीडिया पर एलान किया गया कि सभी छात्र-छात्राएं रात 8.30 बजे तक पुराना पुलिस मुख्यालय के बाहर पहुंचें। उसी के बाद दिल्ली के तीनों विश्वविद्यालयों से छात्र-छात्राएं मेट्रो व बसों से आइटीओ पहुंचे लगे। मुख्यालय के बाहर पहुंचने के दौरान वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती ज्यादा नहीं थी। आनन-फानन में आला अधिकारियों को सूचना मिलने पर मध्य व उत्तरी जिले से पुलिसकर्मियों का मुख्यालय पर पहुंचना शुरू हो गया। पुलिसकर्मियों ने मुख्यालय के सारे दरवाजे बंद कर बाहर बैरीकेडिंग कर दी। पहले 100 की संख्या में ही छात्र-छात्राएं पहुंचे, बाद में 11 बजे तक करीब एक हजार की संख्या में छात्र-छात्राएं पहुंच गए। मेट्रो से लगातार छात्र-छात्राओं को आते देख आइटीओ मेट्रो के सभी दरवाजे बंद करा दिए गए। बाद में डीटीसी की कलस्टर बसों में भरकर छात्र-छात्राएं आइटीओ पहुंचे। शुरू में यातायात चालू रखा गया। जब अधिक भीड़ जमा हो गई तब चौरोहे से विकास मार्ग वाली सड़क पर यातायात रोक दी गई। मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किए जाने के कारण बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। वाटर केनन, फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस मंगवा लिए गए। खबर लिखे जाने तक प्रदर्शनकारी मुख्यालय के बाहर डटे थे।

लोजपा ने कहा, शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर समझने की जरूरत

राज्य ब्यूरो, पटना : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नेशनल सिटीजन रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर चल रही किस्म-किस्म की बयानबाजी के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को पटना में कहा कि बहुत कुछ भ्रम की वजह से भी परेशानी है। शरणार्थी और घुसपैठिए के अंतर को समझने की जरूरत है। यह धारणा गलत है कि मुसलमानों को देश से बाहर करने की कोशिश हो रही है। उन्हें कोई भी सरकार देश से नहीं निकाल सकती। संसद के दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार चिराग ने मीडिया से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा चीजों को समझने के बाद लोग सहज हो जाएंगे। एनआरसी के मसले पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि अभी वह इस मसले पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। जब तक इसका वह पूरी तरह अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ कह नहीं सकते।

नुकसान का आकलन कर रहा डीटीसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : जामिया एवं आसपास के इलाके में रविवार को हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने कई बसों के रूट डायवर्ट कर दिए, ताकि बसों एवं यात्रियों को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में डीटीसी की कुछ बसों को जला दिया गया। डीटीसी के प्रवक्ता डॉ. आरएस मिन्हास ने बताया कि क्षतिग्रस्त हुई बसों की संख्या के बारे सही-सही जानकारी नहीं है, लेकिन डीटीसी की कुछ बसों में आग लगने की सूचना जरूर मिली है। नुकसान की आकलन किया जा रहा है।

छात्रों ने नहीं स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन : जेएमआइ

जासं, नई दिल्ली : जामिया इलाके में हुए बवाल और आगजनी की घटना के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआइ) ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। जेएमआइ द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि परिसर के आसपास के क्षेत्र में रविवार की हुई हिंसक घटना में जेएमआइ के छात्र शामिल नहीं थे। आसपास के इलाकों के लोगों द्वारा विरोध-प्रदर्शन किया गया था, जिसमें यह हिंसा हुई। छात्रों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। कुलपति नजमा अख्तर ने बताया कि विश्वविद्यालय ने पहले ही 13 दिसंबर की घटना के बाद शीतकालीन अवकाश और सेमेस्टर परीक्षा स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में से बड़ी संख्या में छात्र पहले ही जा चुके हैं। उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जेएमआइ के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस ने बल पूर्वक प्रवेश किया है। पुलिस को प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। हमारे कर्मचारियों और छात्रों को पीटा जा रहा है और परिसर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

जामिया की आग से गर्म हुई सियासत

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में राजधानी के जामिया इलाके में हुई हिंसा से दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ गया है। एक तरफ राजधानी के एक हिस्से में अफरातफरी का माहौल था और हिंसक भीड़ तोड़फोड़ कर रही थी, वहीं दूसरी ओर भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता हिंसा के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में व्यस्त थे। कोई ट्वीट कर रहा था तो कोई वीडियो संदेश जारी कर जामिया की आग पर अपनी सियासत को धार देने में जुटा हुआ था। जिस तरह से इसे लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है, इससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गर्म होने की आशंका जताई जा रही है।

अमानतुल्लाह पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप : इस कानून के विरोध में कुछ दिनों से जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को यह आंदोलन और उग्र हो गया। इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया है। आप विधायक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और हिंसा वाली जगह से वह काफी दूर थे।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सियासत और तेज होने के पूरे आसार हैं। भाजपा इस कानून को अपने पक्ष में भुनाना चाहती है, वहीं आप और कांग्रेस इसका विरोध कर रही हैं।

> मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर आप का विधायक जनता को भड़का रहा है। भारत का मुसलमान देश के साथ है, वह किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। आप का असली चेहरा सामने आ रहा है।
> **-मनोज तिवारी (दिल्ली भाजपा अध्यक्ष)**

> दिल्ली में भाजपा आग लगवा रही है। यह आग पुलिस के संरक्षण में लगवाई जा रही है। आम आदमी पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। हिंसा करना भाजपा की संस्कृति है।
> **-मनीष सिसोदिया (उपमुख्यमंत्री, दिल्ली)**

> हम केंद्र सरकार के इस हिटलरशाही फरमान (सीएए 2019) का विरोध करते हैं। हिंसा की मैं निंदा करता हू। दिल्ली की जनता शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें।
> **-सुभाष चोपड़ा (दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष)**

भाजपा सरकार ने दिल्ली को भी जलने के लिए छोड़ा : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस ने रविवार को उस पर देश में शांति बनाए रखने के अपने कर्तव्य को निभाने में नाकाम रहने और असम, त्रिपुरा तथा मेघालय के बाद दिल्ली तक को जलने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने जामिया के छात्रों पर 'बर्बर कार्रवाई' की निंदा करते हुए 'संयम' बरतने की अपील की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कहा, 'पूर्वोत्तर से लेकर असम, बंगाल और अब दिल्ली में। भाजपा सरकार देश में शांति बनाए रखने का अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही। उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमारे देश में शांति बहाल करनी चाहिए।' कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह पूछा कि क्या पुलिस का जामिया परिसर पुस्तकालय में घुसना और छात्रों की पिटाई करना तथा उन पर आंसू गैस छोड़ना न्यायोचित है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली जल रही है, असम, त्रिपुरा और मेघालय जल रहे हैं। बंगाल में हिंसा फैल रही है, गृह मंत्री को पूर्वोत्तर जाने की हिम्मत नहीं है, जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा रद करनी पड़ी, लेकिन मोदी जी झारखंड में चुनाव प्रचार करके खुश हैं।'

एएमयू में बवाल के बाद देवबंद में सतर्कता बढ़ाई गई, इंटरनेट बंद

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

एएमयू में हुए पथराव के बाद फैले पत्थर। जागरण

नागरिकता संशोधन बिल के विरोध को लेकर सहारनपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। एएमयू में हुए बवाल के बाद देवबंद समेत पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गत दिवस देवबंद के मदरसा छात्रों द्वारा स्टेट हाईवे को जाम कर हंगामा करने के बाद से ही एसएसपी का पूरा फोकस देवबंद पर है। रविवार को देवबंद में एक कंपनी पीएसी तैनात कर दी गई है। साथ ही एसपी देहात, सीओ व थानों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। डीएम आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार, सोशल मीडिया के दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर यह आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को स्कूल, कॉलेज यथावत खुले रहेंगे।

सड़कों पर उतरे भाजयुमो कार्यकर्ता : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के हिंदुत्व के विरोध में बोलने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों में रविवार को उबाल आ गया। वे सड़कों पर उतर आए। एएमयू छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन को चेताया कि आग उगलने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम एएमयू की ओर कूच कर देंगे।

नागरिकता कानून सावरकर के विचारों के खिलाफ : उद्धव

नागपुर, एजेंसियां : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए इसे सावरकर के विचारों के खिलाफ बताया है। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीत सत्र की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सावरकर ने सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश बनाने की मांग की थी। इसके लिए काम करने के बजाय केंद्र की भाजपा सरकार सावरकर की उपेक्षा करते हुए सिर्फ पड़ोसी देशों के सताए गए शरणार्थियों को अपना रही है। यह उनका अपमान है। उद्धव ने कहा कि महिला सुरक्षा में कमी, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नागरिकता कानून का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या नागरिकता संशोधन कानून किसी विचारधारा पर आधारित है? इसको लेकर जो हिंसा भड़की है, उसका क्या? उन्होंने कहा कि सावरकर को लेकर शिवसेना के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। हम नए कानून की वैधता की जांच कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

यहां खुशी

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मतुआ संप्रदाय में जश्न, वर्षों से था मलाल, अब है नागरिकता प्रमाण मिलने का इंतजार

बंगाल की ठाकुरबाड़ी में गूंज रहा 'हर-हर मोदी'

मिलन कुमार शुक्ला, कोलकाता

रातों रात बदल गई ठाकुरबाड़ी की तस्वीर

2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएए के बाद ठाकुरबाड़ी की तस्वीर रातों रात बदल गई है। सीएम ममता बनर्जी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है। जाहिर तौर पर यह भाजपा के लिए सुकून देने वाला है। यहां बता दें कि मतदान को लेकर एक मत रहने वाला संप्रदाय 101 वर्ष की उम्र में मतुआ महासंघ की प्रधान वीणापाणि देवी (बड़ो मां) के निधन के बाद बंट गया था। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल के बीच इनके मतों को झटकने की पुरजोर अजमाइश दिखी और इसका लाभ भाजपा को मिला और ठाकुरबाड़ी के शांतनु ठाकुर को जीत मिली थी।

क्यों खास है मतुआ संप्रदाय

यद्यपि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन मतुआ संप्रदाय को लगभग 70 लाख की जनसंख्या के साथ बंगाल का दूसरा सबसे प्रभावशाली अनुसूचित जनजाति समुदाय माना जाता है। उत्तर व दक्षिण 24 परगना तथा नदिया जिलों की कम से कम छह संसदीय सीटों पर यह निर्णायक स्थिति में हैं। अनुमान के मुताबिक विभिन्न जिलों में इनकी आबादी लगभग एक करोड़ है, जो बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से कम से कम 74 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को हालात से अवगत कराया

बंगाल प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी को राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। प्रदेश भाजपा के महासचिव विश्वप्रिय रायचौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प. बर्धमान जिले के अंडाल हवाई अड्डे पर मोदी से मुलाकात की। रविवार को पीएम मोदी झारखंड के दुमका जाने के क्रम में यहां थोड़ी देर के लिए उतरे थे।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर बंगाल के कई जिलों में बवाल मचा है। सियासत हावी है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कानून का विरोध कर रही है, लेकिन कोलकाता से तकरीबन 76 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश की सीमा से लगे बनगांव स्थित ठाकुरनगर की ठाकुरबाड़ी के मतुआपाड़ा (मतुआ बहुल इलाका) में तस्वीर बदली नजर आ रही है, माहौल जश्न का है और हरि नाम संकीर्तन के साथ हर-हर मोदी गूंज रहा है। संप्रदाय के मतदाताओं ने 1971 से बंगाल में कांग्रेस, वाममोर्चा और तृणमूल के सियासी किस्मत को तय करने में अहम भूमिका अदा की है। सरकारें बदली, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब बना लेकिन दिल में 'इंडिया', जुबां पर 'जन, गण, मन...' के बावजूद संप्रदाय की पहचान बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी से नहीं बदली। संप्रदाय के लोगों को इसका मलाल वर्षों से था जो अब सीएए के बाद पूरा होगा।

...जो सुकून दे कि 'वतन है हिंदुस्तां हमारा' : मतुआ संप्रदाय के लोगों को अब भी भरोसा नहीं, इनको तो बस वह कागज चाहिए जो दिल को सुकून दे कि वतन है हिंदुस्तां हमारा। ठाकुरबाड़ी के पास खड़े तापस विश्वास ने कहा, एक कागज चाहिए, जिसे दिखाने के बाद कोई गर्दन पकड़ कर देश से बाहर न खदेड़ दे। सीएए पर सवाल के जवाब में एक बुजुर्ग ने कहा, पहले कांग्रेस करता था, फिर माकपा की और तृणमूल का समर्थन किया, वर्षों से सभी कहते आ रहे हैं, अब कानून बना है, सुना तो है पर जब तक कागज हाथ नहीं आ जाता भरोसा नहीं होता।

बर्दाश्त नहीं हिंसा, सख्ती से निपटे प्रशासन : ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लोगों से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील के बावजूद रविवार को लगातार तीसरे दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से उग्र विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। विभिन्न जिलों में कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं, रेल पटरियों व सड़कों पर आगजनी की गई। स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार देर शाम अपने आवास पर आला अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक बुलाई, जिसमें स्पष्ट कहा कि हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को इससे सख्ती से निपटना होगा। बताया गया कि बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों की आड़ में कुछ लोग राज्य को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएए लागू नहीं करने का सरकारी विज्ञापन असंवैधानिक : धनखड़

जागरण संवाददाता, कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर बंगाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएए और एनआरसी पर सरकार की ओर से जारी विज्ञापन को असंवैधानिक करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से परेशान लोगों की मदद करने का भी अनुरोध किया है। रविवार को राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरी राज्य के लोगों से अपील है कि वे शांति बनाए रखने के लिए और परेशानी में फंसे लोगों की मदद करने के लिए सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री कम से कम विज्ञापन हटाएंगी क्योंकि वे असंवैधानिक हैं और यह पब्लिक फंड का आपराधिक इस्तेमाल है। गौरतलब है कि बंगाल समेत कई राज्यों की सरकारों ने अपने यहां नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करने का एलान किया है।

100 गांवों की तस्वीर संवारी जाएगी उत्तराखंड में नए साल में। नीति आयोग ने इस ओर ध्यान दिया है। पलायन की वजह से इन गांवों की आबादी 50 फीसद से कम हो गई है। प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या 534 है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आइडी स्वामी का निधन

फरीदाबाद : भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ईश्वर दयाल स्वामी का रविवार को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गत 9 दिसंबर को ही उनकी पत्नी पद्मा स्वामी का निधन हुआ था। स्वामी हृदय के साथ-साथ किडनी रोग से पीड़ित थे। शनिवार शाम उनको यहां मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. एसएस बंसल के अनुसार रविवार दोपहर बाद तीन बजे उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त आइडी स्वामी 1999 में दिग्गज कांग्रेस नेता चौ. भजनलाल को करनाल से लोकसभा चुनाव में हराकर देशभर में चर्चा में आ गए। वह 1996 में भी करनाल से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1999 में वाजपेयी सरकार में वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। (जासं)

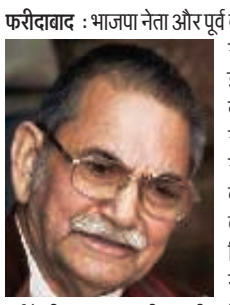

पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आइडी स्वामी। फाइल

ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा को मिला प्रथम पुरस्कार

नई दिल्ली : वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से ऊर्जा संरक्षण के लिए हरियाणा को प्रथम पुस्कार दिया गया है। शनिवार को विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह से यह पुरस्कार हरियाणा नवीन अक्षय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक डॉ. हनीफ कुरैशी ने ग्रहण किया। डॉ. कुरैशी ने बताया कि देश भर में ऊर्जा बचत में हरियाणा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। (राब्यू)

पाकिस्तान से भेजी 2.4 किलो हेरोइन पकड़ी

फिरोजपुर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास चौकी बस्ती राम लाल क्षेत्र में बीएसएफ ने कंटीली तार के नजदीक प्लास्टिक की बोतलों में दो किलो चार सौ ग्राम हेरोइन बरामद की है। जांच की जा रही है कि हेरोइन की खेप किस तस्कर को भेजी गई थी। (जासं)

प्रकाश सिंह बादल के छाती में तकलीफ, कराई स्वास्थ्य जांच

बठिंडा : पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल सीने में तकलीफ के कारण रविवार दोपहर को स्थानीय हार्ट अस्पताल में जांच करवाने पहुंचे। ठंड की वजह से उनके सीने में तकलीफ बताई गई है। इन्फेक्शन के कारण खांसी भी आ रही है। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. स्वर्णजीत सिंह भुल्लर ने सीटी स्कैन, पीएफटी, ईको आदि कराया। उन्होंने इसे रूटीन चेकअप बताया। (जासं)

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 371 लागू नहीं करेगा केंद्र

राज्य ब्यूरो, जम्मू: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 371 लागू करने की संभावना से इन्कार किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 371 लागू करने की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन हैं। यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार कुछ पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी डोमीसाइल अधिकार दे सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म कर दिया था और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तब्दील कर दिया था।

इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाने की चर्चा हो रही थी। यहां के युवाओं और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने बेरोजगारी की बढ़ती दर को देखते हुए नौकरियों में प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर के युवाओं को ही देने की मांग की थी। यही नहीं, यहां पर जमीनों की खरीदारी के अधिकार भी स्थानीय लोगों के पास रखने की मांग हो रही है।

संवाद की सार्थकता में खिलखिलाई संवादी की सफलता

दुर्गा शर्मा, लखनऊ

'ये जो घटने लगा है समाज में संवाद
इसीलिए बेवजह बढ़ने लगे हैं विवाद।'

थोड़ी बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है, फिर किस बात की लड़ाई है? हर विषय पर एक सी राय जरूरी नहीं, असहमति के स्वर भी आने चाहिए। चुप्पी का प्रतिकार कर हर मुद्दे पर बात जरूरी है। बस इतना ख्याल रहे कि संवाद वहीं तक अच्छा जहां वो विवाद न बने। तीन दिन तक जागरण संवादी का सतरंगी मंच विचारों का रण बना रहा। मुद्दे उछले, वक्ता-श्रोता उलझे, विचार उमड़े और आखिरकार सार्थक संवाद की जीत हुई। इसी जीत में संवादी की सफलता भी खिलखिलाई।

जागरण संवादी के रूप में अभिव्यक्ति का जो बीज छह साल पहले रोपा गया था, अब वह विचार, विमर्श, तर्क-वितर्क, हां, ना की उर्वरा धरती पर फलने फूलने लगा है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां हम विदा तो हो रहे हैं लेकिन अगले साल फिर मिलने के वादे के साथ। विदाई कोई भी हो, भावुक कर जाती है। जाने वाले की खलने वाली कमी सोचकर आंखों में नमी आ जाती है। मुंबई से आए दोस्त को विदा करने के बाद अगला दिन संवादी को विराम देने का था। हर विदाई की बेला को साहित्य, शिक्षा, सिनेमा, समाज और संगीत की मौजूदगी ने यादगार बना दिया। 'संघर्ष' से शुरू हुआ संवादी का अंतिम दिन हास्य और गीत की बौछार का अद्भुत अनुभव दे गया।

संवादी के तीसरे और अंतिम दिन की शुरुआत स्त्री साहित्य के संघर्ष के साथ हुई। संघर्ष से शुरू हुई बात ने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर भी समझाया। सृजन ने समानता की भी चाह की। बात निकलकर आई कि स्त्री होना भी एक संघर्ष है। लिखना बड़ा कर्म है। साहित्य में स्त्री और पुरुष को अलग करके देखना और आंकना ठीक नहीं। सम्यक दृष्टि की जरूरत है। अगला सत्र लखनऊ विश्वविद्यालय पर केंद्रित रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय आज उम्र के शतक की दहलीज पर है। यह वो पड़ाव है, जहां निश्चित तौर पर इसका आकलन होगा। आकलन हुआ भी, पर तमाम गौरव को समेटे इमारत की मौजूदा तस्वीर धूमिल निकली। कलम की जगह परिसर में खाकी और खादी के बढ़ते प्रभाव ने शिक्षा व्यवस्था और नीति निर्धारकों को कठघरे में खड़ा किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय से बात निकलकर हिंदी पर बेस्टसेलर के प्रभाव पर आकर टिकी। युवा कलम ने इसके लाभ गिनाए तो दर्शकदीर्घा से आवाज उठी कि साहित्य फास्ट फूड नहीं हो सकता। अगला सत्र यथार्थ और कल्पना को समझने का था और चर्चा साहित्यिक सत्संग बन गई। पांचवें सत्र में इतिहास लेखन की चुनौतियां सामने थीं। कहा गया कि इसके लिए कल्पना नहीं यथार्थ चाहिए। फिर साहित्य और सिनेमा पर विमर्श में संवाद ही प्रमुख रहा। गहन और गंभीर चिंतन से भरा दिन हास्य और गीत के साथ खुशनुमा मोड़ पर छोड़ गया।

फिर मिलेंगे

- भारतेंदु नाट्य अकादमी में तीन दिन तक चले जागरण संवादी ने ली विदाई
- उलझते मुद्दों में सामंजस्य स्थापित कर वार्तालाप का संदेश
- 'संघर्ष' से शुरू हुआ संवादी हास्य और गीत की बौछार का अनुभव दे गया

फिर मिलेंगे सतरंगी संवादी... लखनऊ में रविवार को गोमती नगर स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी में दैनिक जागरण संवादी के आखिरी दिन का समापन सत्र हास्य और गीत से सराबोर रहा। लोगों को गुदगुदाने के लिए कानपुर से हास्य अभिनेता अन्नू अवस्थी पहुंचे। उनके साथ मंच पर बैठे (बाएं से) कवि सर्वेश अस्थाना, गायिका मालविका हरिओम और दूरदर्शन लखनऊ के प्रोग्राम अधिशाषी आत्मप्रकाश मिश्र। रंगनाथ तिवारी

जम्मू-कश्मीर में नजरबंद नेता जल्द रिहा किए जाएंगे : राम माधव

दी जानकारी ▶ कहा, कश्मीर में लोग महसूस कर रहे कि अनु. 370 विकास में बाधा था

विकास शर्मा, चंडीगढ़

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि श्रीनगर में अनुच्छेद 370 पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। इसलिए इस पर शोर मचाने के बजाय इंतजार करना चाहिए। हालात सामान्य होते ही नजरबंद किए गए नेताओं को मुक्त कर दिया जाएगा।

राम माधव रविवार को यहां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के तहत 'आर्टिकल 370 एंड डेथ-नेल ऑफ टेरिज्म' विषय पर आयोजित पैनल में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग तेजी से होते विकास को देख रहे हैं और वह महसूस कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 विकास में बाधक था।

यह तूफान से पहले की शांति: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार आतंकवाद को अनुच्छेद 370 से जोड़कर लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अनु. 370 की वजह से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान समर्थित है। उन्होंने कहा, यह तूफान से पहले की शांति है। ईश्वर जाने आगे क्या होगा।

बातचीत का रास्ता अपनाए सरकार : पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुल्लत ने कहा कि दुनियाभर के इतिहास पर नजर डालें तो एक ही बात देखने को मिलेगी कि युद्ध और गोली से किसी विवाद का हल नहीं हुआ है। हल हमेशा बातचीत से हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह हर उस शख्स से बात करे जिससे जम्मू-कश्मीर में हालत सामान्य करने में मददगार हो।

लातों के भूत बातों से नहीं मानते: दुल्लत की बात का जवाब देते हुए राम माधव ने कहा कि हम अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहा जा सकता है कि लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। ऐसे लोगों से निपटने में सरकार सक्षम है। सरकार किसी भी हालत में गलत बात का समर्थन नहीं करेगी।

कारगिल के बच्चों का जवानों के लिए संदेश: मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित प्रदर्शनी में कारगिल के काकसर स्कूल और बारामुला के बलकोट व नामला गांव के स्कूली बच्चों की ड्राइंग व संदेश पत्र लगाए हैं। बच्चों ने बताया कि कैसे वह मुश्किल हालातों में पढ़ाई कर रहे हैं। काकसर वह गांव है जहां से साल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने महावीर चक्र विजेता सौरभ कालिया को बंधक बनाया था। पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण सिर्फ इसी स्कूल के 18 बच्चे शहीद हो चुके हैं। उन्हें भरोसा है कि भारतीय सेना हर गोली को अपने सीने पर खाएगी। वह पढ़-लिखकर देश की सेवा करेंगे।

मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी दिन आर्टिकल 370 एंड डेथ-नेल ऑफ टेरिज्म विषय पर आयोजित पैनल में हिस्सा लेते (बाएं से दाएं) सीनियर पत्रकार मनोहर जोशी, पूर्व रॉ चीफ एएस दुल्लत, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और सांसद मनीष तिवारी। हरप्रवेश सिंह

'नजरबंद नेताओं को रिहा कर लोगों से सीधी बात करें मोदी'

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया व राजनीतिक गतिविधियां बहाल करने के लिए नेशनल कांफ्रेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजरबंद नेताओं को छोड़कर सीधी बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की आवाज उठाई है। नेकां ने पार्टी के प्रधान फारूक अब्दुल्ला पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की अवधि तीन महीने बढ़ाने का विरोध किया है। कहा है कि उन जैसे कद्दावर नेता पर रोक लगाना किसी पार्टी की विचारधारा पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। यह मुद्दा रविवार को शेर-कश्मीर भवन में जम्मू में नेकां के कार्यवाहक प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने संवाददाता सम्मेलन में उठाया। राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों के लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों से सीधे बातचीत कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया व राजनीतिक हालात की बेहतरी सुनिश्चत करें।

यूं ही नहीं उठी राम से जुड़े देशों के संगठन की बात

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

अवध मिथिला सम्मेलन में सामने आया सुझाव

क्या भगवान राम से जुड़े देशों का अलग संगठन बन सकता है...। यह नई बहस अवध-मिथिला सम्मेलन से निकली है। इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। करीब 25 से अधिक ऐसे देश हैं, जहां अलग-अलग विधाओं में रामलीला का मंचन होता है, जबकि 60 से ज्यादा देशों में रामकथा की व्याप्ति है। अवध-मिथिला सम्मेलन के पहले दिन अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉ. वाईपी सिंह ने इस विषय को यह कहकर रखा था कि कॉमनवेल्थ की तरह भगवान राम से जुड़े देशों का संगठन बन सकता है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने यह कहकर आगे बढ़ाया कि राम के नाम पर पूरी दुनिया एक हो सकती है।

अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों को मानने वाले राम को अलग-अलग रूपों में पूजते हैं। रूस, इंडोनेशिया, फिजी, सूरीनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, थाइलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कैरेबियन देशों में रामलीला का मंचन परंपरा के अनुरूप होता है। सम्मेलन के दूसरे दिन अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉ. सिंह ने यह तथ्य भी साझा किया कि श्रीलंका के 250 गांवों में तमिल रामलीला का मंचन होता है तो दूसरी ओर नेपाल के रामजानकी मंदिर में 70 साल से अधिक समय से नियमित रामधुन बजाई जा रही है। रामनगरी में हुए दीपोत्सव के तीन संस्करणों से भी भगवान राम की वैश्विक व्याप्ति सिद्ध हुई है। इसी साल दीपोत्सव पर मॉरीशस, थाइलैंड, सूरीनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और नेपाल की रामलीला मंडलियों का आगमन हुआ था, तो गत वर्ष हुए दीपोत्सव में इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाइलैंड, रूस, श्रीलंका एवं श्रीलंका के कलाकारों ने प्रस्तुति से समां बांधा था।

अयोध्या शोध संस्थान ने 2018 में राम की विश्व यात्रा व 2017 में राम की वैश्विक यात्रा नाम से दो पुस्तकों का भी प्रकाशन किया, जिसमें यह तथ्य साझा किया गया कि भगवान राम अलग-अलग देशों में किन-किन रूपों में मौजूद हैं। अयोध्या शोध संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी रामतीर्थ कहते हैं, राम से जुड़े देशों का संगठन बना तो यह शोध की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी होगा।

अयोध्या में राम की प्रतिमा स्थल को लेकर मंथन

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या : अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के स्थल को लेकर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए अब प्रशासन मीरापुर दोआबा की दक्षिण-पश्चिम दिशा से लगी माझा बरहठा और माझा जमथरा में जमीन तलाश रहा है। अब चूंकि अयोध्या को इक्ष्वाकुपुरी की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव भी जुड़ गया है, इस लिहाज से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए माझा बरहठा की दावेदारी प्रबल होती दिख रही है। भगवान राम की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा के बाद से ही रामनगरी में उसके निर्माण का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद थी कि छह नवंबर 2018 को रामकथा पार्क में दूसरे दीपोत्सव का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री प्रतिमा स्थल का शिलान्यास कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन सरयू पर बने फोरलेन सड़क पुल एवं रेल पुल के बीच की भूमि को देख रखा था। दीपोत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री खुद मीरापुर दोआबा मौजा की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं जल्दबाजी साबित हुई। 13 महीने बाद भी प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पाया। जमीन खरीद के अंतिम दौर में भूमि चयन के लिए गठित टेक्निकल लीगल सेल ने ऐन मौके पर अपनी रिपोर्ट में उसे अनुपयुक्त करार दे दिया है। अब प्रतिमा स्थापना के लिए 61.38 हेक्टेयर भूमि की दरकार है और इतनी भूमि का प्रबंध प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि, मीरापुर दोआबा में असफलता के बाद प्रशासन ने दो अन्य स्थानों पर भी जमीन देखी है। इसमें दोआबा के ही दक्षिण-पश्चिम दिशा से लगा माझा बरहठा और दूसरा माझा जमथरा शामिल हैं।

मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से पहले बनेगा ट्रस्ट : विहिप

जासं, जालंधर : विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से पहले ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने को कहा है, लेकिन विहिप की कोशिश है कि ट्रस्ट शीघ्र बने जिससे मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। पत्रकारों से बातचीत में आलोक कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। सरकार के संरक्षण के बिना रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को आग लगाना संभव नहीं है। कानून में मुस्लिम समुदाय को बाहर रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यत: धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख व ईसाई वर्ग ही है। पंजाब में नागरिकता संशोधन कानून लागू न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए कोर्ट व केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी होगी।

2023 तक देश से रेल मार्ग के जरिये जुड़ जाएगा कश्मीर

कटड़ा-बनिहाल रेल प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, जम्मू

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2023 तक रेल मार्ग से पूरा देश, कश्मीर से जुड़ जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जम्मू-बारामूला को तीन वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गोयल ने निर्माणाधीन कटड़ा-बनिहाल खंड के निर्माण में तेजी लाने को कहा। रविवार को जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर आए रेलमंत्री गोयल सुबह करीब 10 बजे विशेष हेलीकॉप्टर से अर्धकुंवारी पहुंचे। वहां से बैटरी कार से भवन पहुंचे और भवन में मां वैष्णो देवी की पिंडियों के दर्शन कर करीब डेढ़ बजे वापस कटड़ा पहुंचे। जम्मू में आकर उन्होंने प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जम्मू बारामूला रेल परियोजना का कटड़ा-बनिहाल खंड देश के इंजीनियरिंग इतिहास में बेशक सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन देश के इंजीनियरों में इतनी क्षमता है कि वे इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कर देशवासियों को सौंपेंगे। कटड़ा बनिहाल खंड में दुनिया का सबसे लंबा रेल पुल है। रेल अधिकारियों ने उन्हें भूमि अधिग्रहण समेत संबंधित जिला प्रशासन के साथ पेश आ रही दिक्कतों को उजागर किया। रेलमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को रेल अधिकारियों से बैठक कर उन्हें रेल खंड के निर्माण में आ रही दिक्कतें दूर करने के लिए कहा।

111 किलोमीटर लंबा है कटड़ा-बनिहाल रेल सेक्शन : कटड़ा-बनिहाल प्रोजेक्ट देश के रेल के इतिहास में सबसे अहम व जटिल परियोजना मानी जा रही है। जम्मू-ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक का 326 किलोमीटर का दो-तिहाई हिस्सा तैयार हो चुका है। जम्मू संभाग के कटड़ा से कश्मीर के बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के रूट के निर्माण की जरूरत है। इस लाइन पर कुल 27 पुल, 37 सुरंगें हैं। जिन पर तेजी से काम चल रहा है। इसी लाइन पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। 12 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग भी इसी रूट पर है।

पहाड़ों में बर्फबारी से खिलीं पर्यटकों की बांछें

जागरण संवाददाता, जम्मू

उत्तर भारत के उच्चवर्ती इलाकों में हुई बर्फबारी से पर्यटकों की बांछें खिल गई हैं। कश्मीर में शीशे के बंद केबिन से बर्फ से ढके गगनचुंबी चीड़ और देवदार के पेड़ और चारों ओर बर्फ से ढंकी चोटियों के नजारे किसी के लिए भी यादगार हो सकते हैं। करीब दस मिनट का यह सफर कर जब हिमालय की शिवालिक चोटियों में समुद्र तल से 6640 फुट की ऊंचाई पर खत्म होता है, तो सामने आते हैं बर्फ से ढके पटनीटॉप के दिलकश नजारे, जो स्विटजरलैंड की सैर से कम नहीं लगते। जम्मू संभाग में पिछले दो दिनों में हुई बर्फबारी के बाद इन्हीं नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों ने पटनीटॉप की ओर रुख कर लिया है।

बर्फबारी से मुनस्यारी में जगी स्कीइंग की उम्मीद : उत्तराखंड में हुई ताजा बर्फबारी से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में स्कीइंग की उम्मीद जगने लगी है। मुनस्यारी के पास साढ़े दस हजार फीट की ऊंचाई पर खलिया टॉप और बिटलीधार नामक ढलानों पर तीन से चार फीट बर्फ है। इससे स्कीइंग की आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) उत्साहित है। प्रदेश में औली के बाद मुनस्यारी ही स्कीइंग के लिए उपयुक्त है। औली में स्कीइंग के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मुनस्यारी में इनका अभाव है। बावजूद इसके विगत 28 वर्षों से स्कीइंग का आयोजन किया जा रहा है। केएमवीएन के प्रबंधक (साहसिक पर्यटन) दिनेश गुरुरानी ने बताया कि केएमवीएन वर्ष 1991 से यहां पर स्कीइंग का आयोजन कर रहा है। यदि मौसम ने साथ दिया तो अगले सप्ताह से स्कीइंग कराई जाएगी।

क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए पैक हुए हिमाचल के होटल : क्रिसमस व न्यू ईयर का जश्न मनाली में बिना बुकिंग मनाना आपकी खुशियों में खलल डाल सकता है। पर्यटन नगरी के इन दोनों दिन के लिए होटलों में धड़ाधड़ ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। अब तक पर्यटन नगरी के 65 फीसद होटल पैक हो चुके हैं। अब धीरे-धीरे पर्यटकों ने मनाली का रुख करना भी शुरू कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कड़ाके की ठंड : तीन दिन तक उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और भारी बारिश थमने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख शीतलहर की चपेट में है। रविवार को मौसम साफ होने के बावजूद जम्मू-श्रीनगर, श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड लगातार चौथे दिन भी बंद रहा।

जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप पहाड़ी क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई। जम्मू से करीब 115 किलोमीटर दूर प्रमुख पर्यटक स्थल पर बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। प्रेट्र

तकनीक

सवा करोड़ रुपये की विदेशी डिवाइस पर भारी आइआइटी में बना 25 हजार का सेंसर, पर्यावरण फैकल्टी से मिले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को भाया यह सस्ता विकल्प

देश की आबो-हवा का हाल लेगा स्वदेशी सेंसर

जागरण संवाददाता, कानपुर

देश की आबो-हवा पर नजर रखने का दारोमदार अब आइआइटी में बने स्वदेशी सेंसर पर होगा। वायु प्रदूषण की स्थिति जानने के लिए अभी इस्तेमाल किए जा रहे विदेश के महंगे सवा करोड़ रुपये सेंसर की जगह केंद्र सरकार को आइआइटी का सेंसर बहुत सस्ते विकल्प के तौर पर भाया है। यह 50 हजार रुपये में तैयार किए गए हैं। अब इन्हें और सस्ता करने के लिए आइआइटी ने तकनीक तलाश ली है, जिससे कीमत आधी 25 हजार रुपये जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आइआइटी की पर्यावरण फैकल्टी से मिलकर इन सेंसर के बारे में जानकारी प्राप्त की।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने वहां पर चल रहे शोध कार्यों का जायजा लिया। ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए कहा, जिसका संबंध सीधे आम आदमी से हो। वह आइआइटी निदेशक प्रो. अभय करंदीकर, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी व प्रो. योगेश जोशी समेत पर्यावरण में शोध करने वाले प्रोफेसरों से मिले। आइआइटी को सस्ते सेंसर विकसित करने में प्राप्त सफलता पर वह बेहद उत्साहित हुए। ख्वाहिश जताई कि वायु प्रदूषण पर शिकंजे के लिए ऐसे सेंसर उन शहरों में लगाए जाएं जहां प्रदूषण अधिक है। आइआइटी के सेंसर ये बताएंगे कि किन क्षेत्रों में कितना प्रदूषण है और वहां इसके कारक कौन से हैं। केंद्रीय मंत्री ने वायु प्रदूषण के अलावा जल व मिट्टी को स्वस्थ्य बनाने की दिशा में चल रहे शोध कार्यों का भी जायजा लिया। प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी ने उन्हें बताया कि आइआइटी कानपुर में 12 वायु प्रदूषण मानक यंत्र लगाए गए हैं, अगले वर्ष तक इनकी संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी। प्रो. त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक वायु प्रदूषण मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है उसकी कीमत एक करोड़ 25 लाख रुपये है। उन्होंने 50 हजार रुपये का जो सेंसर तैयार किया है उसकी कीमत और कम होने की उम्मीद है।

तकनीक विकसित करने में मदद करेगी केंद्र सरकार

जावडेकर ने आइआइटी में हुई बैठक में कहा कि यहां के प्रोफेसर तकनीक विकसित करें, केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसरों के साथ हुई बैठक में उन्होंने पूछा कि वायु व जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए वे किस प्रकार मदद कर सकते हैं। इस पर प्रोफेसरों ने विकसित की गई तकनीक व भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया।

कानपुर आइआइटी में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर (बीच में) के साथ निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर (बाएं) व सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाणी। (दाएं) सा.ट्विटर

नागरिकता की नोटबंदी की तरह है एनआरसी : प्रशांत किशोर

राज्य ब्यूरो, पटना

नागरिकता संशोधन कानून पर लगातार ट्वीट कर इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे प्रशांत किशोर (पीके) ने रविवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) पर ट्वीट कर दिया। उन्होंने सीधे-सीधे भाजपा को निशाने पर लिया है। पीके ने ट्वीट किया कि एनआरसी की परिकल्पना नागरिकता की नोटबंदी की तरह है। गरीब और समाज में हाशिए पर खड़े व्यक्ति को इसका सर्वाधिक नुकसान है। यह हम सभी अपने अनुभवों से जानते हैं। नागरिकता कानून पर ट्वीट के बाद सार्वजनिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह के निशाने पर आए पीके ने शनिवार को मुख्यमंत्री से भेंट की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने यह कहा था कि एनआरसी अधिक खतरनाक है। मुख्यमंत्री भी एनआरसी के पक्ष में नहीं हैं।

गलत पार्टी में फंस गए हैं पीके : उपेंद्र कुशवाहा

राब्यू, पटना : रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रशांत किशोर गलत पार्टी में फंस गए हैं। उन्हें वहां से जल्द हट जाना चाहिए। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर प्रशांत के स्टैंड की सराहना करते हुए कहा नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है। जदयू अब भाजपा की बी टीम बनकर रह गई है। पहले तो जदयू ने असम के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनके समक्ष नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध का एलान किया। बाद में संसद में इसके पक्ष में जदयू ने मतदान कर दिया। पटना में कुशवाहा ने कहा कि संपूर्ण पूर्वोत्तर जल रहा है। सरकार नागरिकों के बारे में सोचने की बजाय राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुष्कर्म को लेकर वही बात दोहराई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। लेकिन भाजपा सदस्यों ने संसद में इसे लेकर हंगामा किया।

3000 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के कच्चातिवु के करीब से खदेड़ दिया। उन्होंने मछुआरों की 50 नावों में लगे उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया और उनकी मछलियां भी छीन लीं। रामेश्वरम मछुआरा संघ के अध्यक्ष पी. सेसुराजा ने यह जानकारी दी।

32 फीसद दुष्कर्म के मामलों में ही हो पाती है दोषसिद्धि

निर्भया दुष्कर्म मामले को सात साल का लंबा वक्त बीत चुका है। दुष्कर्म के कई मामलों ने देश को झकझोरा और लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपना विरोध जताया। इस बीच कानून और सुरक्षा चौकसी को मजबूत किए जाने के दावे होते रहे, लेकिन महिलाएं निर्भय न हो सकीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार देश में दुष्कर्म के करीब 32.2 फीसद मामले ऐसे हैं जिनमें दोषसिद्धि हो पाती है। बाकी मामलों में आरोपित छूट जाते हैं।

मामले सामने आते हैं, दोषी नहीं

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 2017 में दुष्कर्म के कुल मामले जो ट्रायल के लिए गए उनकी संख्या एक लाख 46 हजार 201 थी, लेकिन इनमें से केवल 5 हजार 822 मामलों में ही दोषसिद्धि हो सकी। चार्जशीट पेश करने की दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। 2017 में चार्जशीट पेश करने की दर 86.6 फीसद रही जो 2013 में 95.4 फीसद थी।

बिना कोर्ट पहुंचे कैसे होगा न्याय

यह आंकड़े चिंताजनक इसलिए हैं कि दुष्कर्म मामलों में दोषसिद्धि की दर में मामूली सा इजाफा हुआ है लेकिन चार्ज शीट दर में गिरावट दर्ज की गई है। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि जब मामले कोर्ट तक जाएंगे ही नहीं तो न्याय कैसे होगा?

इसलिए नहीं होती दोषसिद्धी

चर्चित अलवर दुष्कर्म केस में एक विदेशी महिला के साथ ओडिशा के पूर्व डीजीपी बीबी मोहंती के बेटे बिट्टी मोहंती ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में बचाव पक्ष की वकील रहीं शिल्पा जैन के अनुसार पुलिस के फील्ड लेवल स्टॉफ को दुष्कर्म मामलों की जांच के लिए ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। वे अप्रशिक्षित होते हैं, ताकत उनके हाथों में होती है और ज्यादातर मामलों में वे भ्रष्ट होते हैं। उसी प्रकार से, जिला स्तर पर अभियोजन पक्ष कम क्षमता और कम योग्य होता हैं। यह सभी कारक मिलकर कम दोषसिद्धि की वजह बनते हैं।

निर्भया के बाद जागा प्रशासन

निर्भया दुष्कर्म मामले के एक सप्ताह बाद यौन उत्पीड़न मामलों से कठोरता से निपटने के लिए जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी को आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए गठित किया गया। कमेटी ने एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसी के आधार पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में दुष्कर्म के लिए सबसे बड़ी सजा फांसी या फिर उम्रकैद का प्रावधान किया गया। 03 फरवरी 2013 को आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2013 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अनुमोदित किया। यह अध्यादेश दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का प्रावधान करता है।

किशोरों से सख्ती

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा) अधिनियम 2015 को भी संसद ने पारित किया। इसमें 16 से 18 साल का किशोर यदि जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उस पर एक वयस्क की तरह व्यवहार किया जाएगा।

एनसीआरबी के अनुसार 2001-17 के बीच देश में 4,15,786 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। यानी हर घंटे तीन मामले सामने आए

सात साल पहले हुई दरिंदगी, अब तक देश को है इंसाफ का इंतजार

आक्रोश ▶ दरिंदों का शिकार हुई बेटी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरा देश सड़क पर उतर आया था

दोस्त के साथ आ रही फिजियोथेरेपिस्ट छात्रा बनी थी हैवानों का शिकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सात साल पहले आज ही की तारीख (16 दिसंबर) को चलती बस में हैवानियत की सारी हदें पार की गई थीं। छह दरिंदों का शिकार हुई बेटी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए तब दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश सड़क पर उतर आया था। इसके बाद न सिर्फ सरकार ने कानून बदला बल्कि अदालत ने भी तेजी से सुनवाई कर चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। एक दोषी ने जेल में खुदकशी कर ली थी, जबकि छठा आरोपित नाबालिग था। विडंबना ही है कि गुनहगारों को फांसी देने की उल्टी गिनती शुरू होने में सात साल लग गए और अब भी देश को इंसाफ का इंतजार है।

16 दिसंबर 2012 को फिजियोथेरेपिस्ट छात्रा दोस्त के साथ फिल्म देखने गई थी। वहां से निकलने के बाद रात्रि नौ बजे वह मुनिरका बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। उसी समय लग्जरी निजी बस में सवार लोगों ने दोनों को बैठा लिया। बस में सवार नाबालिग सहित छह लोगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। दोस्त ने विरोध किया पीटकर उसे चुप करा दिया और छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दरिंदे इतने से नहीं माने। उन्होंने छात्रा की निर्ममता से पिटाई की और रॉड इस कदर पेट में डाला था कि आंतें बाहर निकल आई थीं। गंभीर रूप से जख्मी हालत में दोनों को वसंत विहार थाना क्षेत्र के एक होटल के पास सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे एम्स में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां भी उसे बचाया नहीं जा सका और 29 दिसंबर को छात्रा की सांसें टूट गईं।

- सरकार ने कानून बदला, निर्भया फंड बना, फिर भी नहीं बदले हालात
- एक दोषी ने कर ली खुदकशी, चार को हो चुकी फांसी की सजा
- सिंगापुर में 29 दिसंबर को हुई थी पीड़िता की मौत

वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र। (फाइल)

दरिंदों की फांसी देखना चाहते हैं निर्भया के पिता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया के पिता बताते हैं कि यदि जेल प्रशासन अनुमति दे तो वे तिहाड़ के फांसी घर में उस समय मौजूद रहना चाहते हैं, जब दोषियों को फंदे पर लटकाया जाएगा। वे बताते हैं कि जेल का कानून क्या कहता है, इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। इस बाबत वे जेल प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं। कानून जो भी हो, लेकिन एक बार अपनी इच्छा को वे जेल प्रशासन के समक्ष अवश्य रखना चाहते हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में वे जेल प्रशासन को इस संबंध में पत्र लिखेंगे।

निर्भया के पिता बताते हैं कि हमें उस वक्त ज्यादा दुख होता है, जब गुनहगारों को सजा देने के लिए हमें गुहार लगानी पड़ती है। सात साल हो गए, मेरी बेटी के गुनहगार जिंदा हैं। यह ऐसी बात है जो हर उस माता-पिता को परेशान करती है, जिनके घर एक बेटी है। दुष्कर्मी अब अपने बचाव के लिए पीड़िताओं को मार रहे हैं। उन्हें अब इस बात का यकीन है कि कानूनी दांव-पेच का इस्तेमाल कर वे हर हाल में जिंदा बचे रह सकते हैं। यदि मेरी बेटी के गुनहगारों को फंदे पर लटका दिया गया होता तो आज महिलाओं पर लोग बुरी नजर रखने से भी डरते। यह विडंबना है कि अपराधियों में भय नहीं है, बल्कि भय में हमारे देश की बेटियां जी रही हैं।

इस घटना ने समाज को झकझोर दिया। दिल्ली से लेकर देश के कोने-कोने में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन हुआ। ऐसी दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा देने और मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मांग उठी। आखिर सरकार ने कानून में संशोधन किया। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बना। इधर, पुलिस के लिए दोषियों तक पहुंचना बेहद कठिन था, लेकिन बस पर यादव लिखे होने का सुराग मिला तो पुलिस ने कड़ियां जोड़कर छह लोगों को पकड़ा। इनमें आरके पुरम निवासी बस चालक रामसिंह, उसका भाई व बस हेल्पर मुकेश कुमार, हेल्पर अक्षय कुमार सिंह, फल विक्रेता पवन गुप्ता निवासी रविदास कैंप, यहीं के रहने वाले जिम के हेल्पर विनय शर्मा के अलावा एक नाबालिग (तब साढ़े सत्रह साल) को पकड़ा गया था। 31 अगस्त को बाल न्यायालय ने हत्या में अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा पूरी होने के बाद 2015 में उसे रिहा कर दिया गया। अन्य आरोपितों को कोर्ट से फांसी की सजा हुई। इनमें रामसिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकशी कर ली थी। शेष चार दोषियों को फांसी दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

इन छह दरिंदों ने किया था निर्भया कांड

रामसिंह (मुख्य आरोपी)

पता- झुग्गी नंबर जे 49, रविदास कैंप, आरके पुरम सेक्टर 3

काम- बस चालक

तिहाड़ जेल संख्या 3 में 11 मार्च 2013 को खुदकुशी कर ली

मुकेश कुमार

पता- रविदास कैंप, आरकेपुरम सेक्टर 3

काम- ड्राइवर कम हेल्पर

रामसिंह का भाई है, दोनों साथ रहते थे, भाई के बस पर हेल्पर था, घटना के समय यही बस को चला रहा था।

अक्षय कुमार सिंह उर्फ अक्षय ठाकुर

पता- रविदास कैंप, आरकेपुरम सेक्टर 3

मूल निवासी- औरंगाबाद, बिहार

काम- बस हेल्पर

पवन गुप्ता

पता- रविदास कैंप, आरकेपुरम सेक्टर 3

काम- फल विक्रेता

विनय शर्मा

पता- रविदास कैंप, आरकेपुरम सेक्टर 3

काम- जिम में हेल्पर

छठा आरोपित वारदात के नाबालिग (17 साल छह महीने 11 दिन का था) बालिग होने के बाद उसे 31 अगस्त को बाल न्यायालय ने हत्या में अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा पूरी होने के बाद दिसंबर 2915 में उसे रिहा कर दिया गया।

कैसे हों महिलाएं निर्भय जब एक रुपया भी न खर्च किया

1,649 करोड़ रुपये का राज्यों ने नौ फीसद से भी कम किया उपयोग

- महाराष्ट्र समेत छह राज्यों ने निर्भया फंड का नहीं किया इस्तेमाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिला सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 से केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला निर्भया फंड का राज्यों ने महज नौ फीसद इस्तेमाल किया है। देश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों की तादाद के बीच महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्यों ने इस मद में एक रुपया भी खर्च नहीं किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फंड के तहत 1,649 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसमें से राज्यों ने केवल 147 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं।

हाल ही में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में दुष्कर्म और हत्या के की भयावह वारदातों के बीच महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल में ही लोकसभा को बताया था कि निर्भया फंड के तहत सबसे बड़ी रकम पाने वाले राज्यों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल हैं। केंद्र से मिले फंड का कर्नाटक ने सात फीसद ही इस्तेमाल किया है। केंद्र से मिली यह राशि को 191 करोड़ रुपये दिए थे जिसमें से केवल 13.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए। तमिलनाडु ने 190.68 करोड़ रुपये में से केवल छह करोड़ रुपये यानी तीन फीसद रकम का ही उपयोग किया। केंद्रीय मंत्री ने संसद में दिए आंकड़ों में बताया था कि छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और दमन व दिवु ने केंद्र से मिली रकम में से एक रुपया भी इस मद में खर्च नहीं किया है।

आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, जहां निर्भयाकांड हुआ था, में फंड की पांच फीसद से भी काम धनराशि खर्च की गई है। राष्ट्रीय राजधानी को 390 करोड़ रुपये दिए गए थे जिसमें से केवल 19.41 करोड़ के उपयोग का राज्य सरकार ने सर्टीफिकेट जारी किया है। जब इस विषय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें निर्भया फंड का इस्तेमाल 5500 डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्हें 390 करोड़ रुपये की रकम ही नहीं मिली है।

तेलंगाना, जहां 26 वर्षीय पशु चिकित्सक से दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, ने भी 103 करोड़ रुपये में से सिर्फ चार करोड़ रुपये की खर्च किए हैं। केंद्र सरकार से निर्भया फंड के तहत मिलने वाली रकम का इस्तेमाल एमरजेंसी रिस्पांस स्कीम समेत 13 योजनाओं पर खर्च किया जाना है।

केंद्र सरकार ने निर्भया फंड का समुचित इस्तेमाल नहीं होने का दोष राज्य सरकारों पर डाला है। जबकि राज्यों का आरोप है कि उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों को केंद्र ने मंजूरी ही नहीं दी। वहीं समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील की है कि वह तत्काल युद्धस्तर पर कदम उठाकर सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं।

थम गई थी दिल्ली, फूटा था गम और गुस्से का गुबार

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली : वसंत विहार में दरिंदों की शिकार हुई बहादुर बेटी की मौत से पहले दिल्लीवासियों की आंखों में जो क्रोध था, वह गम और गुस्से के गुबार में बदल गया था। यही वजह थी कि जब 29 दिसंबर को इस बहादुर बेटी की मौत की खबर आई तो हर आंख छलक पड़ी और राजधानी थम सी गई थी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं के होठ तो फड़फड़ा रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। दरअसल, 13 दिनों तक अस्पताल में दर्द और मौत से जंग करने के बाद इस बेटी ने देश के हर इंसान के साथ एक रिश्ता बना लिया था।

निर्भया की मौत की सूचना मिलने पर लोगों ने पहले इंडिया गेट की ओर रुख किया था। लेकिन, पुलिस ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। तब हाथों में बैनर व होर्डिंग लेकर लोग जंतर-मंतर पहुंच गए थे। उस दिन प्रदर्शन कर रहे लोगों के नारों में फर्क था। क्योंकि उनके चेहरे पर पीड़िता के इस बेदर्द दुनिया को विदा कर जाने का दर्द और गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, जंतर मंतर सहित पूरी दिल्ली में प्रदर्शन तेज हो गया था। सड़कों पर उतरे लोगों के चेहरे से दर्द साफ झलक रहा था। उनमें आक्रोश भी था। शाम के समय अनेक स्थानों पर कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई थी। लोगों ने दबी जुवान प्रशासन को आगाह कर दिया था कि अब तो जाग जाओ। नहीं तो हम तुम्हें जगा देंगे। उस समय की याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनता में गुस्सा इस कदर था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जब जंतर-मंतर पर पीड़िता को श्रद्धांजलि देने पहुंची तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था।

फतेहपुर दुष्कर्म मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में गरमाई सियासत

जागरण टीम कानपुर

लगता है खत्म हो गया पुलिस का खौफ : कमलेश गौतम

दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कमलेश गौतम ने पुलिस के इकबाल व भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कह दिया कि लगता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ ही नहीं रहा। पुलिस महिला अपराध की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेती, इसी वजह से घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा की जरूरत बताई। साथ ही अधिकारियों के उन बयानों पर आपत्ति जाहिर की, जिसमें कहा गया कि युवती ने खुद आग लगाई। कहा कि अफसरों को तलब कर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने पीड़िता के गांव पहुंचकर भी जानकारी ली।

उप्र स्थित फतेहपुर के हुसेनगंज थाना के एक गांव में शनिवार को सुबह दुष्कर्म के बाद युवती को केरोसिन डालकर आग लगाने की सनसनीखेज घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा के निर्देश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा व पूर्व सांसद राकेश सचान ने एलएलआर अस्पताल (हैलट) में भर्ती युवती का हाल जाना।

दोपहर में एलएलआर अस्पताल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं पर प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस गंभीर है, लेकिन प्रदेश सरकार संवेदनशील नहीं है। आराधना मिश्रा ने पीड़िता के भाई से कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पार्टी उनके साथ है। उन्होंने डॉक्टरों से पीड़िता का हाल जाना। उन्होंने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने व आरोपित को फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द सजा सुनाए जाने की मांग की। पूर्व सांसद राकेश सचान ने फतेहपुर जिलाधिकारी से बात कर मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपये दिलाने के लिए कहा।

उधर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधायक इरफान सोलंकी के साथ सपा नेता अस्पताल में पीड़िता के स्वजनों से मिले। उन्होंने स्वजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। स्वजनों को 40 हजार रुपये मदद दी गई। फतेहपुर में पीड़िता के गांव में भी कांग्रेस व सपा के स्थानीय नेता पहुंचे। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर घटना को दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है।

पीड़िता की हालत गंभीर : एलएलआर अस्पताल में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता की हालत बेहद गंभीर है। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक प्रो. आरके मौर्या ने बताया कि फिलहाल युवती की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कमलेश गौतम ने डीएम विजय विश्वास पंत से मुलाकात की। उन्हें दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट कराकर दिल्ली शिफ्ट कराने के कहा। इसके बाद प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है।

रविवार को फतेहपुर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डीएनए जांच के लिए आरोपित के खून व सीमेन का सैंपल लिया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

खाताधारकों का प्रदर्शन

मुंबई में रविवार को भारतीय रिजर्व बैंक के सामने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले खाताधारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मातोश्री में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। प्रेट्र

रामपुर में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या

जागरण संवाददाता, रामपुर : उप्र के रामपुर स्थित पटवाई थाना क्षेत्र में पांच दिन से लापता युवती का शव मिला है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी ही निशानदेही पर शव को बरामद किया गया।

पटवाई थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 10 दिसंबर को गोबर फेंकने घर से बाहर गई थी। इसके बाद वह नहीं लौटी। परिजनों ने गांव के ही धर्मपाल के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया था। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कुबूल कर ली। रविवार को उसकी निशानदेही पर युवती की लाश बरामद की गई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस की ढिलाई पर परिजनों ने जाम लगाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपित से युवती के प्रेम संबंध थे। लेकिन युवक ने दूसरी युवती से शादी कर ली। संबंध उजागर होने पर उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। उसने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इधर, युवती युवक पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी कारण आरोपित ने प्रेमिका को बुलाकर उसकी हत्या कर दी।

सखी

हरियाणा सरकार ने थानों में लंबित छह माह से दो साल पुरानी एफआइआर की रिपोर्ट मंगाई

बेलगाम हरियाणा पुलिस का पोस्टमार्टम करने की तैयारी

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा में न्याय के लिए बरसों से पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे फरियादियों की अब सुनवाई होने की आस बढ़ गई है। राज्य के पुलिस थानों में हजारों केस ऐसे हैं, जो छह महीने से दो साल पुराने हो गए, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी के प्रति जवाबदेही के अभाव में पुलिस लंबे समय से अपनी चाल चल रही है और फरियादियों को नजर अंदाज कर रही है। अब राज्य सरकार ने सभी थानों से लंबित मामलों की रिपोर्ट मंगवाई है।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने पास आने वाली शिकायतों की समीक्षा के दौरान महसूस किया कि न्याय में देरी पुलिस थानों के स्तर पर ही हो रही है। राजनीतिक दबाव हो या फिर सामाजिक मजबूरी, पुलिस लोगों की एफआइआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं देती। गृह मंत्री ने राज्य के पुलिस थानों से करीब दो साल पुरानी उन तमाम एफआइआर का रिकार्ड तलब कर लिया है, जो अभी तक न्याय के अभाव में लंबित हैं।

गृह मंत्री ने डीजीपी को पूरे राज्य से ऐसी रिपोर्ट मंगवाकर उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। विज ने तीन स्तर पर यह रिपोर्ट मांगी है। दो साल पुराने तमाम केस की रिपोर्ट अलग देनी होगी और एक साल पुराने केस की रिपोर्ट अलग। छह माह पुरानी एफआइआर से जुड़े केसों की अलग रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तीन स्तर पर रिपोर्ट आने के बाद यह आकलन किया जा सकेगा कि न्याय में देरी की वजह क्या है।

अनिल विज के थानों से रिपोर्ट तलब करने संबंधी फरमान से पुलिस अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना इंचार्ज को कहा गया है कि वह लंबित केस की रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही इस बात की भी जानकारी दें कि न्याय में देरी किस वजह से हुई यानी एफआइआर तो दर्ज हो गई, मगर उस पर कार्रवाई में देरी के क्या कारण रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस को 15 दिन का समय दिया गया है। हालांकि इसमें एक सप्ताह बीत भी चुका है। पुलिस अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। (फाइल)

इसलिए बेलगाम होती रही हरियाणा पुलिस

हरियाणा में किसी मंत्री को करीब 21 साल के लंबे अंतराल के बाद गृह मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है। अन्यथा गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही होता है। गृहमंत्री के नाते सीएम की कार्रवाई डीजीपी, गृह सचिव अथवा एडीजीपी तक ही सीमित होती है। इसलिए निचले स्तर पर पुलिस के कामकाज की सही तरीके से समीक्षा नहीं हो पाती।

अब देखना कैसे होंगे पुलिस थानों में काम

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेरे पास रोजाना 500 से 600 शिकायतें आती हैं। लोग इसलिए ही शिकायतें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस थानों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने प्रत्येक थाने से छह से दो साल पुराने केसों की रिपोर्ट तलब की है, ताकि जान सकूं कि पुलिस निचले स्तर पर कैसे काम कर रही है।

उन्नाव दुष्कर्म कांड में कुलदीप सेंगर के खिलाफ फैसला आज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के करने के मामले में तीस हजारी कोर्ट सोमवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ फैसला सुनाएगी। अदालत ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला 16 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत पांच अगस्त से प्रतिदिन मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने पॉक्सो की धारा 3 व 4 (नाबालिग से दुष्कर्म) और भादंसं की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (दुष्कर्म) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। अदालत ने कहा था कि 4 जून 2017 को नौकरी दिलाने के नाम पर अपनी सहयोगी शशि सिंह के साथ मिलकर कुलदीप सेंगर ने साजिश रची और सहमति के बगैर 16-17 साल की किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अपराध किया।

यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब पीड़िता और उसकी मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता के खिलाफ 3 अप्रैल 2018 को शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस हिरासत में अत्यधिक पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई थी। 28 जुलाई को चाचा से मिलकर वापस लौटने के दौरान रायबरेली में पीड़िता, उसकी चाची, मौसी व वकील की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसमें चाची और मौसी की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता व उसके वकील घायल हो गए थे।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

दैनिक जागरण
व्यावहारिकता के नाम पर आदर्शों की बलि देना अनुचित है

संविधान की फर्जी आड़ में हिंसा

संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों की फर्जी आड़ लेकर नागरिकता कानून का जैसा हिंसक विरोध हो रहा है उससे यही पता चल रहा कि अराजक तत्व उत्पात पर आमादा हैं। सरकारी एवं निजी संपत्ति को आग के हवाले करने और सड़क एवं रेल मार्ग को बाधित करने वाले इन उपद्रवी तत्वों का दुस्साहस इसीलिए चरम पर है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल उन्हें उकसाने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में तो यह लगभग पूरी तौर पर साफ है कि ममता बनर्जी सरकार नागरिकता कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे अराजक तत्वों को परोक्ष तौर पर शह देने में लगी हुई है। यही कारण है कि वहां मालदा, हावड़ा और मुर्शिदाबाद में व्यापक पैमाने पर हिंसा और आगजनी देखने को मिली। यदि उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्ती का परिचय दिया जा रहा होता तो यह संभव ही नहीं था कि बंगाल में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा देखने को मिलती। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से बंगाल में हिंसा को भड़काया जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वह बंगाल में मचाए जा रहे उत्पात के लिए ममता सरकार को जवाबदेह बनाए।

चूंकि नागरिकता कानून विरोधी हिंसा ने दिल्ली में भी अपने पैर पसार लिए हैं इसलिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही सख्ती का भी परिचय देना होगा। विरोध का मतलब नग्न अराजकता नहीं हो सकता। दिल्ली में अराजक भीड़ ने जिस तरह दिन-दहाड़े कई बसों और दोपहिया वाहनों को आग के हवाले किया उससे तो यही लगता है कि सुनियोजित तरीके से नागरिकता कानून विरोधी हिंसा को हवा दी जा रही है। चिंताजनक यह है कि यह खतरनाक काम देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है। कई राजनीतिक दल इसके लिए अतिरिक्त मेहनत करते भी दिख रहे हैं। दुष्प्रचार में लिप्त ऐसे दलों की केवल आलोचना ही पर्याप्त नहीं। उन्हें बेनकाब भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मानवतावादी होने का मुखौटा लगाए उत्पाती तत्वों को यह सख्त संदेश भी देना होगा कि किसी भी सूरत में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निःसंदेह किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को नागरिकता कानून का विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर जब यह स्पष्ट है कि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कहीं कोई लेना-देना नहीं तब फिर उसके विरोध का क्या औचित्य? उत्पात का पर्याय बन गए इस उन्माद भरे हिंसक विरोध से कड़ाई से निपटना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कानून के शासन की हेठी हो रही है।

टकराव अशुभ

ममता बनर्जी सरकार के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ का टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बंगाल में सरकार के साथ राजभवन की खींचतान कोई नई बात नहीं है। इसके पहले केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टकराव हुआ था। त्रिपाठी के साथ जितनी तीव्र गति से टकराव पैदा हुआ था उतनी जल्द ही मतभेद दूर भी कर लिया गया। हिंसा के एक मामले में पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने जब मुख्यमंत्री को फोन कर स्पष्टीकरण मांगा तो वह बिफर गईं। सीएम ने त्रिपाठी पर धमकी देने का आरोप लगाया और इससे खुद को एक सीएम के रूप में अपमानित होने की बात कही। कुछ दिनों तक त्रिपाठी और मुख्यमंत्री के बीच खींचतान चली, लेकिन अचानक रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद राजभवन जाकर त्रिपाठी को राखी बांधी और उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। वाममोर्चा के लंबे शासन में तो वामपंथी नेताओं ने राज्यपाल को कभी महत्व ही नहीं दिया। सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलन के समय तत्कालीन राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी ममता बनर्जी की बातों को गंभीरता से लेते थे। इस पर वाममोर्चा के नेताओं ने गोपालकृष्ण गांधी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था, लेकिन वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ सरकार का टकराव जिस हद तक चला गया है वह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकाधिक बार धनखड़ पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगा चुकी हैं। खैर मामला अगर आरोप प्रत्यारोप तक हो तो भी चल सकता है, लेकिन राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यदि कोई बिल सदन में पेश नहीं किया जा सके और इस कारण स्पीकर को दो दिनों तक सदन स्थगित कर देना पड़े तो यह गंभीर मामला बनता है। सरकार और राजभवन के बीच इसी तरह खींचतान चलती रही तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में एक पूर्ण बहुमत की निर्वाचित सरकार है, लेकिन राज्यपाल भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। इस नाते उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। पिछले दिनों जो दो घटनाएं घटीं वह लोकतांत्रिक सरकार के लिए शोभा नहीं देती हैं। पहले राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय गए तो वीसी नहीं थे। दूसरे दिन राज्यपाल विधानसभा गए तो गेट पर ताला लगा था। इतना कुछ होने के बावजूद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सारे मुद्दों पर बातचीत करने की इच्छा जताई है तो वार्ता के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।

प्रतीकों की प्रतिस्पर्धा में फंसी राजनीति

बद्री नारायण

यदि अपने नायकों की विरासत पर दावा करने वाले दलों के पास भाजपा के प्रभावी विमर्श की सही काट नहीं तो तो देर-सबेर उन्हें ये प्रतीक भी गंवाने ही पड़ेंगे

राजनीतिक महानायकों की स्मृतियों का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाली राजनीतिक धारा की शक्ति कितनी प्रभावी है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि उक्त राजनीतिक धारा को उस नायक की स्मृति एवं विरासत की उस वक्त कितनी जरूरत है। अक्सर यह देखने को भी मिलता है कि कोई राजनीतिक नायक अपने जीवनकाल में जितना महत्वपूर्ण नहीं होता, वह बाद में कई गुना प्रभावी हो जाता है। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के मामले में ऐसा ही हुआ है। अपने जीवन काल में वह एक यथार्थ बने रहे और उसके उपरांत एक मिथक में तब्दील हो गए जो उनके यथार्थ वाले प्रभाव को बढ़ाता गया। जीवनपर्यंत किए कार्यों के कारण ही कालांतर में वह दलित मुक्ति के प्रतीक में परिवर्तित होते गए। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में उनके जीवनकाल में ही लामबंद समर्थकों एवं अनुयायियों का एक वर्ग तो तैयार हो ही गया था। उनके निधन के पश्चात भी दलित समर्थक राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआइ उनके विचारों को आगे बढ़ाती रही। हालांकि इस दौरान आरपीआइ का आधार खिसकता गया। इसकी भरपाई आजादी के बाद उभरे दलितों के शिक्षित वर्ग से हुई जो लोग शिक्षा प्राप्ति एवं अपने अधिकारों के लिए आंबेडकर के प्रतीक से अपने संघर्ष की प्रेरणा पाने लगे। इस प्रकार आंबेडकर के प्रतीक को नई ऊर्जा, नई शक्ति एवं नया जीवन मिला। उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में कांशीराम के नेतृत्व में उभरे बहुजन दलित आंदोलन, जिसने आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का रूप अख्तियार किया, ने आंबेडकर के प्रतीक को और शक्तिशाली बनाया। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में पिछली सदी के नौवें दशक में उभरे बहुजन दलित आंदोलन के तहत दलितों की राजनीतिक गोलबंदी की गति तेज हुई। फलतः उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में आंबेडकर का प्रतीक और ताकतवर बनकर उभरा। इस व्यापक उभार में इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि उत्तर भारत खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुजन सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन ने भी इसे धार देने का काम किया। इस जुगलबंदी से आंबेडकर दलितों के निर्विवाद महानायक के रूप में स्थापित होते गए। इससे यही आशय है कि राजनीतिक नायकों के नायकत्व का विकास उनकी विचारधारा के प्रतिनिधियों की राजनीतिक शक्ति एवं संबंधित विमर्श में उन्हें दी जाने वाली जगह पर निर्भर करता है।

डॉ. राममनोहर लोहिया, पंडित नेहरू के बाद दूसरे राजनीतिक नायक थे। उनका नायकत्व तो उभरा, किंतु भारतीय समाज में पिछड़े वर्ग के समूहों के राजनीतिक सशक्तीकरण, भागीदारी और विकास के लिए किए गए अनेक कार्यों के बावजूद वह आंबेडकर जैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। इसका मूल कारण यह है कि समाजवादी आंदोलन से उभरे सामाजिक समूहों एवं राजनीतिक दलों ने अपने विमर्श को इस प्रकार आकार नहीं दिया जिसमें लोहिया का नायकत्व विकसित हो पाए। यह ठीक है समाजवादी सरकारों ने तमाम संस्थाओं-स्थानों को लोहिया का नाम दिया, परंतु उन्होंने इस प्रतीक को और शक्तिशाली बनाने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए। कहने का अर्थ है कि समाजवादी विचारधारा से उभरे दलों ने सत्ता और ताकत हासिल करने के बावजूद अपने विमर्श को इस प्रकार नियोजित नहीं किया जिससे समाजवादी विचारधारा का महिमामंडन होने के साथ ही लोहिया का नायकत्व भी उभर सके। अगर तुलना करें तो आंबेडकर ने दलितों के लिए जो किया, बिल्कुल वही काम लोहिया ने पिछड़ों को सशक्त बनाने के लिए किया। कुछ ऐसा ही जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ। जेपी आंदोलन से निकलकर तमाम नेता राजनीति के आकाश पर तो खूब चमके, लेकिन उन्होंने जेपी को वैचारिक स्मृति का प्रेरक तत्व बनाकर अपना कोई विशिष्ट राजनीतिक विमर्श विकसित नहीं किया।

अवधेश राजपूत

वर्ष 2014 के बाद भाजपा के शक्तिशाली होने के बाद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे राजनीतिक प्रतीकों का महत्व बढ़ा है। इसके पूर्व इन प्रतीकों के बारे में शायद लोग ज्यादा नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि भाजपा ने अपने राजनीतिक विमर्श के मूल तत्वों में इनके विचारों को शामिल किया। इसी तरह मदनमोहन मालवीय की गिनती आजादी के पहले दिग्गज कांग्रेस नेताओं में हुआ करती थी, किंतु वर्ष 2014 में भाजपा के सत्ता में आने एवं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मालवीय और सरदार वल्लभभाई पटेल का नायकत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस के ही उन प्रतीकों को अपनाया जिनकी कांग्रेस की पहली पांत के प्रतीकों के आगे अमूमन अनदेखी की गई। भाजपा ने पटेल और मालवीय जैसे कांग्रेसी प्रतीकों को कांग्रेस के शीर्ष प्रतीकों के समानांतर खड़ा करने का प्रयास कर राजनीतिक प्रतीकवाद के मोर्चे पर अपनी शक्ति का दायरा बढ़ा लिया। चूंकि भाजपा के पास अपने ज्यादा प्रतीक नहीं थे, लिहाजा उसने अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई के कुछ कांग्रेसी नायकों को अपनाया। हालांकि इसमें भी उसने यह खयाल जरूर रखा कि ये प्रतीक उसकी वैचारिकी के खांचे में भी फिट हो सकें। मिसाल के तौर पर मालवीय को ही लें। वह कांग्रेस में हिंदू पक्षधर राजनीति के समर्थक थे। इसी तरह सरदार पटेल और नेहरू के प्रतीकों में कई ऐसे अंतर्विरोध थे जिन्हें आगे लाकर भाजपा ने अपना राजनीतिक विमर्श गढ़ा। कांग्रेस अपने ही प्रतीकों के भाजपा के पाले में जाने से रोकने के लिए कोई प्रतिरोधी विमर्श खड़ा करने में नाकाम रही। परिणामस्वरूप कांग्रेस अपनी प्रतीक शक्ति के कई तत्वों को गंवाती गई। इस तरह सत्ता के साथ-साथ ये प्रतीक भी उसके हाथ से फिसलते रहे।

इस तरह यह स्पष्ट है कि राजनीतिक नायकों की प्रतीकात्मक शक्ति का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके वैचारिक प्रतिनिधि भविष्य में उन्हें किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। उनके विचारों से प्रभावित राजनीतिक पक्ष अपने विमर्श में उन्हें कैसे, कहां और किस तरह स्थान देते हैं। भाजपा ने हाल में तमाम ऐसे प्रतीकों को अपने खेमे से जोड़कर बड़ी शक्ति अर्जित कर ली है। इस प्रकार वह आंबेडकर, मालवीय, सरदार पटेल और विवेकानंद को अपने पक्ष में भुना सकती है। यही नहीं, लोहिया को कांग्रेस विरोध से जोड़कर वह उन्हें भी अपने पाले में लाने के प्रयास करती रही है। अगर इन नायकों की विरासत पर दावा करने वाले दलों के पास ऐसे प्रभावी विमर्श की सही काट नहीं है तो देर-सबेर उन्हें ये प्रतीक भी गंवाने ही पड़ेंगे।

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

अपने अस्तित्व को सार्थक करता बांग्लादेश

नंदिनी सिन्हा

16 दिसंबर को विजय दिवस हमें बांग्लादेश निर्माण का स्मरण कराता है जिसने कई मुश्किलों के बावजूद एक मिसाल पेश की है

आज से ठीक 48 साल पहले दुनिया के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा रहा यह मुल्क एक लंबे हिंसक संघर्ष के बाद स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। भारत ने भी इस नए देश के जन्म में सार्थक और सहयोगी भूमिका निभाई। इससे पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे पर होने वाले टकराव के बीज भाषा आंदोलन के दौरान ही पड़ गए थे। देश के राजकाज में पूर्वी पाकिस्तान की नहीं चलती थी। इसलिए वहां के बाशिंदों में नाराजगी स्वाभाविक थी। वर्ष 1948 में यह तल्खी तब और बढ़ गई जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एलान किया कि देश की राष्ट्रभाषा उर्दू होगी। इस पर पहले से ही नाराज चल रहे पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लाभाषियों का आक्रोश उबल पड़ा। इसके बाद संघर्ष लगातार बढ़ता गया। 1958 से 1962 के बीच तथा 1969 से 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान मार्शल लॉ के अधीन रहा। 1970-71 में पाकिस्तान के संसदीय चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग ने बड़ी संख्या में सीटें जीतीं और सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो को वह बात नागवार गुजरी। पूर्वी पाकिस्तान से निकली लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सैनिक अत्याचार से कुचलना शुरू कर दिया। तब वही बलिदानी चेतना सशस्त्र मुक्ति संग्राम के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही मुक्ति युद्ध प्रारंभ हो गया। पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का समर्थन किया था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल एके नियाजी ने आखिरकार हार स्वीकार करते हुए अपने 93 हजार सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसे इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी माना जाता है। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के नाकाम होने के उपलक्ष्य में यह दिन हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बहरहाल भारत के सहयोग से एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का उदय तो हो गया, किंतु नए देश के नवनिर्माण की बड़ी और कड़ी चुनौती सामने थी। बड़े पैमाने पर गरीबी, मानव संसाधन की कमी, सीमित प्राकृतिक संसाधन, अकाल, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियां भी बेहद आम थीं। इन सबके बावजूद मुक्ति संग्राम सेनानियों ने बांग्लादेश को 'सोने का देश' बनाने का सपना देखा। रवींद्रनाथ टैगोर के गीत 'आमार सोनार बांग्ला' को जब बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया तो इसके पीछे देश की प्रगति ही राष्ट्रनिर्माताओं के जेहन में थी। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आज बांग्लादेश ने अपने विकास से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। इस देश ने गरीबी में कमी, कम वजन वाले बच्चों की संख्या को घटाने, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, शिशु मृत्यु दर और जननी मृत्यु दर को कम करने में महती सफलता अर्जित की है। पिछले वर्ष बांग्लादेश ने अपना पहला भू-स्थिर संचार उपग्रह, बंगबंधु-1 या बीडी लांच किया।

विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ द्वारा प्रस्तुत वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में बांग्लादेशी सभी दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर स्थिति में है। ऐसे सूचकांक की गणना आमतौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति सहित चार मापदंडों के आधार पर की जाती है ताकि किसी देश में लैंगिक समानता की स्थिति का पता लगाया जा सके। वर्ष 2018 में स्त्री-पुरुष समानता के मामले में बांग्लादेश 48वें स्थान पर रहा जबकि भारत 108वें स्थान पर था। मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया के रूप में देश की दोनों शीर्ष नेता महिलाएं ही हैं। बांग्लादेश ने महिलाओं के रोजगार के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्तीकरण पर बहुत ध्यान दिया। इसीलिए यहां कामकाजी वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है, जबकि भारत में मात्र 28 प्रतिशत।

घरेलू उद्योगों की बढ़ती क्षमता के कारण बांग्लादेश का निर्यात 2018 के 6.7 फीसदी से बढ़कर 2019 में 10.1 प्रतिशत पहुंच गया। उसके कुल निर्यात में कपड़ा निर्यात का योगदान 84.2 फीसद है। रेडीमेड कपड़ा उद्योग में उसने खासी तरक्की की है। अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में बांग्लादेशी कपड़ों की अच्छी-खासी मांग है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश ने एक उद्यमी देश के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है। बांग्लादेश विकास के इस स्तर पर पहुंच गया है कि वह न केवल भारत में निवेश की क्षमता रखता है, बल्कि भारतीय कंपनियों को अपने यहां निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रहा है। कुछ महीने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित इंडिया इकोनॉमिक समिट में मुख्य अतिथि के रूप में आई थीं। वहां उन्होंने भारतीय कंपनियों को अपने देश में निवेश का न्योता दिया। इस वक्त चीन की तमाम कंपनियां बांग्लादेश को अपना ठिकाना बना रही हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल बांग्लादेश की आर्थिक विकास दर के अन्य दक्षिण एशियाई देशों से ज्यादा रहने की संभावना है। 1990 के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चार-पांच प्रतिशत की दर से बढ़ी है। क्रय शक्ति भारिता यानी पीपीपी के संदर्भ में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 1991 में 890 डॉलर प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2011 में 2,780 डॉलर प्रति व्यक्ति हो गई। कहना न होगा कि कोई भी देश न तो अपने बड़े क्षेत्रफल से ताकतवर होता है न ही अपनी बड़ी जनसंख्या से, बल्कि उसके विकास की गति ही उसकी ताकत को बयां करती है। बांग्लादेश वही उदाहरण पेश कर रहा है।

(लेखिका बांग्लादेश मामलों की शोध अध्येता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का उद्देश्य

प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से मिलने एक बार उनका एक अनुयायी उनके घर पर आया। दरवाजे पर दस्तक के बाद जब सुकरात अपने घर से बाहर निकले तो शिष्य ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह किया, मैं सुकरात के विचारों और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूं। क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? सुकरात थोड़ी देर के लिए शांत रहे और फिर बोले, सुकरात? आप किस सुकरात की बात कर रहे हैं? आज तक तो मैं खुद सुकरात को नहीं पहचान पाया हूं। माफ कीजिए मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा सकता हूं। सुकरात के दर्शन का मुरीद बेचारा याचक बड़ी निराशा के साथ वापस लौट गया।

सुकरात का उत्तर आसान था, किंतु उसके निहितार्थ काफी सारगर्भित हैं। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर गंभीरता से इस प्रश्न के उत्तर की तलाश करें कि क्या हम खुद को पहचान पाते हैं? प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, मानव जीवन में केवल दो ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब उसका जन्म होता है और दूसरा जब वह यह जान लेता है कि आखिर उसके जन्म का उद्देश्य क्या है, किंतु दुर्भाग्यवश जीवन धारण करने के बाद हम अपने जन्म के पवित्र उद्देश्यों को पूरी तरह से भूल जाते हैं और अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। यहां पर एक अहम प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है?

भौतिक सुख-सुविधाओं और बेशुमार धन-संपत्ति को बटोरने की अंधी चाहत में हम मानवता के दुख और उसके आंसू पोंछ नहीं पाते हैं। लोभ, तृष्णा, अहिंसा, असत्य वचन सरीखे अमानवीय कृत्यों में जीवन के जो अनमोल क्षण व्यर्थ होते हैं, वे जीवन को सच्चे उद्देश्यों से भटकाते हैं। दुखी और असहाय मानव के दुख और दर्द के आंसू पोंछकर उनके चेहरे पर खुशियां लाने की कोशिश ही सच्ची मानवता है। जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं और अपने जीवन के अर्थ पर विचार करना होगा।

श्रीप्रकाश शर्मा

खतरनाक होता सेल्फी का शौक

सुधीर कुमार

दुनियाभर में 2011 से 2017 तक 259 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसमें भारत सबसे आगे है

यूं तो सेल्फी का इतिहास करीबन पौने दो सौ साल पुराना है, लेकिन 21वीं सदी के मौजूदा दशक में इसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई है। माना जाता है कि दुनिया की पहली सेल्फी 1839 में अमेरिका के रॉबर्ट कोर्नेलियस नामक एक व्यक्ति ने ली थी। उन्होंने यह सेल्फी अपने कैमरे से ली थी और उस सेल्फी को लेने में उन्हें तीन मिनट लगे थे। आज स्मार्टफोन के जरिये चंद सेकेंड में सेल्फी लेना मुमकिन हो गया है। हालांकि संवेदनशील, खतरनाक और विपरीत परिस्थितियों में सेल्फी लेने का शौक एक नई मुसीबत बन कर सामने आई है!

दरअसल रोमांचक और विस्मयकारी सेल्फी लेने के लिए लोग कई तरह के बेवकूफी भरे प्रयोग करते रहते हैं। इससे कई बार दुर्घटना और मौत को असमय आमंत्रण मिल जाता है। आभासी दुनिया में लोकप्रियता हासिल करने का यह तरीका बहुत घातक साबित होता जा रहा है। चलती ट्रेन, झरना या डैम के किनारे, नदी या समुद्र में नहाते समय, चिड़ियाघर या सड़क पर सेल्फी लेने का शौक नासूर बन चुका है। सेल्फी लेते समय व्यक्ति का सारा ध्यान फोन पर केंद्रित हो जाता है और अच्छी से अच्छी सेल्फी लेने के चक्कर में लोग मौत की दहलीज पर पहुंच जाते हैं! इंडिया जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसीन एंड प्राइमरी केयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में 2011 से 2017 तक 259 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसमें 159 लोगों की मौत के आंकड़े के साथ भारत सबसे आगे है। इसी अवधि में अमेरिका में 23, रूस में 16, जबकि पाकिस्तान में केवल 11 लोगों की मौत हुई। सेल्फी के लिए मौत के मुंह में जानबूझकर जाना लापरवाही, आत्ममुग्धता और आभासी दुनिया के प्रति अतिरेक प्रेम की निशानी है। यह एक घातक प्रवृत्ति है, जिसे रोकना बेहद जरूरी हो गया है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि अगर किसी को दिनभर में तीन से ज्यादा सेल्फी लिए बिना मन नहीं भरता है तो वह एक डिसऑर्डर का शिकार है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में 'सेल्फाइटिस' कहा जाता है। अध्ययन के मुताबिक सेल्फाइटिस बीमारी के तीन स्तर होते हैं। पहला, दिन में 3 सेल्फी लेने की आदत होना, लेकिन सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट न करना। दूसरा, सेल्फी सोशल मीडिया में शेयर करना शुरू कर देना। तीसरा, हर समय अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश करना। ऐसे लोग दिन में कम से कम छह फोटो पोस्ट करते हैं। सेल्फी की लत के शिकार लोग किसी भी परिस्थिति में सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं, जिससे कई बार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है!

सेल्फी लेना सामान्य स्थिति है, परंतु यह ध्यान रहे कि अनुकूल परिस्थितियों में ही स्वयं की तस्वीरें ली जाएं। जिन स्थानों पर नो सेल्फी जोन का बोर्ड टंगा हो, वहां सेल्फी लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। खुद को मुसीबत में डालकर सेल्फी लेना अच्छी बात नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है। इसकी महत्ता हमें समझनी होगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

राष्ट्रहितैषी कानून का बेजा विरोध

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'नागरिकता कानून पर दुष्प्रचार' में पड़ोसी मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किए जाने वाले वहां के अल्पसंख्यक सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि गैर-मुस्लिम धर्मावलंबियों को मानवीय आधार पर भारत की नागरिकता देने संबंधी कानून के दुराग्रही विरोध को रेखांकित करते हुए इसे दुष्प्रचारित करने की जो बात की है, वह एकदम सही है। इस देश के मुट्ठी भर लोगों द्वारा निहित स्वार्थवश एक राष्ट्रहितैषी कानून का जिस तरह से बेजा विरोध किया जा रहा है वह न केवल उनके हिंदूविरोधी एजेंडे का एक हिस्सा है, अपितु इस कानून को वे मुस्लिम हितों के विपरीत प्रचारित कर इसके विरुद्ध एक संप्रदाय विशेष की भावनाओं को भड़काने का दुष्प्रयास भी कर रहे हैं। जबकि देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह कानून न तो किसी धर्म विशेष का पक्षधर है और न ही विरोधी, बल्कि विशुद्ध रूप से उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने वाला है जो अपने जीवन और धर्म दोनों की रक्षा के लिए भारत के अंदर शरणार्थियों का बेगैरत जीवन जीने को विवश हैं। इस देश में अवैध रूप से रहने वाले ऐसे उत्पीड़ित और मजबूर लोग ही नहीं हैं, अपितु वे घुसपैठिए भी हैं जो बेहतर जीवन जीने के लिए अवैध रूप से भारत में घुसकर यहां के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। मोदी सरकार नागरिकता कानून लागू करके ऐसे सभी घुसपैठियों को चिन्हित करना चाहती है जो देश के ऊपर किसी बोझ से कम नहीं हैं। आजाद भारत में पहली बार नागरिकता कानून के जरिये अवैध घुसपैठियों और मजबूर शरणार्थियों में अंतर करके भारत की जनसांख्यिकी को दुरुस्त करने का जो अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है, वह स्वागत योग्य है। ऐसे में किसी भी स्तर पर इस राष्ट्रहितैषी कानून का विरोध अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय हितों का विरोध है, जिसको समझने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

शरीर में प्लास्टिक

वर्तमान में मनुष्य के शरीर में निर्धारित मानक से 40 गुना ज्यादा प्लास्टिक का केमिकल पाया जा रहा है। कारण हमारे खान-पान में तमाम ऐसे तत्व हैं जो प्लास्टिक में पैक होकर व्यवहार में हमें उपलब्ध हैं, इसका दुष्परिणाम यह है कि शरीर में मानक से अधिक प्लास्टिक के केमिकल हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक की पैकिंग में आने वाला खाना, कोल्ड ड्रिंक, चाय, दूध, दही, मसाले, अचार, सब्जी आदि सैकड़ों ऐसी चीजें हैं, जो हमें प्लास्टिक के जार/थैलियों आदि में मिलती हैं। उस खाद्य पदार्थों को खाकर प्लास्टिक का केमिकल हमारे शरीर में पहुंच रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हर किसी को इसके खिलाफ जागरूक होना होगा।

pramodaggoldiee@gmail.com

मूल्य आधारित शिक्षा की जरूरत

तेलंगाना की पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या और उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश में उन्नाव की बेटी को जिंदा जलाकर मारे जाने से पूरे देश में आक्रोश फैला है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस तरह की निंदनीय घटनाएं कब तक होती रहेंगी? हमारे सामाजिक तंत्र के बुनियादी चरित्र में परिवर्तन तभी आ सकता है जब हम परिवार एवं समाज पर खुद का ध्यान केंद्रित करेंगे। महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते अनाचार से सिद्ध होता है कि हम अभी भी सभ्य समाज की परिकल्पना से कोसों दूर हैं। मौजूदा समाज में लगातार बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के लिए पूरी तरह से शासन व्यवस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक शिक्षित एवं मूल्य आधारित सामाजिक जीवन पद्धति के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को धर्मनिष्ठ बनाना पड़ेगा।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव, दिल्ली

सभ्य ढंग से हो आलोचना

राहुल गांधी के दुष्कर्म पर बयान को लेकर पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है। राहुल एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। इस तरह की बातें उनकी शख्सियत के अनुरूप नहीं हैं। इससे उनकी ही छवि को नुकसान हुआ है। सरकार तथा कानून-व्यवस्था की आलोचना सभ्य ढंग से की जाए तो अधिक असरदार होती हैं। उनको कुछ तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।

सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

23 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की आबादी थी पाकिस्तान में 1947 में, जो 2011 में 3.7 प्रतिशत पर आ गई। बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 प्रतिशत थी, जो 2011 में 7.8 प्रतिशत रह गई।

आजकल

संविधान से परे नहीं नागरिकता कानून

सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को नागरिकता संशोधन कानून में स्थान नहीं दिया गया है तो इससे संविधान की भावना को ठेस पहुंची है? देखा जाए तो उक्त देशों के मुस्लिम विशेष को नागरिकता देना या न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का मामला न होकर संविधान के भाग-2 में निहित अनुच्छेद 11 के अंतर्गत निर्मित नागरिकता कानून का मामला है जो केवल लोगों की नागरिकता को निर्धारित करता है, न कि उनके साथ भेदभाव को

प्रतीकात्मक

राष्ट्रपति की मुहर लगते ही नागरिकता (संशोधन) कानून-2019 अस्तित्व में आ गया है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी सुलभ हो जाएगी। हालांकि नागरिकता उन्हें ही मिलेगी जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हैं। स्पष्ट कर दें कि इस कानून को लेकर विपक्ष के अलावा जनमानस की भी राय बंटी हुई है। जिसका प्रमुख कारण मुस्लिमों को इससे अलग रखना है। कानून की खासियत यह है कि पहले नागरिकता हासिल करने के लिए भारत में रहने की अवधि 11 वर्ष थी अब इसे 5 साल कर दिया गया है। गौरतलब है कि नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इसमें उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया था जो बरसों पहले बिना वीजा, पासपोर्ट के भारत की सीमा में घुस आए हैं। ऐसे में इन्हें या तो जेल हो सकती है या वापस भेजा जा सकता है, लेकिन अब संशोधन के बाद कानून में मुस्लिमों को छोड़कर शेष धर्म के लोगों को छूट दे दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि भारत में वैध दस्तावेज के बगैर भी गैर मुस्लिम शरणार्थी पाए जाते हैं तो उन्हें न तो जेल भेजा जाएगा, न ही निर्वासित किया जाएगा, बल्कि उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इस मसले को लेकर विपक्ष का यह आरोप है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।

सवाल यह है कि क्या नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों से भेदभाव कर रहा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में साल 1976 में हुए 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। हालांकि इस शब्द के बगैर भी भारत धर्म के सापेक्ष कभी नहीं रहा। पूरे संविधान को पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जब संविधानविदों ने अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस बात को लेकर चर्चा की कि यदि आने वाले समय में इस स्वतंत्रता का लाभ लेकर कोई धार्मिक प्रचार-प्रसार आदि को महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? उन दिनों दृष्टिकोण यह उभरकर आया कि धर्म लोगों का निजी मामला है और इसे उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के भीतर अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा और यह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू है, जबकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कहता है और यह नागरिकों के साथ गैरनागरिकों को भी मिला है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को यदि इस कानून में स्थान नहीं दिया गया तो संविधान की भावना को ठेस पहुंची है? उक्त देशों के मुस्लिम विशेष को नागरिकता देना या न देना अनुच्छेद 14 का मामला न होकर संविधान के भाग 2 में निहित अनुच्छेद 11 के अंतर्गत निर्मित नागरिकता कानून का मामला है जो केवल नागरिकता को निर्धारित करता है, न कि भेदभाव को। इस कानून में इसके पहले पांच बार संशोधन हो चुके हैं। जाहिर है 2019 का यह संशोधन उसी का एक चरण है। नागरिकता प्राप्त किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ यदि भेदभाव होता तब संविधान का उल्लंघन है। और भारत के भीतर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तब संविधान का उल्लंघन है इसमें घुसपैठी अपवाद हैं। गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो यह कानून संविधान का कोई उल्लंघन करता नहीं दिखाई देता। हालांकि संविधान संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय का इस पर न्याय निर्णय क्या होगा यह बाद में पता चलेगा।

दो टूक यह भी है कि हिंदू समेत अन्य धर्मों को इस कानून में स्थान देना धर्मनिरपेक्षता का ही परिचायक है। रही बात मुसलमानों को शामिल नहीं करने की तो इसकी वजह को शोषण से जोड़कर देखा गया है। चूंकि तीनों देश इस्लामिक हैं, ऐसे में शोषण और प्रताड़ना मुसलमानों का नहीं अल्पसंख्यकों का हुआ है। ऐसे में कानून से उन्हें अलग करना किसी प्रकार का पक्षपात नहीं दिखाई देता। यह बात और पुख्ता तरीके से इसलिए कही जा सकती है, क्योंकि भारतीय मुसलमान नागरिकों को यह कानून कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस कानून पर बहस का तेज होना स्वाभाविक है। इसमें कोई दुविधा नहीं कि देश में नागरिक कौन है और कौन नहीं, इसका पता होना चाहिए। सरकार की यह दलील भी रही है कि यह नागरिकता देने का कानून है न कि छीनने का। ऐसे में संविधान को तनिक मात्र भी इससे नुकसान नहीं होता है। बावजूद इसके पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि एनआरसी के चलते 13 लाख हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलेगी जो उनकी रोजी, रोजगार से लेकर संस्कृति तक पर खतरा होंगे। हालांकि असम के कुछ क्षेत्र समेत इनर लाइन परमिट वाले राज्य इस कानून से अछूते रहेंगे। देखा जाए तो यह काल और परिस्थितियों के बदलावस्वरूप लिया गया एक फैसला है, जिसके चलते सरकार उन्हें नागरिक बनाने का प्रयास कर रही है जो उक्त देशों के गैरमुस्लिम हैं और आजादी से पहले वे भी भारत का हिस्सा थे। इस कानून से इस बात की भी पुष्टि होती है कि 1947 का शेष 2019 में पूरा किया जा रहा है।

बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी, पर असम के भीतर जो 6 लाख मुस्लिम हैं उनका क्या होगा? ऐसे सवाल पर एक कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत मानवता वाला देश है, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रश्न यह भी है कि जब नागरिकता कानून से लेकर एनआरसी तक की पहल से विपक्ष सहित कुछ वर्गों में भी असंतोष है तो आखिर सरकार जन साधारण के खिलाफ क्यों जाना चाहती है? पूर्वोत्तर के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बावजूद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार इतनी संजीदा क्यों रही? इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल में भाजपा को मिली चुनावी सफलता को भी एक कारण माना जा सकता है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर की 25 संसदीय सीटों में सहयोगियों सहित भाजपा ने 18 पर जीत दर्ज की है।

भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची में आने वाले पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों को इससे मुक्त रखा गया है, जबकि छठी अनुसूची के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। हालांकि इस नागरिकता कानून के चलते भारत की आबादी पर भी प्रभाव पड़ेगा। तीन पड़ोसी देशों से करीब 32 हजार लोग भारत में लंबी वीजा अवधि पर रह रहे हैं जिन्हें तुरंत फायदा होगा। इसमें 25 हजार हिंदू, 58 सौ सिख, 55 ईसाई, दो बौद्ध, दो पारसी शामिल हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के कुछ समाचारपत्र भारत की पंथनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहे हैं जिसे बेबुनियाद करार दिया जाना चाहिए।

द्विराष्ट्र सिद्धांत बनाम नागरिकता

डॉ. निशांत रंजन

लगातार दो विश्व युद्धों में भागीदारी के चलते आर्थिक रूप से कमजोर पड़े अंग्रेजों ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के मात्र दो वर्षों के भीतर अपनी अधिकतर कॉलोनियों को आजाद कर दिया था। इसी कड़ी में भारत भी अंततः 1947 में आजाद हुआ। इसलिए भारत की आजादी का प्रमुख श्रेय दोनों विश्व युद्धों को जाता है, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़ दी थी, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जितनी भी कॉलोनियां थीं, उनमें से भारत की आजादी मानवनिर्मित त्रासदी बना दी गई। मजहब के आधार पर भारत माता के दो टुकड़े कर दिए गए। लाखों लोग मरे, लाखों बेघर हुए, हजारों बहन-बेटियों की अस्मत लुट गई। लाशों के ढेर पर मुसलमानों के लिए अलग देश-इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। मानो हिंदू और मुस्लिम किसी नदी के दो किनारे की तरह हैं, जो आपस में मिल कर नहीं रह सकते! इसे ही टू नेशन थ्योरी (द्विराष्ट्र सिद्धांत) के नाम से जाना जाता है।

इसके बाद झूठे इतिहास लेखन का दौर चला। भारत की आजादी के आसपास जितनी भी अप्रिय घटनाएं हुईं, उन्हें हिंदू महासभा, आरएसएस, वीर सावरकर इत्यादि के मत्थे मढ़ कर उस वक्त की दोनों प्रमुख शक्तियों-कांग्रेस और मुस्लिम लीग-को क्लीन चिट दे दिया गया। ये दोनों शक्तियां प्रभावशाली थीं, क्योंकि उनके पास मजहब के आधार पर लोगों का समर्थन प्राप्त था। हिंदू महासभा हाशिये पर और अलग-थलग पड़ा एक गुमनाम संगठन था, जिसके समर्थक अत्यंत ही सीमित थे। देश के 90 प्रतिशत मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ थे, लेकिन 95 प्रतिशत हिंदू हिंदू महासभा के साथ न होकर, कांग्रेस पार्टी के साथ थे!

टू नेशन थ्योरी सर्वप्रथम सर सैयद अहमद खान ने 1867 में हिंदी-उर्दू विवाद के बाद दिया था जो कालांतर में विभाजन का कारण बना। 1931 में मोहम्मद इकबाल ने इस सिद्धांत की पैरवी करते हुए इलाहाबाद की एक आमसभा में भारत के उत्तरी-पश्चिमी इलाके को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की, लेकिन इस देश के कुछ लोगों की जमात ने 1935 में वीर सावरकर पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी।

आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी में लगातार कमी आई है। पाकिस्तान में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 प्रतिशत थी, 2011 में यह 3.7 प्रतिशत पर आ गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 प्रतिशत थी, जो 2011 में 7.8 प्रतिशत हो गई। आखिर कहां गए ये लोग?

दूसरी ओर भारत के मुसलमानों ने जब मजहब के आधार पर और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर भारत को छोड़ कर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपना मुल्क चुन लिया तो भारत स्वाभाविक रूप से मुसलमानों का देश नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन मुसलमानों ने टू नेशन थ्योरी को नकार कर इस देश में ही रहना पसंद किया, उन्हें भारत ने खुले दिल से स्वीकारा है। भारत में रह गए मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1951 में मुस्लिम 9.8 प्रतिशत थे, आज 14.23 प्रतिशत हैं। यह बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को विकास के लिए बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक अवसर मिले हैं, लेकिन जिन मुसलमानों ने टू नेशन थ्योरी को स्वीकार कर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहना स्वीकार किया, उनके लिए अब भारत की नागरिकता के सवाल पर हमारे देश में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वे अपने-अपने इस्लामिक मुल्कों में खुश रहें, आगे बढ़ें।

(सचिव, आइएमए, बेगूसराय, बिहार)

खरी-खरी

कांदे के वांदे में हो गए घांदे!

संदीप देव

वे दिन अब इतिहास हुए जा रहे, जब गरीब को भूख लगती थी तो वह सूखी रोटी के साथ प्याज खाकर भूख शांत कर लेता था। अब तो वह दौर है जब प्याज से भूख शांत नहीं होती, बल्कि देश अशांत हो जाता है। प्याज ने बड़ी खामोशी से अपना किरदार बदल लिया है। वह अब गरीब की मजबूरी से अमीर की लग्जरी हो गया है। प्याज, अब प्याज भी न रहा, वह 'ऑनियन' हो चला है। कांदा नाम का चोला तो खैर उसने तभी उतार फेंका था, जब उसने एक सरकार ही उखाड़ फेंकी थी। बहरहाल देखिए कि क्या दिन आ गए हैं। सोना, चांदी, रुपया-पैसा, दिल, 2जी और कोयला लूट लेने के समाचार अब बासी हुए, अब तो ब्रेकिंग न्यूज यह है कि लुटेरों ने प्याज की बोरियां लूट ली। समझ नी आता, इस समाचार पर हंसे या रोएं? रोना ही पड़ेगा, क्योंकि काटने पर रुलाने वाला प्याज, अब बिन कटे ही रुला रहा है। वैसे भी ये उसे बोने और उगाने वालों को तो दशकों से रुला ही रहा है। हंसने का अवसर बस उन 'आला-बाजारियों' के पास है, जो इसकी 'कालाबाजारियां' कर रहे हैं।

बीते बरस तक किसान अपने ही खेत में उगे कांदे को, अपने ही हाथों से उखाड़कर सड़क पर फेंक आते थे। आती-जाती दुष्ट लग्जरी गाड़ियां उन्हें कुचलकर ऐसे निकलतीं जैसे देश में 'हिट एंड रन' के केस में बरी होने की गारंटी हो। मगर आज कुचले हुए उसी प्याज की बद्दुआ फेंकने वाले को भी लगी है और लग्जरी गाड़ियों को भी। फेंकने वाली बैलगाड़ियां एवं कुचलने वाली लग्जरी गाड़ियां तक, सब प्याज के लिए यहां-वहां भटक रही हैं।

अब बाजार में प्याज देख मन ललचा जाता है। सोचता है, आज प्याज के पकौड़े बनाएं, पराठे बनाएं, मगर पर्स मना कर देता है। कहता है-अपनी औकात देख और प्याज की औकात देख। इसे तू लेगा तो मैं लुट जाऊंगा, तू कंगाल हो जाएगा। कल का डेढ़ कौड़ी का, मुंह लगा प्याज आज हमें ही दो कौड़ी का साबित करके मुंह चिढ़ा रहा है। कल तक आंगन में यूं ही 'रड़बड़ता' कांदा, आज 'स्पेशल ऑनियन विथ गार्लिक पेस्ट इन इटैलियन डिश' होकर माथे पर बैठ रहा है! अजीब बात है कि देश की सरकार भी इटैलियन सम्मान पाकर इठला रहे प्याज का ताज नहीं उतार पा रही, जबकि ऐसे ताज उतारने का उसे अभ्यास है।

ट्वीट-ट्वीट

देश के प्रधानमंत्री हैं वो, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन पीएम की तस्वीर पर भद्दी टिप्पणी करना, हा हा ही ही करके मजाक बनाना बताता है किस हद का मानसिक दिवालियापन है। एक बार फिर साबित कर दिया कि परेशानी मोदी से है मुद्दों से नहीं।

रूबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

अब जबकि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अभयदान दे दिया है तब क्या जदयू अपनी दिल्ली इकाई भंग करेगा? यह कैसे हो सकता कि पार्टी की दिल्ली इकाई केजरीवाल सरकार को हटाने का अभियान चलाए और जदयू नेता प्रशांत किशोर उसी सरकार की वापसी की रणनीति बनाएं।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हृदयविदारक हैं। यह सूबा मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। प्रदर्शनकारियों को सोचना चाहिए कि विरोध जताने के और भी तरीके हैं। उन्हें सार्वजनिक संपत्ति और देश के अन्य नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
समाचार संपादक, पानीपत

हरियाणा डायरी

मनोहर के गृह मंत्री की भूमिका में गब्बर विज

गब्बर के नाम से चर्चित अनिल विज को मनो-टू सरकार में छवि के अनुरूप गृह मंत्री की भूमिका मिल गई। अब वह एक्शन मोड में भी हैं। प्रदेश में लंबे समय से गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रख रहे थे। इससे पहले 1996 में चौ. बंसीलाल ने अपने विश्वासपात्र मनीराम गोदारा को गृह मंत्रालय सौंपा था। सत्तारूढ़ दल में विधायक के रूप में सर्वाधिक अनुभव वाले विज पर सख्ती की जिम्मेदारी दिख रही है जिनसे विपक्ष के नेता पहले ही विचलित होते रहे हैं। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने तथा जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपे जाने के बाद विज को दी गई जिम्मेदारियां सरकार की कार्यनीति का संदेश देने में कामयाब रहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पता है कि जो किसी से नहीं सधे उसे विज साध देते हैं। उनके साथ तो डॉ. अशोक खेमका जैसे आइएएस अधिकारी भी शांति से काम कर लेते हैं। पिछली सरकार में स्वास्थ्य और खेल विभाग में निर्णयों के कारण विज स्पष्ट विजन वाले नेता के रूप में छवि बनाने में कामयाब रहे। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तालमेल के कुछ सवाल भी उठते थे। सत्ता में दोबारा वापसी के बाद विज में भी बदलाव दिख रहा है।

अनिल विज को मनोहर लाल ने गृह मंत्रालय के साथ ही स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य सहित सात विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इस तरह 18 विभागों वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 10 विभागों वाले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बाद वह सरकार में तीसरे नंबर के मंत्री हैं। दूसरी तरफ कार्रवाई की दृष्टि से देखें तो लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित कर जांच बैठाने में नंबर एक का दर्जा दिया जा सकता है। उनके पास प्रतिदिन 400 से अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं। विज भी भरोसा दे रहे हैं कि शिकायतकर्ता संतुष्ट होंगे, उन्हें इंसाफ मिलेगा। पानीपत-करनाल से लेकर गुड़गांव-फरीदाबाद तक में कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने पुलिस अफसरों की कुंडली के साथ-साथ अनसुलझे केसों की फाइलें भी तलब कर ली हैं। उधर नगर निगमों में अलग ही खौफ है। बचाव के लिए शरण में आने वालों को मनोहर मुस्कुराहट के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भरोसा नहीं मिलना फिलहाल गब्बर को और पावरफुल बना रहा है।

एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (दाएं) के साथ अनिल विज (बाएं)। फाइल फोटो

पानीपत पर पानीपत : तीन युद्धों के लिए चर्चित पानीपत का नाम अगर संघर्ष का पर्याय है तो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत पर एक बार फिर उत्तरी भारत में पानीपत हो गया है। वैसे महाराष्ट्र के लोग पानीपत शब्द का प्रयोग सत्यानाश के लिए करते हैं। जैसे, जा तेरा पानीपत हो जाए। फिल्म में दिखाए गए भरतपुर के महाराजा सूरजमल के चरित्र ने पानीपत को चर्चा में ला दिया है। उन्हें लोभी दिखाया गया है जो मराठा पेशवा सदाशिव राव से इमाद को दिल्ली का वजीर बनाने और अपने लिए आगरा के किले की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के जाटों के साथ-साथ हरियाणा के जाटों में इस चरित्र चित्रण पर उबाल है। परिणामतः फ्लाप हो रही फिल्म चर्चा में आ गई है। धरना-प्रदर्शन और ज्ञापनों के कारण हरियाणा के सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लग गई है। उधर मध्य प्रदेश के बांदा में बाजीराव मस्तानी के वंशज सदाब बहादुर भी अपने पूर्वज शमशेर बहादुर को जंग की जगह शायर की पोशाक में दिखाए जाने से खफा हैं। युद्ध के बाद हरियाणा में रह रहे मराठाओं का जिक्र नहीं है। फिल्म पानीपत में युद्धभूमि पानीपत का कहीं भला होता नजर भी नहीं आ रहा। न यहां शूटिंग हुई और न ही यहां के ऐतिहासिक स्थलों को ही फिल्म में देश-दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया गया है।

तीन पीढ़ियों का विवाद : यमुना आर और पार का संघर्ष हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के तालमेल से समापन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष फरवरी-मार्च तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल और योगी आदित्यनाथ मिल-बैठकर 9265 एकड़ जमीन के बंटवारे का सही रास्ता निकाल लेंगे। वैसे यह विवाद 1966 से चलता आ रहा है, परंतु नदी की धारा बदलने के साथ विवाद और गहराता रहा है। अवैध खनन ने खूनी संघर्षों को और बढ़ावा दिया। 1974 में सर्वे के बाद अरबों-खरबों एमएलडी पानी यमुना में बह चुका है। हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिले यमुना नदी के एक तरफ हैं दो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बागपत, शामली और गाजियाबद जिले हैं। नदी किनारे 146 गांवों के लोगों के बीच जमीन के लिए पिछले 44 वर्षों में लगभग 1400 झड़पों के दो हजार से अधिक केस अदालतों में लंबित हैं। उम्मीद की जा सकती है कि दोनों प्रदेशों की भाजपा सरकारें तीन पीढ़ियों से चले आ रहे विवाद के स्थाई समाधान में सफल रहेंगी। हरियाणा के हिस्से में 5643 एकड़ जमीन आनी है। इसके लिए माफिया के खिलाफ विशेष सख्ती दिखानी होगी।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या बोरिस जॉनसन की जीत से भारत-ब्रिटेन संबंध और मजबूत होंगे?

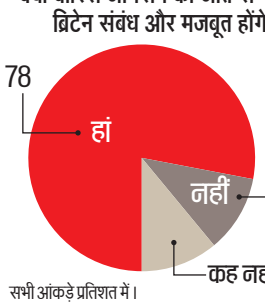

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या प्रशांत किशोर के साथ आने से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ऐसे ही यदि देश में लगा करेगी आग,
फिर तो पाले बैठिए आस्तीन में नाग।
आस्तीन में नाग पालकर दूध पिलाओ,
फिर तो दुख के गीत रात-दिन घर में गाओ।
एक बहाना ढूंढ आग लगती है कैसे,
सोचो कैसे देश बढ़ेगा आगे ऐसे!!

-ओमप्रकाश तिवारी

आधी आबादी की सुरक्षा

'निर्भया' के सात साल बाद

अपनी बेटियों को संभालने, उन्हें बचाने के लिए जहां समाज ने अब भी खास सीख हासिल नहीं की है, वहीं राजव्यवस्था राजनीति ही करती नजर आ रही है

उमेश चतुर्वेदी
स्वतंत्र पत्रकार

मशहूर अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपमैन का एक कथन है, 'दुनिया जैसी है, वैसी ही रहेगी, चलती रहेगी।' भारतीय परंपरा में नियतिवादी विचार दर्शन भी रहा है। निर्भया कांड की जब-जब बरसी आती है, पश्चिम के पत्रकार के विचार हों या सदियों पुराने भारतीय दार्शनिक विचार, दोनों पर आस्था बढ़ जाती है। दिसंबर 2012 में वीभत्स और शर्मनाक घटना से क्षोभ और गुस्से में आए देश ने न जाने कितनी प्रतिज्ञाएं की थीं। भविष्य में कोई लाली किसी कुत्सित और नापाक हाथ का शिकार न बने, इसके लिए राज और समाज-दोनों ही ओर से तमाम वायदे किए गए थे, लेकिन सात साल बीतने के बावजूद जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उससे साफ है कि समाज की सोच और राजव्यवस्था के तंत्र में खास बदलाव नहीं हुआ है।

निर्भया कांड के बाद पूरे देश में लोग सड़कों पर निकल आए थे। आम जनता के स्वतः स्फूर्त गुस्से और क्षोभ की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के बाद माना गया था कि समाज में महिला सुरक्षा को लेकर चेतना जागेगी, लेकिन हालात बहुत बदले नजर नहीं आ रहे। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर बीस मिनट में एक बेटी के साथ हैवानियत हो रही है। हाल ही में तेलंगाना की एक पशु चिकित्सक और उन्नाव की एक बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, साफ है कि सामाजिक स्तर पर जो बदलाव होने चाहिए थे, वे नहीं हो पाए हैं। उन्नाव की घटना की आंच भी थमी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर में एक लड़की के दुष्कर्मी ने उसे जला दिया। निर्भया और तेलंगाना की पशु चिकित्सक के दुष्कर्मी जहां अजनबी थे, वहीं उन्नाव और फतेहपुर की लड़कियों से वीभत्सता करने वाले जान-पहचान और रिश्ते वाले थे। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, राजव्यवस्था पर सवाल सबसे ज्यादा उठते हैं। उठने भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि रिश्तों को ही जब तार-तार करने वाले लोग समाज के भीतर ही तमाम तरह के पर्देदारी के भीतर बने हुए हैं, तब उनकी कुत्सित मानसिकता से राजव्यवस्था किस तरह पार पा सकती है। इसके लिए राजव्यवस्था के बजाय समाज को ही अपने भीतर माकूल इंतजाम करने के बारे में सोचना चाहिए।

सामाजिक सुधार की प्रक्रिया चूंकि सोच आधारित है, लिहाजा इसके चलते तात्कालिक परिवर्तन नहीं हो सकता। यहीं पर राजव्यवस्था की याद आती है। वह अपने फौरी और प्रभावी कदमों से सामाजिक अपराधियों और कुत्सित विचारधारा वाले लोगों पर लगाम लगा सकती है। इसके तहत राजव्यवस्था दो तरह के कदम उठा सकती है। उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कुत्सित घटनाएं होने ही न दें। कम से कम तंत्र की ओर से ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि अपराधियों को मौका ही नहीं मिले और जिनके पीड़ित होने की आशंका हो वे मजबूत सोच के साथ उनका मुकाबला कर सकें, ताकि कोई अपराधी अपनी कुत्सित सोच को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत ही न दिखा सके। वहीं अगर अपराधी अपने नापाक कार्य में सफल ही हो गया है तो राजव्यवस्था न्याय तंत्र की सहायता से फौरी कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को सजा के अंजाम तक पहुंचा सके। निर्भया कांड के ही अपराधियों को अभी तक न्यायिक व्यवस्था की पेचों के चलते फांसी पर भी नहीं चढ़ाया जा सका है। एक दोषी की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।

निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की घोषणा की थी। इस निधि से राज्यों को आपातकालीन रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, दुष्कर्म आदि की शिकार महिलाओं को मुआवजा देने का इंतजाम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम की व्यवस्था, वन स्टॉप योजना के साथ महिला पुलिस स्वयंसेवक की तैनाती करनी थी, लेकिन हकीकत यह है कि राज्यों ने इस निधि से मिली रकम को खर्च करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई है। 29 नवंबर को संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के अलावा दमन एवं दीव की सरकारों ने केंद्र द्वारा दिए निर्भया फंड से एक भी पैसे खर्च नहीं किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश ने 119 करोड़ रुपये में से सिर्फ छह करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी तरह तेलंगाना ने 103 करोड़ रुपये में से केवल चार करोड़ खर्च किए हैं, जबकि उसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने 21 करोड़ में से 12 करोड़ बचाए हैं। यही हालत बिहार की भी रही, जिसने आवंटित 22 करोड़ में से सिर्फ छह करोड़ ही खर्च किए हैं। निर्भया फंड के तहत राज्यों को महिला हेल्पलाइन भी बनाने थे, लेकिन सिर्फ 20 राज्यों ने ही महिला हेल्पलाइन बनाने में पैसे खर्च किए हैं। हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों को महिला हेल्पलाइन के लिए दिए पैसे वैसे ही बचे हुए हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी इस मद में मिले 50 लाख रुपये में से एक भी पैसे खर्च नहीं किए हैं।

प्रतीकात्मक

जाहिर है कि अपनी बेटियों को संभालने, उन्हें बचाने के लिए जहां अब भी समाज ने खास सीख हासिल नहीं की है, वहीं राजव्यवस्था राजनीति ही करती नजर आ रही है। यानी हमारी बेटियां नियतिवादी दर्शन के ही सहारे जी रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि पांच खरब की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में जुटा देश किन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है?

बीईएमएल में सरकार बेचेगी 28 परसेंट हिस्सेदारी

कोलकाता, प्रेट्र : सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश के क्रम में केंद्र सरकार बीईएमएल में 28 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस समय बीईएमएल में सरकार की हिस्सेदारी 54 .03 परसेंट है। सूत्रों के मुताबिक बीईएमएल को किसी अन्य सरकारी कंपनी से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस विनिवेश योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बीईएमएल मुख्य रूप से खदानों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण बनाती है।

प्रमुख भारतीय इक्विटी बाजार फ्री फ्लोट शेयरों के मामले में काफी पीछे हैं। फ्री-फ्लोट शेयरों से विदेशी निवेशक भी आकर्षित होते हैं। यह भारतीय बाजारों के विकास के लिए जरूरी पहलू है।

— विक्रम लिमये, एनएसई के सीईओ व एमडी

सीजी पावर के गौतम थापर ने नकारा धन के दुरुपयोग का आरोप

मुंबई, प्रेट्र : सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के गैर कार्यकारी चेयरमैन गौतम थापर ने धन के दुरुपयोग के आरोपों से इन्कार किया है। साथ ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी को कर्ज के लिए निदेशक मंडल की मंजूरियों का हवाला दिया है। थापर ने सरकार को दस्तावेज सौंप खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है।

कॉरपोरेट मंत्रालय को नवंबर की शुरुआत में थापर ने 36 पेजों का दस्तावेज सौंपा है। इनमें कंपनी से कंपनी को कर्ज, बोर्ड बैठकों और स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिंगापुर और येस बैंक से मिले कर्ज का ब्योरा है। थापर को 30 अगस्त को पद से हटा दिया गया था। वैश्य एसोसिएट्स की ऑडिट रिपोर्ट के बाद बोर्ड ने थापर पर यह कार्रवाई की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि थापर ने सीजी पावर से 3,000 करोड़ की गड़बड़ी की है। सेबी ने थापर और उनसे संबंधित संस्थाओं पर तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गंभीर अपराध जांच कार्यालय ने भी सीजी पावर और इससे जुड़े 15 संस्थानों के खिलाफ जांच शुरू की है। इसमें सोमवार को फैसला आ सकता है।

हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा नाबार्ड

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए शुरू करने होंगे नए उद्यम

कृषि क्षेत्र को मुश्किल दौर से उबारने के साथ उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नाबार्ड हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला ने कहा कि नई पीढ़ी खेती से नहीं जुड़ना चाहती हैं, जिसके लिए कुछ नए उद्यम शुरू किए जा सकते हैं। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बहुत मददगार साबित हो सकता है। 'जागरण' से बातचीत में नाबार्ड चेयरमैन ने कहा 'जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समान क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को एकजुट होना होगा।'

भानवाला ने कहा 'कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यम को कामयाब बनाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ धन बहुत मायने रखता है, जो नाबार्ड कर सकता है।' एक लक्ष्य और समान दिशा में काम करने वाले सभी संस्थानों को साझा तौर पर काम करना होगा, जिससे कारगर तौर पर जल्दी सफलता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि देश में 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हैं, जिन्हें नाबार्ड से फंडिंग होती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को तो बिना गारंटी के ही लोन मिल जाता है। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में इनका और सही उपयोग किया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियों में किसानों की छोटी जोत पर भानवाला ने कहा, 'देश में फिलहाल 12 करोड़ लघु व सीमांत किसान हैं। छोटी जोत वाले इन किसानों को बड़ा बनाने के लिए ही फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (एफपीओ) की शुरुआत की गई है।' देश में फिलहाल 3,500-4,000 एफपीओ बन चुके हैं, जिन्हें नाबार्ड की ओर वित्तीय मदद दी जा रही है। प्रत्येक एफपीओ को 20-30 लाख रुपये दिये जा रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना संभव हो पा रहा है। भानवाला का कहना था कि ग्रामीण विकास की दिशा में आदिवासी विकास फंड का गठन किया गया है, जिसका उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में फलदार वृक्ष लगाने में किया जा रहा है। नाबार्ड फिलहाल 400 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर काम कर रहा है।'

समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को करना होगा साझा प्रयास

वाटरशेड कार्यक्रम में उनका संगठन प्रायोगिक परियोजना चला रहा है। नाबार्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, ताकि छोटे किसानों को खेती से लाभ मिल सके। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का महत्व आगे और बढ़ेगा। बेमौसम भारी बारिश से कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान होने लगा है। कृषि उपज पर उलटा असर हो रहा है। खेती की इस कठिनाई से निपटने में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और आधुनिक प्रौद्योगिकी लाभप्रद हो सकती है। नाबार्ड कृषि प्रसार के क्षेत्र में बहुत पहले से कार्य कर रहा है। किसानों में जागरूकता के लिए प्रसार से काफी सहायता मिलेगी।

भानवाला के मुताबिक नाबार्ड सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर कार्य कर रहा है। किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए आइसीएआर का साथ लेना चाहते हैं, जिसके लिए वह भी तैयार है। कृषि प्रौद्योगिकी क्रांति आइसीएआर की अहम भूमिका है। उन्होंने माना कि खेती के लाभ में आने के बाद ही युवा इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए नए आविष्कार की जरूरत होगी, जो देश के कृषि संस्थानों के पास हैं। अच्छी प्रजाति के बीज, मिट्टी की सेहत में सुधार, सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं, मौसम की मार से बचाने के तरीके, रोगों से बचाव को क्रॉप प्रोटेक्शन की तकनीक, उपज की प्रोसेसिंग व बाजार में बिक्री के तरीके जैसे क्षेत्रों में नाबार्ड आइसीएआर के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाएगा।

विंटेज वाहनों के संरक्षण के लिए नियम लाएगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : विंटेज वाहनों के संरक्षण के लिए सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। यह नियम इस तरह के वाहनों को कबाड़ की श्रेणी से अलग करेंगे। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है। इसमें 50 वर्ष या इससे पुराने वाहनों के लिए विशेष नंबर प्लेट जारी किए जाने का प्रस्ताव है। इन नियमों के बाद विंटेज वाहनों को आसानी से सड़क पर उतारा जा सकेगा। हालांकि इस तरह के वाहनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

विंटेज वाहनों के पंजीकरण के बाद इन्हें परिवहन विभाग एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट जारी करेगा, जिसमें अंग्रेजी के 'वीए' अक्षरों को शामिल किया जाएगा। इस तरह से वाहनों के पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इन वाहनों की नंबर प्लेट उच्च सुरक्षा मानकों पर आधारित होगी। इसे अंकों और अक्षरों से मिलाकर बनाया जाएगा। इसमें अंग्रेजी के वी-ए अक्षरों को जगह दी जाएगी, जो इसकी विंटेज पहचान को जाहिर करेंगे। नंबर प्लेट की शुरुआत के दो अक्षर राज्य की पहचान और अंत के दो अंक वाहन की पंजीकरण संख्या बताएंगे।

इन वाहनों के लिए विशेष नंबर प्लेट जारी किए जाने का है प्रस्ताव

मंत्रालय ने इस मसौदे पर आम लोगों और साझेदारों से सलाह मांगे हैं। फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद विंटेज वाहनों के शौकीन लोगों को नियामकों और इससे संबंधित लोगों द्वारा संभावित प्रताड़ना से भी मुक्ति मिल सकेगी। गौरतलब है कि सरकार ने इस तरह के वाहनों को रैली में शामिल होने की अनुमति दे रखी है। विंटेज वाहन बिना पंजीकरण या नंबर प्लेट के ही रैली में हिस्सा ले सकते हैं।

स्थिर बाजार के लिए ज्यादा फ्री-फ्लोट शेयर जरूरी

- एनएसई के सीईओ ने कहा, अफवाहों के कारण बाजार में घबराहट का माहौल
- फ्री फ्लोट में भारतीय बाजार वैश्विक समकक्षों की तुलना में काफी पीछे

एनएसई बिल्डिंग। फाइल फोटो

मुंबई, आइएएनएस : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सीईओ व एमडी विक्रम लिमये ने कहा है कि बाजार की स्थिति सुधारने व अस्थिरता रोकने के लिए और अधिक फ्री-फ्लोट शेयरों की जरूरत है। फ्री-फ्लोट शेयर किसी कंपनी के सार्वजनिक स्वामित्व को दर्शाते हैं। ये बाजार को मजबूती प्रदान करने के साथ ही लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करते हैं। इनके न होने या कम होने से छोटे शेयरधारकों को नुकसान उठाना पड़ता है। पहले से ही सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण बाजार में घबराहट का माहौल है।

लिमये ने कहा कि उद्योगों के आंकड़ों से पता चला है कि प्रमुख भारतीय इक्विटी बाजार अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में फ्री फ्लोट शेयरों के मामले में काफी पीछे है। फ्री-फ्लोट शेयर से विदेशी निवेशक भी आकर्षित होते हैं। यह भारतीय बाजारों के विकास का जरूरी पहलू है। यह विकास और निवेश के लिए जरूरी पूंजी मुहैया कराने में अहम भूमिका भी निभाता है। मौजूदा समय में निफ्टी का सूचकांक फ्री फ्लोट शेयर के बाजार में 66-67 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस समय ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां निवेशक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। गौरतलब है कि फ्री फ्लोट शेयर किसी कंपनी के शेयरों का वह हिस्सा है, जो बाजारों में खरीद-फरोख्त के लिए उपलब्ध होता है।

छोटे और मध्यम उद्योगों (एसएमई) की बाजार में पहुंच बढ़ाने के संदर्भ में लिमये ने कहा कि एनएसई इसके लिए मजबूत ढांचा तैयार कर सकता है। एसएमई अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने के भी साधन हैं। एसएमई की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एनएसई उद्यमियों को भी जागरूक बना रहा है।

लिमये का कहना था कि इस वर्ष अब तक 200 कंपनियों ने एनएसई एमर्ज प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है, और करीब 22 कंपनियां इसमें से निकलकर एनएसई के मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध हुई हैं। इस दौरान छोटे शहरों के निवेशकों की इक्विटी मार्केट में दिलचस्पी खासी बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु के निवेशक एनएसई को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इस वर्ष दिखा है कि राजकोट, वडोदरा, लखनऊ और नागपुर से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं। लिमये के मुताबिक एनएसई में निवेशकों की संख्या के लिहाज से शीर्ष 10 से बाहर के शहरों की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

बजट में घरेलू मांग बढ़ाने पर रहेगा जोर

तैयारी ▸ उद्योग जगत व अर्थविदों से सुझाव आने शुरू, पहली फरवरी को पेश होगा आम बजट

पर्सनल इनकम टैक्स की छूट को पांच लाख किए जाने की जबरदस्त मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदमों की लगाई जा रही उम्मीद। प्रतीकात्मक फोटो

अर्थव्यवस्था पर गहराती मंदी के संकेतों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से आगामी बजट की तैयारियों की विधिवत शुरुआत कर देंगी। यह शुरुआत विभिन्न सेक्टरों के विशेषज्ञों व प्रतिनिधियों के साथ विमर्श व उनकी समस्याओं के सुनने के साथ होगी। पहले दिन वित्त मंत्री स्टार्ट-अप के प्रतिनिधियों के साथ ही देश में डिजिटल पेमेंट व फाइनेंशियल तकनीक से जुड़ी कंपनियों के प्रतिधिनियों से विमर्श करेंगी।

सोमवार को ही वित्त मंत्री की पूंजी बाजार नियामकों व वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक होगी। अगले कुछ दिनों के दौरान वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, कृषि क्षेत्र के जानकारों व वैज्ञानिकों, श्रम संगठनों, ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों व अर्थशास्त्रियों के साथ अलग-अलग मुलाकात करेंगी। ज्यादातर जानकार व विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण की तरफ से पेश होने वाले दूसरे बजट में घरेलू मांग को बढ़ाना पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा। वैसे, इस बार पहले से ही कुछ उद्योग संगठनों, एजेंसियों और अर्थविदों की तरफ से आगामी बजट को लेकर सुझाव देने का सिलसिला शुरू हो गया है। उद्योग जगत की तरफ से जो सुझाव वित्त मंत्रालय को मिले हैं उनमें अधिकांश ने घरेलू मांग को बढ़ावा देने की सबसे ज्यादा जरूरत बताई है। अग्रणी उद्योग चैंबर फिक्की ने कॉरपोरेट टैक्स की दर में हाल ही में की गई कटौती का स्वागत किया है। लेकिन चैंबर ने यह भी कहा कि आम जनता की जेब में भी खर्च लायक रकम बढ़ाया जाना जरूरी है और इसके लिए व्यक्तिगत कर की दरों को नए माहौल के मुताबिक बनाना होगा। फिक्की का सुझाव है कि आयकर की छूट सीमा को मौजूदा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का कदम बहुत उपयोगी साबित होगा। 10 से 20 लाख रुपये आय-वर्ग पर टैक्स की दर को 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 प्रतिशत निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। अभी 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले वर्ग को 30 प्रतिशत की दर से आयकर देना पड़ता है। एक अन्य उद्योग चैंबर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी पांच लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को आयकर से पूरी तरह से छूट देने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने खुद भी आयकर में कटौती के ठोस संकेत दिए हैं।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कुछ आर्थिक थिंक टैंक व संस्थानों की तरफ से भी आम बजट मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है जिसमें घरेलू मांग को बढ़ाने को लेकर काफी विस्तार से चर्चा की गई है। इस महीने में अभी तक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो सूचनाएं आई हैं उससे भी यह बात साबित हो रही है कि घरेलू मांग बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने ब्याज दरों को घटाने में काफी मदद की है। लेकिन महंगाई दर पिछले तीन महीनों के उच्च स्तर पर जाते ही बैंक ने रेपो रेट में कटौती का सिलसिला तोड़ दिया है। ऐसे में आम जनता के हाथ में खर्च करने योग्य अतिरिक्त राशि पहुंचाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से ही करनी होगी। पर्सनल टैक्स में राहत इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। पिछले गुरुवार को सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया कि अक्टूबर में देश के औद्योगिक उत्पादन में 3.34 प्रतिशत की गिरावट हुई है। जबकि इसी महीने खुदरा महंगाई की दर 5.54 प्रतिशत हो गई है।

इस महीने के अंत तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयकर विभाग ने कहा है कि इस महीने के अंत तक पैन को आधार से लिंक करना ही होगा। रविवार को आइटी विभाग की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि बेहतर कल के निर्माण और बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवाएं पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करें।

इस संदेश में साफतौर पर कहा गया है कि दी गई समय-सीमा के भीतर यह लिंकिंग प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने लिंकिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी। आयकर विभाग के लिए नीति-निर्माण का काम सीबीडीटी ही करता है।

गौरतलब है कि लंबे गतिरोध के बाद पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संविधान-सम्मत ठहराया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कहा था कि आयकर रिटर्न भरने और पैन आवंटन में बायोमीट्रिक पहचान की अनिवार्यता बनी रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आधार कार्डधारक करदाताओं को इसे पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य है। आधार कार्ड यूआइडीएआइ द्वारा भारतीय निवासियों को जारी किया जाने वाला बायोमीट्रिक पहचान पत्र है, जबकि पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

राज्यों पर बिजली खरीद का 67 हजार करोड़ से ज्यादा बकाया

रायपुर, नईदुनिया

बिजली मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर तक के हिसाब से राज्यों पर बिजली खरीद का 67,143 करोड़ रुपये बकाया है। सितंबर में यह बकाया 54,705 करोड़ रुपये था। केंद्र सरकार ने एक देश एक ग्रिड सिस्टम लागू करने के साथ इसके माध्यम से होने वाली बिजली की खरीद-बिक्री के लिए कुछ नियम भी तय किए हैं। इसके तहत बिजली खरीदने वाली कंपनियों को 60 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। 67,143 करोड़ रुपये की यह राशि 60 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद की है।

राजस्थान शीर्ष पर : बिजली के बकायेदारों में राजस्थान शीर्ष पर है। उस पर ढाई वर्ष से 21,467 करोड़ रुपये की देनदारी बनी हुई है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पर 5,300 करोड़ से अधिक का बकाया है। मध्य प्रदेश पर भी 1,100 करोड़ से अधिक की देनदारी है। ज्यादातर राज्यों पर सौ करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। देश के बड़े बिजली उत्पादक राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ पर सिर्फ 66 करोड़ और पश्चिम बंगाल पर भी केवल 61 करोड़ रुपये ही बकाया है।

राज्यों पर बिजली खरीद का बकाया

राज्य	बकाया	दिन
राजस्थान	21467	912
तमिलनाडु	11400	908
उत्तर प्रदेश	8746	880
तेलंगाना	5074	890
मध्यप्रदेश	1164	897
ओडिशा	967	876
दिल्ली	961	939
बिहार	684	912
पंजाब	562	839
महाराष्ट्र	358	870
उत्तराखंड	333	329
गुजरात	188	876
झारखंड	127	248
छत्तीसगढ़	66	854
पश्चिम बंगाल	61	874
हिमांचल प्रदेश	04	133

नोट : बकाया करोड़ रुपये में

आइबीसी से बाहर ही निपट गए पौने चार लाख करोड़ रुपये के मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने बताया है कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रक्रिया में जाने से पहले ही 9,600 से अधिक मामलों को निपटा लिया गया है। इन मामलों से सम्मिलित रूप से करीब 3.75 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी हुई। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आइबीसी के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक इसमें कुल 21,136 मामले आए हैं। इनमें 3,74,931.30 करोड़ रुपये के 9,653 मामले आइबीसी के बाहर ही सुलझा लिए गए।

इसके अलावा 2,838 मामलों में इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई और इनमें से 306 मामलों का निपटान कर दिया गया है। इस दौरान मंत्रालय ने बताया कि आइबीसी के तहत 161 ऐसे मामलों को सुलझाया गया है, जिनमें 1,56,814 करोड़ रुपये फंसे हुए थे। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) वर्ष 2016 में अस्तित्व में आया था। इसका मकसद संकट से गुजर रही संपत्ति की समस्याओं का निश्चित समय के भीतर निपटान करना है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वर्ष के अंत में की गई समीक्षा में बताया कि पिछले कुछ समय के दौरान सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं और मजबूत इन्सॉल्वेंसी ढांचा तैयार किया है। सरकारी सुधारों के चलते ही हम विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में 14 स्थानों के सुधार में सफल रहे हैं। भारत इस वर्ष की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में 63वें पायदान पर रहा है। इससे पहले यह 77वें पायदान पर था।

- इन्सॉल्वेंसी में जाए बिना ही 9,600 से अधिक मामलों का हुआ निपटान
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में उठाए गए हैं कई कदम

प्रतीकात्मक फोटो

14,000 से अधिक मामले वापस लिए गए : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी कानून में सुधार के बाद 14,000 से अधिक मामले वापस लिए गए हैं। इन सुधारों में कई कानूनों को गैर-आपराधिक मामलों में तब्दील करना शामिल है। इससे आपराधिक अदालतों और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) पर बोझ कम हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने ग्रीन चैनल के अंतर्गत ऑटोमैटिक अप्रूवल सिस्टम की शुरुआत की है। इससे समय और लागत में कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों के पंजीकरण और नाम का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बनाए गए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में महज दो दिनों के भीतर काम हो जाता है, जिसमें पहले अमूमन 15 दिनों तक लगते थे। पिछले तीन वर्षों में सालाना सवा लाख से ज्यादा कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। उससे पहले यह आंकड़ा सलाना 60 हजार तक होता था।

शेयर समीक्षा

अमेरिका-चीन में डील हो जाने के चलते निवेशक उत्साहित, थोक महंगाई के आंकड़ों पर भी रहेगी निवेशकों की नजर

ग्लोबल संकेतों पर बाजारों का थिरकना रहेगा जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका-चीन में प्राथमिक व्यापार समझौते के मूर्त रूप लेने के बाद भारत सहित दुनियाभर के शेयर बाजारों में सोमवार को उत्साह दिखने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक इस सप्ताह भी भारतीय शेयर बाजारों में खरीदारी का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा ब्रिटेन के आम चुनावों में बोरिस जॉनसन की जीत का सकारात्मक असर भी दुनियाभर के बाजारों पर दिखा है। जॉनसन की जीत से ब्रेक्जिट का संकट खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है।

रेलिगेयर के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा के मुताबिक हाल के घटनाक्रमों के बाद लगभग डेढ़ वर्ष से चल रहा कारोबारी संकट खत्म होता दिख रहा है। इसका जश्न भारतीय बाजारों सहित पूरे ग्लोबल मार्केट में मनाया गया। इससे बाजारों का मूड पॉजिटिव हुआ है और उसके आगे भी बने रहने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च प्रमुख सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक पिछले सप्ताह के आखिरी सत्र में देखी गई तेजी आगे भी बने रहने की उम्मीद है। घरेलू स्तर पर सोमवार को जारी होने जा रहे थोक महंगाई के आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम कहते हैं कि हाल के घटनाक्रमों के बाद निवेशकों का जोश बढ़ा है और आगे भी बने रहने की उम्मीद है। डॉलर के मुकाबले रुपये का प्रदर्शन और कच्चे तेल के भाव से भी बाजार भी प्रभावित होंगे। पिछले सप्ताह बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 564.56 अंक का इजाफा हुआ था। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 165.20 अंक की तेजी दर्ज करने में सफल रहा था।

बाजारों का पॉजिटिव मूड बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रतीकात्मक फोटो

सरकार ने शुरू की विदेशी फंड की समीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार विभिन्न सेक्टरों में विदेशी निवेश की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान रणनीतिक स्थानों पर टेलीकॉम और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगाए गए विदेशी फंड की समीक्षा की जाएगी। इस समय ज्यादातर सेक्टरों में ऑटोमैटिक रूट से विदेशी निवेश आ रहा है। इस वजह से विदेशी फंड पर नजर रखना जरूरी हो गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए ढांचागत निर्माण में लगे विदेशी फंड की समीक्षा करेगी। इसके अलावा संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों में आए विदेशी निवेश पर भी नजर डाली जाएगी। इस काम में आरबीआइ सहित कई सरकारी एजेंसियों की मदद ली जाएगी।

शीर्ष 10 में से छह कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में हुआ इजाफा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सप्ताह शेयर बाजार की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से छह के बाजार पूंजीकरण में 65,060 .30 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इस दौरान आरआइएल और एचडीएफसी के एम-कैप में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआइ के एम-कैप में इजाफा दर्ज किया गया। दूसरी ओर टीसीएस, एचयूएल, इन्फोसिस और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में गिरावट देखी गई।

आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम-कैप में 17,439 .74 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके साथ कंपनी का एम-कैप 10,03,147 .26 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। वहीं एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 15,435 .51 करोड़ रुपये उछलकर 4,06,705 .23 करोड़ रुपये का स्तर दर्ज करने में सफल रहा। इसके अलावा एसबीआइ का एम-कैप 11,512 .75 करोड़ रुपये वृद्धि के साथ 2,96,921 .83 करोड़ रुपये रहा।

अब तीन दिन में पोर्ट होगा मोबाइल नंबर

जेएनएन, नई दिल्ली : मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) यानी नंबर बदले बिना सेवा प्रदाता कंपनी बदलने को लेकर सोमवार से नया नियम लागू हो रहा है। नए नियम के अनुसार अब आवेदन के तीन दिन के भीतर ही सर्विस ऑपरेटर बदल जाएगा। अभी तक इसमें लगभग सात दिन लगते हैं।

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने हाल ही में नए नियम लागू करने का आदेश दिया था। इससे जुड़ा सिस्टम अपडेट करने के लिए देशभर में 10 से 15 दिसंबर तक एमएनपी सेवा बंद रही। 16 दिसंबर से लागू होने जा रहे नियम के अनुसार नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन करने के तीन कामकाजी दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरे सर्किल में नंबर पोर्ट करवाने की प्रक्रिया में पांच दिन लगेंगे। हर महीने एमएनपी के लिए काफी संख्या में आवेदन आते हैं। देश में नवंबर, 2010 में एमएनपी सुविधा शुरू हुई थी।

न्यूज गैलरी

मेक्सिको में सामूहिक कब्र की खोदाई में निकले 50 शव

गुआदलजारा : मेक्सिको के जलिस्को प्रांत में गुआदलजारा शहर के बाहरी इलाके में शनिवार को एक सामूहिक कब्र की खोदाई में 50 शव निकाले गए। पुलिस ने बताया, इनमें से 13 की शिनाख्त हो चुकी है। इस कब्र के पीछे भी मेक्सिको में ड्रग्स तस्करों के बीच होने वाले गैंग वार को मुख्य वजह कहा जा रहा है। इसी क्षेत्र में सितंबर में एक अन्य सामूहिक कब्र से 34 शव बरामद किए गए थे। इससे चार महीने पहले भी 30 शवों वाले एक कब्र का पता चला था। (एएफपी)

सिंगापुर में विपक्षी दल को पोस्ट बदलने का आदेश

सिंगापुर : फेक न्यूज के खिलाफ सिंगापुर में हाल में बने कानून के तहत सरकार ने सोशल मीडिया पर एक विपक्षी दल द्वारा पेश आंकड़ों को भ्रामक बताते हुए उन्हें बदलने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि सिंगापुर डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) ने रोजगार के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर देश में लागू ऑनलाइन फाल्सहुड एंड मैनिपुलेशन एक्ट (पीओएफएमए) का उल्लंघन किया है। सोशल साइट फेसबुक और अपनी वेबसाइट पर डाले पोस्ट में एसडीपी ने लिखा है कि सिंगापुर में रोजगार के अवसरों में स्थानीय लोगों की संख्या कम हुई है। लेकिन सरकार का कहना है कि पिछले चार वर्षों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त हुए। दो महीने पहले लागू नए कानून के तहत सरकार ने एसडीपी को अपने पोस्ट के साथ यह नोट लगाने का आदेश दिया है कि इसमें दिए गए तथ्य भ्रामक और गलत हैं। (रायटर)

इटली में द्वितीय विश्वयुद्ध काल का बम मिलने से मचा हड़कंप

रोम : इटली के ब्रिंदिसि शहर में द्वितीय विश्वयुद्ध काल का एक बम मिलने से वहां हड़कंप मच गया। 200 किलोग्राम के इस बम की खबर मिलने पर डेढ़ किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को पहले बाहर शिफ्ट किया गया। इलाका खाली होने के बाद बम को नष्ट करने का काम किया गया। (एएफपी)

फिलीपींस में भूकंप से बच्चे की मौत

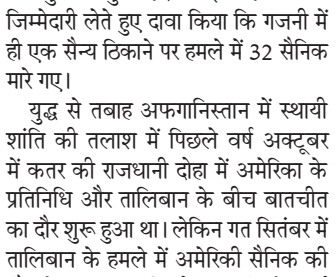

दक्षिणी फिलीपीस में आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से पडाडा शहर में ध्वस्त हुई इमारत। एएफपी

डावाओ : फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से के डावाओ डेल सुर प्रांत में रविवार को आए तेज भूकंप से एक बच्चे की मौत हो गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई। फिलीपींस के इस क्षेत्र में आए दिन भूकंप के तेज झटके आते रहते हैं। (एपी)

गर्लफ्रेंड के हाथ की बनी चिकन करी खाकर जॉनसन ने मनाया जीत का जश्न

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गर्लफ्रेंड कैरी सायमंड्स के हाथ की बनी चिकन करी खाकर आम चुनाव में मिली शानदार जीत का जश्न मनाया। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार रात यहां एक रूसी अरबपति द्वारा दी गई क्रिसमस पार्टी में भी शिरकत की। गत 12 दिसंबर को हुए संसदीय चुनाव में जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी को 1987 के बाद सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी लेबर पार्टी को 1930 के बाद सबसे कम सीटें मिलीं।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान बुरी तरह थक चुके जॉनसन शुक्रवार को बहुत खुश थे। चुनाव में मिली जीत की खुशी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को उनकी गर्लफ्रेंड ने 11 डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास) में जॉनसन की पसंदीदा मसालेदार चिकन करी बनाई। डिनर के बाद दोनों रूसी अरबपति एवगेनी लेवेव द्वारा दी गई क्रिसमस पार्टी में भी शामिल हुए। इस दौरान उनकी मुलाकात रोलिंग स्टोंस के सिंगर मिक जैगर, प्रिंसेस बीट्राइस और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से हुई। मुलाकात के दौरान कैमरन ने जॉनसन को गले से लगा लिया। इस क्रिसमस पार्टी में जॉनसन ने वही सूट पहन रखा था जो उन्होंने चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट से देश को संबोधित करते हुए पहना था। इस चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी ने जहां 365 सीटें जीतीं वहीं लेबर पार्टी के खाते में मात्र 203 सीटें आईं। कंजरवेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी के परंपरागत इलाकों मिडलैंड्स और उत्तरी इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे वेल्स में भी उसका दबदबा रहा।

उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के डरहम काउंटी में स्थित सेजफील्ड क्रिकेट क्लब में कंजरवेटिव पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में शिरकत करने जाते ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। एएफपी

इच्छा के विपरीत स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में नहीं रख सकते जॉनसन

लंदन, रायटर : चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोल स्टर्जन ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को चेताया है कि वह स्कॉटलैंड की इच्छा के विपरीत उसे यूनाइटेड किंगडम में नहीं रख सकते। जॉनसन और उनकी सरकार लगातार कहती रही है कि वह स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता को लेकर एक और जनमत संग्रह नहीं कराएंगे। लेकिन स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) ने कहा है कि उसे जनमत संग्रह के लिए जनादेश मिला है। एसएनपी ने स्कॉटलैंड की 59 सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की है। स्कॉटलैंड की कैबिनेट की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। स्टर्जन ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर वह सोचते हैं कि नहीं कहने से काम खत्म हो जाएगा तो वह पूरी तरह गलत साबित होंगे। आप स्कॉटलैंड की इच्छा के विपरीत उसे यूनाइटेड किंगडम में नहीं रख सकते। यह उसकी स्वीकृति के बाद ही संभव हो सकेगा। अगर जॉनसन समझते हैं कि वहां के लोग यूनाइटेड किंगडम के साथ रहने को प्रतिबद्ध हैं तो इसका निर्णय वहां के लोगों को ही करने दें।

भारतवंशी सांसद को मिल सकती है लेबर पार्टी की कमान

लंदन, प्रेट्र : भारतवंशी सांसद लीसा नंदी ब्रिटेन की लेबर पार्टी में जेरेमी कॉर्बिन की जगह ले सकती हैं। कॉर्बिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह अगले आम चुनावों में पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे। पार्टी की बुरी हार के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ गया है।

गुरुवार को हुए आम चुनाव में भारतीय मूल के जिन 15 सांसदों ने जीत दर्ज की है, उनमें 40 वर्षीय लीसा भी हैं। वह अपनी विगान सीट बचाने में कामयाब रहीं। रविवार को एक इंटरव्यू में पार्टी नेतृत्व की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं इसके बारे में गंभीरता से सोच रही हूं। हमें इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जिन लोगों ने जीवनभर लेबर पार्टी को वोट दिया आखिर उन्होंने हमें क्यों नकार दिया।

नंदी के अलावा कीर स्टारमर और बर्मिंघम से सांसद जेस फिलिप्स भी पार्टी मुखिया बनने के लिए जोर लगा रहे हैं।

हार के लिए कॉर्बिन ने मांगी माफी

आम चुनावों में पार्टी की हार के लिए लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने लोगों से माफी मांगी है। संडे मिरर और ऑब्जर्वर में लिखे लेख में कॉर्बिन ने हार के लिए माफी तो मांगी लेकिन नेतृत्व छोड़ने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। उन्होंने लिखा, कोई भी व्यक्ति जो परिवर्तन चाहता था, उसके लिए यह परिणाम झटका है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।

सबसे लंबे पर्यावरण सम्मेलन में नहीं हो सकी कोई घोषणा

बेनतीजा ▶ लेकिन गैसों का उत्सर्जन कम करने को सभी देश हुए सहमत

मैड्रिड, एपी : पर्यावरण पर आयोजित दो सप्ताह का सम्मेलन रविवार को खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान पर्यावरण सुधार पर लंबी चर्चा के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। हां, पेरिस समझौते को उचित रूप से लागू करने पर प्रमुख देश जरूर सहमत थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने सम्मेलन में कोई घोषणा न हो पाने पर निराशा जताई है। कहा कि दुनिया ने बड़ा मौका गंवा दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में करीब 200 देशों ने हिस्सा लिया।

पर्यावरण पर दो सप्ताह चली चर्चा में ज्यादातर देशों ने नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन पर चिंता जताई। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन नियंत्रित करने की आवश्यकता जताई गई। पर्यावरण में हो रहे बदलाव से समस्याएं झेल रहे गरीब देशों ने मदद की मांग की। इन सारे बिंदुओं पर सम्मेलन में सबसे लंबी चर्चा हुई लेकिन पर्यावरण सुधार के लिए कोई नया कार्यक्रम फलक पर नहीं आया। अगला वार्षिक सम्मेलन ग्लासगो में होगा।

सम्मेलन में पर्यावरण समूहों और कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर धनी देशों की इच्छाशक्ति पर सवाल उठाए। कहा, पर्यावरण से जुड़े मसलों पर गंभीरता दिखाने की जगह ये देश मामूली काम करते हैं। इससे समस्या जस की तस बनी हुई है। दुनिया में कोयले के कारोबार पर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। कोयले के जलने से ही सबसे ज्यादा मात्रा में जहरीली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अब यह मसला एक साल के लिए टल गया है। अब ग्लासगो में इस विषय पर बात होगी। पर्यावरण सुधार के लिए किसी घोषणा तक पहुंचने के लिए सम्मेलन में भरसक कोशिश हुई लेकिन अंततः वह विफल रही। सबसे लंबे समय दो सप्ताह के इस सम्मेलन में 40 घंटे अतिरिक्त चर्चा हुई। रविवार को समापन सत्र में प्रतिनिधियों ने रात भर जगकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की लेकिन वे विफल रहे। सम्मेलन बिना किसी घोषणा के संपन्न हो गया। पूर्व में पारित चिली-मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन के पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि नुकसानदायक गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए सभी देश अपने प्रयासों को बढ़ाएं।

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र के मौके पर विचारपूर्ण मुद्रा में ब्राजील के विदेश मंत्रालय में पर्यावरण विभाग के निदेशक लियोनार्डो क्लीवर(बाएं) और मोबाइल पर व्यस्त राष्ट्रीय संप्रभुता और नागरिकता के सचिव फैबियो मेंडेंस मार्जानो। रायटर

विकास के रथ पर सवार होकर पाक से आगे निकला बांग्लादेश

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश ने अपनी आजादी के बाद के वर्षों में विकास की कुलांचे भर पाकिस्तान की आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के समय पड़ोसी पाकिस्तान ने आशंका जताई थी कि वह लंबे समय तक आजाद देश नहीं रह पाएगा। बांग्लादेश के 'विजय दिवस' की पूर्व संध्या रविवार को एक वरिष्ठ मंत्री ने यह दावा किया कि उनका देश मानव विकास, सामाजिक व आर्थिक सूचकांक के मामले में काफी आगे निकल चुका है।

विदेश मंत्रालय के 'विजिट बांग्लादेश' कार्यक्रम के तहत भारत, नेपाल, मालदीव, ब्रिटेन, पुर्तगाल व जर्मनी आदि के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सूचना मंत्री हसन महमूद ने कहा, 'सामाजिक और मानव विकास सूचकांक के मामले में हमारा देश पड़ोसी पाकिस्तान समेत अन्य से आगे निकल चुका है। हम रेडिमेड गार्मेंट के मामले में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक हैं। शेख हसीना सरकार प्रेस की आजादी और बहुलवादी समाज में विश्वास रखती है। बांग्लादेश सरकार आलोचना का स्वागत करती है और ऐसा करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी करती है। इससे हमें समस्या के समाधान की दिशा में काम करने में मदद मिलती है।' उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2021 तक बांग्लादेश मध्यम आय वर्ग वाला व वर्ष 2041 तक विकसित देश बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 25 मार्च 1971 को बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में युद्ध शुरू हुआ था, जिसका समापन 16 दिसंबर को उसकी आजादी के साथ हुआ।

सालाना जीडीपी (लाख डॉलर) : 28,84,240, 3,14,588	रक्षा खर्च (दस लाख डॉलर) : 3,936.7, 12,664.5
प्रति व्यक्ति जीडीपी (लाख डॉलर) : 1,788, 1,565	निर्यात (दस लाख डॉलर) : 35,850.0, 21,724
ऋण (लाख डॉलर) : 91,524, 2,25,435	निर्यात (जीडीपी का फीसद) : 13.68, 7.13
ऋण (जीडीपी का फीसद) : 33.99, 71.69	आयात (दस लाख डॉलर) : 5,2836.3, 5,7746
प्रति व्यक्ति कर्ज (डॉलर) : 567, 1122	आयात (जीडीपी का फीसद) 20.16, 18.96
व्यय (दस लाख डॉलर) : 38,512.0, 68,020.1	वैश्विक शांति सूचकांक में स्थान : 101, 153
शिक्षा पर खर्च (दस लाख डॉलर) : 3,618.1, 8,407.5	जन्मदर (सालाना एक हजार पर जन्मदर) : 18.61 फीसद, 27.70 फीसद
शिक्षा पर व्यय (बजट का फीसद) : 11.42, 13.85	मानव विकास सूचकांक वैल्यू : 0.608, 0.562
रक्षा खर्च (बजट का फीसद) : 10.16, 18.51	जीवन प्रत्याशा (साल में) : 72.81, 66.63

कौन कितने पानी में

बांग्लादेश, पाकिस्तान
राजधानी : ढाका, इस्लामाबाद
जनसंख्या : 16 करोड़, 20 करोड़
क्षेत्रफल (वर्ग किमी) : 147630, 796100
मुद्रा : टका, पाकिस्तानी रुपया

प्रतिव्यक्ति आय में तेज इजाफा

दक्षिण एशिया में गत चार दशक के दौरान बांग्लादेश की सालाना जीडीपी वृद्धि दर 7.6 और पाकिस्तान की 6.7 फीसद थी। इसकी सालाना विकास दर पाकिस्तान के 8.6 के मुकाबले 12.9 फीसद रही है। नतीजतन, यहां लोगों की प्रतिव्यक्ति आय में तेजी से इजाफा हो रहा है। 2016 में यह आय 1,355 डॉलर थी जो 40 फीसद इजाफे को दिखाती है। इस दौरान पाकिस्तान में प्रतिव्यक्ति आय सिर्फ 21 फीसद बढ़ी।

वार्ता रुकते ही तालिबान ने अफगानिस्तान में तेज किए हमले

काबुल, आइएएनएस : अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता स्थगित होते ही आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं। बीते शुक्रवार से देश के कई हिस्सों में आतंकी वारदातों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गजनी प्रांत में शनिवार को किए गए एक हमले में 23 सुरक्षाकर्मी मारे गए। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि गजनी में ही एक सैन्य ठिकाने पर हमले में 32 सैनिक मारे गए।

युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थायी शांति की तलाश में पिछले वर्ष अक्टूबर में कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के प्रतिनिधि और तालिबान के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ था। लेकिन गत सितंबर में तालिबान के हमले में अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता रद कर दी थी। गत सात दिसंबर को यह वार्ता फिर शुरू हुई थी। लेकिन चार दिन बाद ही अफगानिस्तान के बगराम स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने वार्ता स्थगित कर दी।

बांग्लादेश ने भारत में अवैध तरीके से रह रहे देशवासियों की सूची मांगी

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश ने भारत में अवैध तरीके से रह रहे अपने देश के लोगों की सूची मांगी है। साथ ही कहा है कि वह ऐसे लोगों को स्वदेश वापसी की अनुमति देगा।

भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बारे में पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा, 'भारत-बांग्लादेश के संबंध बहुत मधुर हैं। इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत ने इसे आंतरिक मामला करार देते हुए बांग्लादेश को आश्वस्त किया है कि इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।'

विदेश मंत्री ने कहा, सभी को वापस आने की अनुमति दी जाएगी

मोमेन ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए गुरुवार को अपने भारत दौरे के रद कर दिया था। इस संबंध में पूछे जाने पर फिर उन्हीं कारणों को दोहराया। भारत के विरोध की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय आर्थिक कारणों से बिचौलियों के जरिये बांग्लादेश आ जाते हैं। हम उन्हें वापस भेज देते हैं।

एके अब्दुल मोमेन। फाइल

बांग्लादेश सरकार ने रजाकारों की सूची जारी की

बांग्लादेश सरकार ने 1971 की आजादी की लड़ाई में दुश्मन सेना का साथ देने वाले 10,789 रजाकारों की सूची जारी कर दी है। रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान मुक्ति आंदोलन विभाग के मंत्री एकेएम मुजम्मिल हक ने सूची को सार्वजनिक किया। रजाकारों ने बांग्लादेश की आजादी के समय पाकिस्तानी सेना का साथ देते हुए हिंदुओं को निशाना बनाया था।

उत्तर कोरिया से तनाव के बीच दक्षिण कोरिया पहुंचे अमेरिकी दूत

इंचियोन, रायटर : उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बीगन रविवार को दक्षिण कोरिया पहुंचे। ट्रंप प्रशासन ने बीगन को खासतौर पर उत्तर कोरिया से जुड़ी जिम्मेदारी है। बीगन अपने इस तीन दिवसीय दक्षिण कोरिया दौरे में सोमवार को राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह आधिकारिक दौरे पर जापान जाएंगे।

अमेरिकी दूत की यह यात्रा ऐसे वक्त पर शुरू हुई है जब उत्तर कोरिया ने एक दिन पहले ही महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किया था। जानकारों के मुताबिक यह लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण था। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षणों से अमेरिका पर आर्थिक प्रतिबंधों में ढील का दबाव बनाने की कोशिश में है। अमेरिका हालांकि स्पष्ट कर चुका है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के बगैर उत्तर कोरिया को कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग-उन के बीच तीन बार वार्ता हो चुकी है। लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई।

इराक में प्रदर्शन जारी, तरीका बदला

इराक की राजधानी बगदाद के तहरीर स्क्वायर में रविवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान दीवार पर स्लोगन लिखता युवक। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निम्नस्तरीय सरकारी सेवाओं को लेकर इराक में अक्टूबर माह से प्रदर्शनों का दौर जारी है। यहां पुलिस से संघर्ष में कई प्रदर्शनकारियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। एएफपी

दी सफाई

उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के मामले में चीन ने अंतरराष्ट्रीय चर्चा के बीच कहा, तीन साल से सीमावर्ती राज्य में नहीं हुई कोई वारदात

आतंकवाद से बचाव के लिए शिनजियांग में सुधार शिविर

नई दिल्ली, प्रेट्र : शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न की अंतरराष्ट्रीय चर्चा के बीच चीन की ओर से सफाई आई है। कहा गया है कि चीन में धार्मिक आधार पर लोगों को उत्पीड़न नहीं हो रहा। शिनजियांग प्रांत के सुधार शिविर वास्तव में आतंकदवाद, चरमपंथ और कट्टरता के चंगुल से लोगों को निकालने के लिए स्थापित किए गए हैं।

भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा, शिनजियांग प्रांत 1990 से ही आतंकी और धार्मिक चरमपंथ वाली हिंसक गतिविधियों का शिकार रहा है। लेकिन बीते तीन साल में प्रांत में आतंकी हिंसक गतिविधियों में भारी गिरावट देखी गई है। ऐसा वहां पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुधार शिविरों के चलते हुआ। इनमें लोगों को मिल-जुलकर रहने की शिक्षा दी जा रही है और राष्ट्रप्रेम की भावना पैदा की जा रही है। चीन की ओर से यह प्रतिक्रिया करीब दस लाख उइगर मुसलमानों को उच्च सुरक्षा वाले बंदी शिविरों में रखे जाने की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़े के बाद आई है। इन मुस्लिमों को बिना किसी अपराध के और अदालतों में पेश किए बगैर रखा गया है।

भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग। फाइल

- कहा कि शिनजियांग प्रांत 1990 से ही आतंकी और धार्मिक चरमपंथ वाली हिंसक गतिविधियों का शिकार रहा है
- लोगों को मिल-जुलकर रहने की शिक्षा दी जा रही है और राष्ट्रप्रेम की भावना पैदा की जा रही है।

एक सवाल के जवाब में चीनी राजदूत ने कहा, शिनजियांग में एक भी बंदी शिविर नहीं है। वहां पर आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि शिनजियांग में बीते तीन वर्षों में कोई आतंकी वारदात नही हुई है। शिनजियांग के आंकड़ों को सामने रखते हुए वीडोंग ने कहा, कुछ वर्षों पहले वहां पर दो हजार मस्जिदें थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 24,400 हो गई है। इसी प्रकार से मौलानाओं की संख्या तीन हजार से बढ़कर 29 हजार हो गई है। उन्होंने कहा कि शिनजियांग चीन का हिस्सा है और वहां के मामलों में हस्तक्षेप या गलत चर्चा का किसी को अधिकार नहीं है। पश्चिमी ताकतें चीन को अस्थिर करने की बार-बार कोशिश कर रही हैं लेकिन इससे चीन के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

क्षेत्रीय शांति के लिए भारत-चीन सहयोग जरूरी: राजदूत ने कहा, चीन और भारत के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के सकारात्मक नतीजे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए एकमत हैं।

जासूसी के आरोप में दो चीनी राजनयिक अमेरिका से निष्कासित

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका ने चीनी दूतावास के दो अधिकारियों को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया है। अमेरिका ने यह कदम सितंबर में उठाया जब दोनों अधिकारियों को वर्जीनिया सैन्य ठिकाने से पकड़ा गया। यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। अखबार ने लिखा है कि पहली बार अमेरिका ने जासूसी के आरोप में चीन के किसी अधिकारी को देश से निष्कासित किया है। माना जा रहा है कि इनमें से एक अधिकारी वास्तव में खुफिया अधिकारी था जो राजनयिक के रूप में चीनी दूतावास में काम कर रहा था। पता चला है कि दोनों चीनी अधिकारी अपनी पत्नियों के साथ वर्जीनिया के नोरफोक इलाके में स्थित सैन्य ठिकाने पर कार से जा पहुंचे थे। यह अमेरिका के विशेष बलों का प्रशिक्षण स्थल भी है।

पाक ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को जर्मनी का राजदूत बनाया

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने बड़ा कूटनीतिक फेरबदल करते हुए विदेशों में स्थित अपने विभिन्न दूतावासों में 20 राजदूतों और माहवाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति की है। इनमें विदेश मंतत्रालय के प्रवक्ता मौहम्मद फैसल का भी नाम शामिल है जिन्हें जर्मनी में देश का नया राजदूत बनाया गया है। समाचारपत्र 'डॉन' की खबर में बताया गया कि विदेश मंत्रालय की ओर से 13 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने 17 राजदूतों और तीन महावाणिज्यदूतों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है।

दक्षिण एशिया और दक्षेस के लिए महानिदेशक के तौर पर भी सेवा दे रहे फैसल, जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत जौहर सलीम का स्थान लेंगे। सलीम अब इटली में अपनी सेवाएं देंगे। फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर फैसल की जगह कौन लेंगे।

98 हजार डॉलर के साथ कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़े गए दो सीरियाई

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 97.6 हजार अमेरिकी डॉलर (लगभग 69 लाख रुपये) के साथ सीआइएसएफ ने दो सीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपित मोजे और हैंड बैग में डॉलर छिपा कर ले जा रहे थे। इनके नाम मोहम्मद अल सब्बाघ और मोहम्मद बस्साम है। आरोपित एयरपोर्ट पर शनिवार शाम चाइना एयरलाइंस विमान पकड़ने पहुंचे थे, तभी दोनों को दबोचा गया। सीआइएसएफ अधिकारियों की मानें तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के लिए लगे डोर फ्रेम मेटर डिटेक्टर (डीएफएमडी) से गुजर रहे थे, तभी उन पर संदेह हुआ। उनकी तलाशी ली गई, तो मोजे से चार-चार बंडल यूएस डॉलर (100-100 के आठ सौ नोट) मिले, जिसे पेपर में लपेट कर मोजे के भीतर छिपाए गए थे। इसके बाद हैंडबैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से दो बंडल (100 बंडल के 176 नोट) बरामद हुए।

ये भी जानिए

भारत ने इस मैच में लगातार तीसरी बार चौथे विकेट के लिए 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। इससे पहले भारतीय टीम ने ऐसा 2004 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वीबी सीरीज में किया था।

हेटमायर-होप ने सिखाया सबक

- वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में भारत को आठ विकेट से हराया
- शाई-शिमरोन के शतक, पंत-अय्यर के अर्धशतक गए बेकार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: चेन्नई शहर को क्रिकेट की परख है। वह क्रिकेट को सम्मान देते हैं तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को भी सर आंखों पर बैठाते हैं। पिछले कई मैचों से धौनी-धौनी की आवाजों से दबाव में आने वाले भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत (71) को आखिरकार पंत-पंत की आवाज सुनने को मिली और उनका बल्ला चल पड़ा। नंबर चार के स्थान पर श्रेयस अय्यर (70) ने भी लगातार तीसरा अर्धशतक लगाकर टीम इंडिया की इस दुविधा को काफी हद तक दूर कर दिया। सही मायनों में टीम इंडिया के लिए एमए चिदंबरम मैदान पर रविवार को यही दो सुखद चीज रहीं। बाकी का शो तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर (139) और शाई होप (नाबाद 102) अपने नाम कर गए, जिनकी बदौलत वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में भारतीय टीम को आठ विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने पंत-अय्यर के अर्धशतकों की बदौलत 50 ओवर में आठ विकेट पर 287 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 13 गेंद शेष रहते 291 रन बनाकर मैच जीत लिया।

शुरुआती झटके के बाद संभले मेहमान: 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने धीमे विकेट पर संभलकर शुरुआत की, लेकिन इस बीच पांचवें ओवर में दीपक चाहर ने मेहमानों को सुनील अंबरीश (09) के रूप में पहला झटका दिया। इसके बाद तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पिच से पूरी तरह से सामंजस्य बैठा चुके थे। होप और हेटमायर ने दूसरे विकेट के लिए 218 रनों की साझेदारी करके जीत की नींव रख दी थी। हेटमायर हालांकि 106 गेंद में 11 चौके और सात छक्के लगाकर 139 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी। होप के अलावा निकोलस पूरन ने नाबाद 29 रन बनाए।

फिर टपकाए कैच: वेस्टइंडीज की पारी के 35वें ओवर में अय्यर ने हेटमायर का कैच टपका दिया। चाहर की गेंद पर लांग ऑन पर यह कैच टपका दिया। हेटमायर उस वक्त 107 रन पर थे। मालूम हो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण बेहद ही खराब रहा था। इससे पहले टी-20 सीरीज में भी कई खिलाड़ियों ने यहां तक की विराट कोहली ने भी कैच टपकाए थे।

राहुल, कोहली नहीं चले: इससे पहले, भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने 21 रन के कुल योग पर लोकेश राहुल (06) का विकेट गंवा दिया। राहुल को कॉटरेल ने शिमरोन हेटमायर के हाथों कैच कराया। इसके बाद विकेट पर कप्तान विराट कोहली आए, लेकिन वह चार रन के निजी योग पर कॉटरेल की गेंद को ठीक से पढ़ नहीं सके और बोल्ड हो गए। अय्यर ने इसके बाद आकर रोहित के साथ पारी को संवारने की जिम्मेदारी ली। दोनों संभलकर खेल रहे थे। 80 रन के स्कोर पर हालांकि रोहित अपना संयम खो बैठे और 56 गेंदों पर छह चौके लगाने के बाद अल्जारी की गेंद पर कप्तान कीरोन पोलार्ड के हाथों लपक लिए गए।

अय्यर-पंत ने बांधा समां: अब अय्यर का साथ देने ऋषभ पंत आए। पंत और अय्यर ने संभलकर खेलते हुए भारत के स्कोर को पहले 100 और फिर 150 के पार पहुंचाया। इस साझेदारी के दौरान पंत ने जहां अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया वहीं अय्यर ने छठा अर्धशतक पूरा किया। अय्यर हालांकि 194 के स्कोर पर अल्जारी की गेंद पर पोलार्ड के हाथों लपके गए। अय्यर ने 88 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्का लगाया। अय्यर के बाद पंत भी एक लापरवाह शॉट खेलकर आउट हुए। पंत ने 69 गेंदों का सामना कर सात चौके और एक छक्का लगाया।

जाधव-जडेजा ने पहुंचाया 250 के पार: इसके बाद केदार जाधव और रवींद्र जडेजा ने अर्धशतकीय साझेदारी कर भारत को 250 रन के पार पहुंचाया। जाधव कीमो पॉल की गेंद पर पोलार्ड के हाथों लपके गए। जाधव ने 35 गेंदों का सामना कर तीन चौके और एक छक्का लगाया। जडेजा बदकिस्मत रहे। वह इसी योग पर रन आउट हुए।

अपनी साझेदारी के दौरान रन के लिए दौड़ते शाई होप और शिमरोन हेटमायर ● एएफपी

जडेजा के रन आउट मामले में घिरे अंपायर जॉर्ज

चेन्नई, प्रेट्र: दक्षिण अफ्रीकी अंपायर शॉन जॉर्ज भारतीय बल्लेबाज रवींद्र जडेजा से जुड़े रन आउट के मामले को लेकर मुश्किल में घिर गए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच यहां खेले गए पहले वनडे में भारतीय पारी के दौरान जॉर्ज ने जडेजा को शुरुआत में तो रन आउट नहीं दिया था, लेकिन कैरेबियाई खिलाड़ियों के विरोध के बाद उन्होंने यह मामला तीसरे अंपायर के हवाले किए, जिसके बाद जडेजा आउट दिए गए। यह घटना भारतीय पारी के 48वें ओवर की है। जडेजा एक लेने के प्रयास में रन आउट हुए। हालांकि अंपायर ने पहले उन्हें रन आउट नहीं दिया था और ना ही तीसरे अंपायर की राय मांगी थी। जब कैरेबियाई खिलाड़ी पोलार्ड ने जाएंट स्क्रीन पर रिप्ले देखा तो उन्होंने इस संबंध में विरोध जताया। इसके बाद अंपायर ने तीसरे अंपायर से राय मांगी और फिर जडेजा आउट करार दिए गए। मैदान के बाहर बैठे कप्तान विराट कोहली इस पूरे घटनाक्रम पर काफी नाराज नजर आए। वह खीझ में हाथ झटकते हुए वेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चले गए। कोहली को इस बात का गुस्सा था कि गेंद डेड होने के बाद आखिरकार अंपायर इस मामले को तीसरे अंपायर को कैसे सुपुर्द कर सकते हैं।

स्कोर बोर्ड

टॉस : वेस्टइंडीज (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : शिमरोन हेटमायर

भारत — **287/8** (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. पोलार्ड बो. जोसेफ	36	56	06	00
राहुल का. हेटमायर बो. कॉटरेल	06	15	01	00
विराट कोहली बो. कॉटरेल	04	04	01	00
श्रेयस अय्यर का. पोलार्ड बो. जोसेफ	70	88	05	01
ऋषभ पंत का. हेटमायर बो. पोलार्ड	71	69	07	01
केदार जाधव का. पोलार्ड बो. पॉल	40	35	03	01
रवींद्र जडेजा रन आउट	21	21	02	00
शिवम दुबे का. होल्डर बो. पॉल	09	06	01	00
दीपक चाहर नाबाद	06	08	00	00
मुहम्मद शमी नाबाद	00	01	00	00

अतिरिक्त : (बा-5, लेबा-5, नोबॉ-3, वा-11) 24

कुल : 50 ओवर में आठ विकेट पर 287 रन

विकेट पतन : 1-21 (राहुल, 6.2), 2-25 (कोहली, 6.6), 3-80 (रोहित, 18.1), 4-194 (श्रेयस, 36.4), 5-210 (पंत, 39.4), 6-269 (जाधव, 47.3), 7-269 (जडेजा, 47.4), 8-282 (दुबे, 49.3)

गेंदबाजी:
शेल्डन कॉटरेल 10-3-46-2
जेसन होल्डर 8-0-45-0
हेडन वाल्श जू. 5-0-31-0
कीमो पॉल 7-0-41-2
अल्जारी जोसेफ 9-1-45-2
रोस्टन चेस 7-0-42-0
कीरोन पोलार्ड 4-0-28-1

वेस्टइंडीज — **291/2** (47.5 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
शाई होप नाबाद	102	151	07	01
सुनील अंबरीश, एलबीडब्ल्यू बो. चाहर	09	08	02	00
शिमरोन हेटमायर का. अय्यर बो. शमी	139	106	11	07
निकोलस पूरन नाबाद	29	23	04	00

अतिरिक्त : (लेबा-4, नोबॉ-1, वा-7) 12, कुल : 47.5 ओवर में दो विकेट पर 291 रन, विकेट पतन : 1-11 (अंबरीश, 4.1), 2-229 (हेटमायर, 38.4)

गेंदबाजी : चाहर 10-1-48-1
मुहम्मद शमी 9-1-57-1
कुलदीप यादव 10-0-45-0
शिवम दुबे 7.5-0-68-0
केदार जाधव 1-0-11-0
रवींद्र जडेजा 10-0-58-0

एक जनवरी 2010 से सबसे ज्यादा वनडे जीतने वाली टीम

टीम	मैच	जीत
भारत	246	155
ऑस्ट्रेलिया	216	125
इंग्लैंड	218	124
दक्षिण अफ्रीका	188	114
श्रीलंका	256	113
पाकिस्तान	217	104
न्यूजीलैंड	192	98
बांग्लादेश	162	70
वेस्टइंडीज	194	69
अफगानिस्तान	123	57

भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत में सर्वाधिक स्कोर

रन	खिलाड़ी	टीम	वर्ष
160	दिलशान	श्रीलंका	2009
158	स्ट्रॉस	इंग्लैंड	2011
151*	जयसूर्या	श्रीलंका	1997
149*	चंद्रपॉल	वेस्टइंडीज	2007
139	हेटमायर	वेस्टइंडीज	2019

भारत के खिलाफ सबसे धीमा शतक

गेंद	खिलाड़ी	टीम	जगह	वर्ष
166	डेविड बून	ऑस्ट्रेलिया	होबार्ट	1991
149	शाई होप	वेस्टइंडीज	चेन्नई	2019
143	जैक कैलिस	द. अफ्रीका	डरबन	2006

चेन्नई में सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा

लक्ष्य	टीम	बनाम	वर्ष
288	वेस्टइंडीज	भारत	2019
287	ऑस्ट्रेलिया	न्यूजीलैंड	1996
269	वेस्टइंडीज	भारत	2007

85 गेंद के अंदर ही अब तक वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने अपने सभी पांच वनडे शतक लगाए हैं। उनके यह शतक 74, 78, 82, 84, 85 गेंद में आए

04 खिलाड़ियों ने इस वर्ष भारत के लिए वनडे में पदार्पण किया है। शिवम दुबे चौथे खिलाड़ी बने। इससे पहले मुहम्मद सिराज, विजय शंकर, शुभमन गिल पदार्पण कर चुके हैं

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 296 रन से पराजित किया

पर्थ, एएफपी: ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को 171 रन पर समेट कर 296 रन से जीत दर्ज की, जो इस टीम के खिलाफ रनों के लिहाज से उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहली पारी में 250 रन से पिछड़ने वाली न्यूजीलैंड को डे-नाइट टेस्ट की चौथी पारी में जीत के लिए 468 रन का मुश्किल लक्ष्य मिला था।

ऑस्ट्रेलिया ने लंच से पहले ही सलामी बल्लेबाज जीत रावल और कप्तान केन विलियमसन के विकेट चटकाकर जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इसके बाद मैच को पांचवें दिन तक खींचने की कोशिश की, लेकिन मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस ने पर्थ के मैदान पर खेले गए पहले डे-नाइट टेस्ट में उनकी एक ना चलने दी। न्यूजीलैंड के अंतिम पांच विकेट 17 रन के अंदर गिर गए, जिससे टीम 171 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 296 रन से जीता, जो रनों के हिसाब से न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी जीत से सिर्फ एक रन कम है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑकलैंड में 1974 में न्यूजीलैंड को 297 रन से हराया था। पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले स्टार्क ने दूसरी पारी में 45 रन देकर चार विकेट चटकाए। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड ने सलामी बल्लेबाज जीत रावल और विलियमसन के विकेट गंवा दिए। रावल एक रन बनाकर मैच में स्टार्क का छठा शिकार बने, जबकि लियोन ने पारी की अपनी पहली गेंद पर ही विलियमसन को शॉर्ट लेग पर खड़े मैथ्यू वेड के हाथों कैच कराया। न्यूजीलैंड के कप्तान ने 14 रन बनाए। फॉर्म में चल रहे रॉस टेलर भी 22 बनाकर स्टार्क की गेंद को विकेटकीपर टिम पेन के हाथों लपके गए। सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम ने 68 गेंद की पारी में 18 रन बनाए, लेकिन लियोन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बीजे वटलिंग भी अपनी पारी को 40 रन से आगे नहीं ले जा सके। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में छह विकेट पर 167 रन से की। उसने अपनी पारी नौ विकेट पर 217 रन बनाकर समाप्त घोषित की।

संक्षिप्त स्कोर

ऑस्ट्रेलिया (पहली पारी): 416 (146.2 ओवर), **न्यूजीलैंड (पहली पारी):** 166 (55.2 ओवर) **ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी):** 217/9 घोषित (69.1 ओवर), बर्न्स : 53 (123 गेंद, 06 चौके), लाबुशाने : 53 (81 गेंद, 03 चौके), साउथी : 21.1-6-69-5, **न्यूजीलैंड (दूसरी पारी):** 171 (65.3 ओवर), वाटलिंग : 40 (106 गेंद, 04 चौके), मिशेल : 14-5-45-4, लियोन : 22.3-3-63-4

आबिद का रिकॉर्ड शतक, पाक-श्रीलंका टेस्ट ड्रॉ

रावलपिंडी, एएफपी: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच बारिश से प्रभावित पहला टेस्ट क्रिकेट मैच रविवार को यहां ड्रॉ रहा, जिसका आकर्षण सलामी बल्लेबाज आबिद अली का शानदार शतक रहा। वह वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों में पदार्पण पर शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। इतना ही नहीं, आबिद पदार्पण टेस्ट में शतक लगाने वाले पाकिस्तान के 11वें बल्लेबाज भी बने। आबिद ने नाबाद 109 रन की पारी खेली और बाबर आजम (नाबाद 102) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 162 रन की अटूट साझेदारी निभाई।

पाकिस्तान ने खेल के पांचवें और अंतिम दिन अपनी पहली पारी में जब दो विकेट पर 252 रन बनाए थे तो अंपायरों ने मैच ड्रॉ समाप्त घोषित करने का फैसला किया। पाकिस्तान में पिछले 10 साल में पहली बार खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले चार दिन का खेल बारिश से प्रभावित रहा। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी छह विकेट पर 308 रन बनाकर घोषित की। उसकी तरफ से धनंजय डिसिल्वा ने शतक लगाया। उन्होंने रविवार को सुबह 87 रन से आगे खेलते हुए नाबाद 102 रन बनाए। डिसिल्वा ने पहले तीन दिन भी बल्लेबाजी की, जबकि चौथे दिन बारिश के कारण खेल नहीं हो पाया था। इसके बावजूद यह मैच पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी और आबिद के शतक के कारण यादगार बन गया। आबिद ने अपनी पारी में 201 गेंदें खेली तथा 11 चौके लगाए। यह 32 वर्षीय बल्लेबाज जब 95 रन पर था तब उन्होंने विश्व फर्नांडो पर पहले चौका जड़ा और फिर कवर पर दो रन के लेकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इस साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में वनडे क्रिकेट में पदार्पण पर 112 रन की पारी खेली थी। बाबर आजम ने दिन के अंतिम क्षणों चौका लगाकर घरेलू सरजमीं पर पदार्पण मैच में शतक पूरा किया। दोनों कप्तानों की सहमति से मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया।

वनडे और टेस्ट पदार्पण में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने अली, आजम ने भी लगाया घरेलू सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक

संक्षिप्त स्कोर

श्रीलंका (पहली पारी): 308/6 घोषित (97 ओवर), धनंजय डिसिल्वा : नाबाद 102 (166 गेंद, 15 चौके), शाहीन शाह अफरीदी : 22-7-58-2,
पाकिस्तान (पहली पारी): 252/2 (70 ओवर), आबिद अली : नाबाद 109 (201 गेंद, 11 चौके), बाबर आजम : नाबाद 102 (128 गेंद, 14 चौके), कासुन रजिता : 6-2-5-1

श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट में शतक लगाने के बाद जश्न मनाते पाकिस्तानी बल्लेबाज आबिद अली ● एएफपी

डिविलियर्स को वापसी के लिए मनाऊंगा : बाउचर

जोहानिसबर्ग, एएफपी: दक्षिण अफ्रीका के नवनियुक्त मुख्य कोच मार्क बाउचर ने कहा है कि वह एबी डिविलियर्स सहित हाल में संन्यास लेने वाले कुछ खिलाड़ियों को अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले टीम में वापसी के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। बाउचर को शनिवार को 2023 तक दक्षिण अफ्रीका का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में टी-20 विश्व कप होगा, जिसमें 10 महीने का समय है।

बाउचर ने कहा कि जब आप विश्व कप में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके लिए खेलें। अगर मैं मानता हूं कि वह (डिविलियर्स) हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं तो मैं उसके साथ बात क्यों नहीं करना चाहूंगा। मैंने अभी पद संभाला है, मैं कुछ खिलाड़ियों के साथ बात कर सकता हूं और देखूंगा कि वे किसी स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि आप विश्व कप में अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चाहते हैं और अगर इसके लिए आपको मीडिया, टीम के साथियों के साथ कुछ मुद्दों को सुलझाने की जरूरत पड़े और दक्षिण अफ्रीका के लिए अच्छा हो तो फिर ऐसा क्यो नहीं करें। दक्षिण अफ्रीका के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले पूर्व कप्तान डिविलियर्स ने पिछले साल मार्च में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और अब दुनिया भर के फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंटों में खेल रहे हैं। बाउचर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को टी-20 विश्व कप में अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की जरूरत है और वह कोलपैक करार करने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धता का स्वागत करेंगे।

खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डाल सकते : बीसीबी प्रमुख

ढाका, आइएएनएस: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के प्रमुख नजमुल हसन ने साफ कर दिया है कि बीसीबी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए अपने खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डाल सकता। बीसीबी का कहना है कि अगर आगामी प्रस्तावित सीरीज के लिए सुरक्षा क्लीयरेंस मिल भी जाती है तो भी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान जाने को लेकर दबाव डालना उचित नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी सीरीज के लिए जो कार्यक्रम भेजा है, उसके मुताबिक दोनों टीमों के बीच जनवरी और फरवरी में दो टेस्ट और दो टी-20 मुकाबले खेले जाने हैं। ऐसे में जबकि इस सीरीज के लिए बीसीबी को सुरक्षा क्लीयरेंस का इंतजार है। हसन मानते हैं कि इन सब तमाम बातों के बावजूद खिलाड़ियों पर पाकिस्तान जाने को लेकर दबाव नहीं बनाया जा सकता है और इसके लिए खिलाड़ियों की रजामंदी जरूरी है।

विराट कोहली के डीएनए में ही बसती है आक्रामकता : ब्रायन लारा

लारा ने कहा, धौनी विश्व कप के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प, रोहित, विराट और वार्नर जैसे खिलाड़ी पैदा करते हैं रोमांच

क्रिकेट अगर एक फिल्म है तो ब्रायन लारा उस फिल्म के सबसे मनोरंजक किरदार। करीब 17 साल के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में लारा ने क्रिकेट के हर उतार-चढ़ाव को देखा। बेशक वह अब मैदान से दूर हो गए हों, लेकिन क्रिकेट से आज भी उन्हें उतना ही लगाव है जितना उन्हें खेलते समय हुआ करता था। ऊषा के ब्रांड एंबेसडर लारा की पारखी नजर धौनी और पंत ही नहीं, बल्कि सचिन और विराट की तुलना को भी सही नहीं मानती। उन्हें लगता है कि आक्रामकता विराट के डीएनए में है और इसे सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर के विश्व रिकॉर्डधारी वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज **ब्रायन लारा** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने क्रिकेट से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। पेश है उस बातचीत के प्रमुख अंश :

- **भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल ही में खत्म हुई टी-20 सीरीज काफी रोचक रही। अब वनडे सीरीज चल रही है। आपको कैसे नतीजे की उम्मीद है?**

-देखिए, अगर तीन मैचों की टी-20 सीरीज की बात करें तो वेस्टइंडीज वह सीरीज जीत सकता था। पहले टी-20 में अगर उसने अच्छी गेंदबाजी की होती तो नतीजा उसके पक्ष में हो सकता था। जहां तक वनडे सीरीज की बात है तो वेस्टइंडीज के पास सीरीज जीतने का अच्छा मौका है। उसके पास अच्छे युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो वेस्टइंडीज को सीरीज में जीत दिला सकते हैं। उन्हें विराट की टीम के सामने अगर जीत हासिल करनी है तो सौ फीसद प्रदर्शन करना होगा।

- **कुछ समय पहले संन्यास लेने वाले ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। ब्रावो के आने से वेस्टइंडीज की टीम में कितना फर्क पड़ेगा?**

-ड्वेन ब्रावो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से किसी टीम पर सकारात्मक असर पड़ता है। आइपीएल की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स हो या फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग की टीम त्रिनिबैगो नाइटराइडर्स हो, उन्होंने हमेशा टीम में अपनी छाप छोड़ी है। इसी तरह हमेशा से उन्होंने वेस्टइंडीज पर सकारात्मक असर छोड़ा है। हालांकि टीम में वापसी उनके लिए आसान नहीं होगी। उन्हें इसके लिए लड़ना होगा, अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और फॉर्म दिखानी होगी। मुझे लगता है कि अभी वेस्टइंडीज की टीम में काफी प्रतिस्पर्धा है। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि ब्रावो आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम में जगह बनाएंगे।

- **धौनी को आराम देकर हाल के दिनों में रिषभ पंत को खूब आजमाया गया है। आगामी टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए आप इनमें से किसे बेहतर मानते हैं?**

-मौजूदा हालात के हिसाब से मैं महेंद्र सिंह धौनी के साथ जाना चाहूंगा। धौनी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और आप उनकी तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि धौनी अभी भी फिट हैं और किसी टीम के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने भारत के लिए बेहतरीन नतीजे दिए हैं। हालांकि, अगर आप युवा रिषभ पंत की बात करें तो वह महज अभी 21 साल के हैं और उन पर अच्छा प्रदर्शन करने का अभी दबाव है। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट धर्म की तरह है और आपको टीम में बने रहने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पंत के अलावा संजू सैमसन के रूप में भी भारत के पास अच्छा विकल्प है। साथ ही केएल राहुल भी जरूरत पड़ने पर विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में भारत के पास विकेटकीपर के लिए बहुत विकल्प हैं।

- **हाल ही में आपने कहा था कि रोहित शर्मा आपके एक पारी में 400 टेस्ट रन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। आपको उनकी बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?**

-रोहित एक रोमांच पैदा करने वाले क्रिकेटर हैं। जब आप क्रिकेट या दूसरा कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें मनोरंजन एक अहम हिस्सा होता है। मुझे हमेशा रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने रोमांचित किया है। इन सभी ने मैदान में जाकर अपने खेल से लोगों के बीच रोमांच पैदा किया है और उनका खूब मनोरंजन किया है।

उत्साही और जुनूनी क्रिकेटर हैं। ये सभी काबिलियत एक शानदार खिलाड़ी को चरितार्थ करती हैं। यह सब उनके डीएनए का हिस्सा है और हम सभी को इसे स्वीकारना होगा। यह उनके खेल के लिए भी अच्छा है।

- **विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। आप सचिन के साथ खेल चुके हैं और अब आप विराट को खेलते देख रहे हैं। दोनों में किस तरह की तुलना की जा सकती है?**

-मैं इन दोनों खिलाड़ियों ती तुलना नहीं कर सकता। संभवतः ये दोनों भारत के महानतम खिलाड़ी हैं। सचिन अपने करियर के दौरान अद्भुत थे और विराट भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। दोनों की कामयाबियां बेहतरीन रही हैं। मुझे इन दोनों के बीच तुलना बिलकुल भी पसंद नहीं है।

- **निलंबन से लौटने के बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से निलंबन के बाद इन दोनों में क्या बदवाल देखने को मिले हैं?**

-इन दोनों ने निलंबन के बाद मानसिक रूप से मजबूती के साथ वापसी की है। जिस दौर से ये दोनों गुजरे हैं, वैसे दौर से गुजरना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होता है। जो हुआ वह दुर्भाग्यपूण था, लेकिन जिस तरह की लय के साथ उन्होंने वापसी की है, वह साबित करता है कि वे मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं।

- **विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत सबसे आगे चल रहा है। इस पहल को आप कैसे देखते हैं और भारत को किससे अच्छी चुनौती मिल सकती है?**

-यह एक अच्छी पहल है। लंबे समय से इसी पहल का इंतजार किया जा रहा था। यह अपनी तरह की ऐसी पहली कोशिश है। इसलिए इसे सफल बनाने के लिए कुछ चीजों को बदलनी होगी। जहां तक भारत को चुनौती देने के बात है तो उसे ऑस्ट्रेलिया इस समय कड़ी चुनौती दे सकता है। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। किसी भी टीम के लिए इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना भी काफी मुश्किल होता है। भारत भी इस समय शानदार क्रिकेट खेल रहा है और उसे हराना किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल होगा।

- **आपके क्रिकेट करियर के दौरान कौन सा वह गेंदबाज था जिसे आपको खेलने में सबसे ज्यादा परेशानी होती थी?**

-वसीम अकरम। मेरे समय में वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे। उनके पास अच्छी गति थी। मुझे अपना शिकार बनाने में ग्लेन मैक्ग्रा सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा बार अपना शिकार बनाया। इसी तरह शेन वॉर्न और मुरलीधरन खास स्पिनर थे। सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि मेरे समय में कई महान गेंदबाज थे।

21 दवाओं के बिक्री मूल्य में 50 फीसद बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने फार्मा सेक्टर की मांग पर। इससे एंटीबायोटिक, एंटीएलर्जिक, मलेरिया और विटामिन सी की दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं।

शब्द बदलिए, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे...

स्वच्छ भाषा अभियान के कैंप में मौजूद अभिभावक। सौजन्य : सुभाषी फाउंडेशन

रवि प्रकाश तिवारी, मेरठ

- **स्वच्छ भाषा अभियान से समाज में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश**
- **मेरठ से शुरू अभियान 13 राज्यों में फैला, 250 से ज्यादा प्रशिक्षक तैयार**

नेहा गुप्ता, संस्थापक, सुभाषी फाउंडेशन। जागरण

मूर्ख हो क्या? बदमाश कहीं के...। शैतान...। तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी ...। बच्चों के साथ इस तरह का संवाद गाहे-बगाहे हर घर में सुनने को मिल जाएगा। गुस्सा आने पर अभिभावक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बच्चों को अनुशासित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अनजाने में बच्चों के समूचे व्यक्तित्व और रवैये में नकारात्मकता भर रहे होते हैं। सुभाषी फाउंडेशन इन्हीं गलतियों को अभिभावकों-शिक्षकों को बताकर स्वच्छ भाषा अभियान की अलख जगा रहा है।

इनका कहना है कि स्वच्छ भाषा से बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह उसकी सोच, विचार, व्यक्तित्व को निखारती है। पिछले प्रयासों में इसकी सफलता भी दिखी है। मेरठ निवासी नेहा गुप्ता, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है, कहती हैं, मेरे मन में आया कि स्वच्छता की बात तब तक अधूरी है, जब तक कि आचार-विचार-व्यवहार की गंदगी को दूर नहीं कर लिया जाए। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसी सोच के साथ अक्टूबर 2017 में स्वच्छ भाषा अभियान की नींव रखी, जो आज 13 राज्यों तक फैल चुका है। संस्था का तर्क है कि ध्वनि ऊर्जा बहुत देर तक वातावरण में बनी रहती है। यही वजह है कि भाव सकारात्मक होते हुए भी भाषा गलत हुई तो यह प्रतिकूल प्रभाव छोड़ जाती है।

शिक्षकों के लिए इनका कहना है कि आप बच्चों को यह न कहें कि योर हैंडराइटिंग इज पूअर या तुम्हारी लिखावट खराब है। कहें कि अपनी लिखावट को और बेहतर बनाएं। इसी तरह दुलार से भी बेटे को शैतान कहने की बजाए उसे तेज, ऊर्जावान या एक्टिव कहें। स्वच्छ भाषा के इस्तेमाल से लड़ाई-झगड़े भी कम होंगे और हमारे विचार स्वस्थ और स्वच्छ होंगे, जो बेहतर कल का आधार बनेंगे।

पानी के अणुओं पर भी दिखा असर : नेहा ने बताया कि जापानी शोधकर्ता डॉ. मुसारो इमैटो के शोध से निकले निष्कर्ष ही स्वच्छ भाषा अभियान का वैज्ञानिक तर्क हैं। जापानी शोधकर्ता ने इस शोध में समझाया कि हमारे शब्दों व संगीत का पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष में मिला कि जब अच्छे शब्द कहे गए और मधुर संगीत बजाया गया तो पानी के अणुओं ने सुंदर और सकारात्मक (क्रिस्टल) छवि बनाई, जबकि कठोर, अपशब्द या कर्कश आवाज से अणुओं की क्रिस्टल छवि नकारात्मक दिखी। ऐसे में स्वच्छ भाषा का इस्तेमाल हमारे शरीर, दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यही तर्क हमारे शास्त्र-धर्मग्रंथों में भी है।

इस तरह दिया जाता है प्रशिक्षण : नेहा के मुताबिक, स्वच्छ भाषा की ट्रेनिंग लगभग 40 मिनट की होती है। प्रत्येक शिक्षक कम से कम 50 छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं, इसलिए अधिकांश प्रशिक्षण शिक्षकों को ही दिया जाता है। इनके अलावा सामाजिक संगठनों, कॉलोनियों में भी अभियान चलाया जाता है। आमने-सामने के प्रशिक्षण के साथ टेलीफोनिक ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। यह सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क।

इस तरह आगे बढ़ रहा कारवां : संस्था द्वारा अब तक 250 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 100 से अधिक कार्यशालाएं भी हो गई हैं। अकेले मेरठ में ही 70 प्रशिक्षक तैयार हो चुके हैं। मेरठ के साथ ही यह अभियान अब उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। कई मंचों पर संस्था को सराहना भी मिल चुकी है।

यहां के हर आंगन में खिलखिलाती हैं बेटियां

मप्र के हरपुरा मड़िया गांव में बेटियों के जन्म पर मनता है उत्सव, 2300 की आबादी वाले गांव में एक हजार पुरुषों पर 1096 महिलाएं

मनीष असाटी, टीकमगढ़ (मप्र)

नारी सशक्तीकरण

बेटियां एक नहीं, दो-दो घरों की इज्जत बढ़ाती हैं, इसलिए बेटियों को बोझ न समझें और उन्हें वह हर खुशी दें, जिसकी वे हकदार हैं। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के हरपुरा मड़िया गांव ने इसे सिर्फ विचार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिद्दत से अपनाया है। यहां बेटियों के जन्म पर लोग जश्न मनाते हैं। बधाइयों का दौर चलता है। महिलाएं मंगलगीत गाती हैं और जमकर नाच-गाना होता है।

टीकमगढ़ जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 901 महिलाओं का है, जबकि 2300 की आबादी वाले हरपुरा मड़िया गांव में 1000 पुरुषों पर करीब 1096 महिलाएं हैं। भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी बात तो यहां सुनाई भी नहीं देती। 98 वर्षीय शुगररानी जब नातिनों और बेटियों के किस्से सुनातीं हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह कहतीं हैं कि हमारी बेटियां आज बेटों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल रहीं हैं। दस बेटियों की मां सुधा चौबे कहती हैं कि आज लोग एक बेटी को बोझ समझते हैं, जबकि मैंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह परवरिश दी है। आज सात बेटियां शादी के बंधनों में बंधकर दूसरे परिवारों की मान-मर्यादा संवार रही हैं।

बेटी के जन्म पर सोन सिंह के घर पहुंचकर मंगल गीत गातीं महिलाएं। नई दुनिया

> नारी सशक्तीकरण के क्षेत्र में हरपुरा मड़िया एक आदर्श गांव बने, इसके लिए भी पहल की जाएगी। शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा और ग्राम पंचायत को पुरस्कृत कराने का प्रयास होगा।
>
> **– डीके दीक्षित, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, टीकमगढ़**

जन्म पर मनाते हैं जश्न : इस गांव में जब किसी परिवार में बेटी जन्मती है तो बधाइयों का लंबा दौर चलता है। हाल ही में सोन सिंह के यहां पर पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा गया जमना। गांव की महिलाओं ने आंगन में मंगल गीत गाए। नाच-गाना किया। गांव की बेटी का जब रिश्ता किया जाता है, सभी से सलाह ली जाती है। लड़के के परिवार के बारे में चर्चा होती है। गांव के सनदकुमार चौबे बताते हैं कि पांच भाइयों के उनके परिवार में 21 बेटियां हैं। स्वयं उनकी पांच बेटियां और दो बेटे हैं। गांव के रमेश राजपूत के घर में छह और इंद्रल राजपूत के घर में छह बेटियां हैं।

सुविधाओं से वंचित है बेटियों का यह गांव : सुनैना राजपूत, भावना, आराधना राजपूत व चांदनी लोधी ने बताया कि गांव में आठवीं तक स्कूल है, जिससे यहां से दूरस्थ गांव खिरिया के लिए हाईस्कूल की पढ़ाई करने जाना पड़ता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को इतना मान सम्मान देते हैं। सरकार को भी चाहिए कि उसकी योजनाओं का लाभ हमारी बेटियों को मिले।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

प्रयागराज के 61 सिलिका सैंड प्लांटों पर 4.5 करोड़ का जुर्माना

एनजीटी सख्त ▸ शंकरगढ़ स्थित सभी प्लांटों को भेजा नोटिस, 20 तक मांगा जवाब

सभी प्लांट तोड़ने के निर्देश, पर्यावरण प्रदूषण के लिए खतरा बने थे प्लांट

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

एनजीटी ने लगाया है जुर्माना। फाइल

> शंकरगढ़ के 61 सिलिका सैंड वॉशिंग प्लांट पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है। लगभग पांच माह से यह प्लांट बंद हैं। ट्रिब्यूनल से इन प्लांटों को तोड़ने का भी आदेश दिया गया है।
>
> **– न्यायमूर्ति राजेश कुमार, चेयरमैन ओवर साइट कमेटी, एनजीटी**

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यमुनापार स्थित सिलिका सैंड वॉशिंग प्लांटों से फैले प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाया है। एनजीटी ओवर साइट कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजेश कुमार ने शंकरगढ़ में 61 सिलिका सैंड वॉशिंग प्लांटों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना लगाया है। प्रत्येक प्लांट पर 7.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह रकम चार करोड़ 42 लाख 25 हजार रुपये बनती है। जुर्माना राशि इसी माह जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यमुनापार के शंकरगढ़ इलाके में संचालित उक्त सभी सिलिका सैंड वॉशिंग प्लांटों को एनजीटी के निर्देश पर इसी साल जुलाई में बंद करा दिया गया था। अब ट्रिब्यूनल ने इन प्लांट पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना ठोका है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सभी प्लांट संचालकों को इसके लिए नोटिस भेजा गया है। उनसे 20 दिसंबर तक जवाब तलब किया गया है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जेबी सिंह ने बताया कि सभी प्लांट सील करा दिए गए हैं। इन सिलिका वॉशिंग प्लांटों से निकलने वाले हानिकारक धूल के कण से 200 से ज्यादा गांव, बाजार और नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे थे। कई तरह की बीमारियां की चपेट में आ गए हैं। फसलों के उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। प्रदूषण से फलदार पौधे ही नहीं, जंगली पेड़ तक सूखते जा रहे थे। पूरा इलाका क्रिटिकल पॉल्यूशन जोन में आ गया है। इन प्लांटों में भारी मात्रा में जल का भी दोहन हो रहा था। अनुमान है कि एक प्लांट में करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी होती थी। चार-चार पंपिंग सेट लगाए गए थे, जिससे सिलिका सैंड साफ कर अलग किया जाता था। अत्यधिक जल दोहन की वजह से शंकरगढ़ विकासखंड डॉर्क जोन में आ गया था। इन प्लांटों को तोड़ने का भी एनजीटी ने निर्देश दे दिया है। ट्रिब्यूनल के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि प्लांटों को तोड़कर जमीन को पूर्व की स्थिति में लाया जाए।

मध्य प्रदेश की सीमा से सटा शंकरगढ़ इलाका पूरे देश में बेशकीमती सिलिका सैंड के लिए जाना जाता है। यहां सिलिका सैंड को सफेद सोना भी कहा जाता है। यहां से प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड के अलावा नेपाल भी सिलिका सैंड भेजा जाता था। सिलिका सैंड की प्रचुरता के चलते ही घूरपुर में ग्लास फैक्ट्री लगाई गई थी।

पटियाला के बेसहारा जख्मी कुत्तों को विदेश में मिल रहा आशियाना

- **गार्जियंस ऑफ वॉइसलेस संस्था 89 कुत्तों को भेज चुकी है विदेश**
- **ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका जैसे कई देशों के लोग लेते हैं इन्हें गोद**

गार्जियंस ऑफ वॉइसलेस संस्था की संस्थापक लुज्मा गोम्स (सबसे बाएं) के साथ पंकज अरोड़ा (मध्य में) व उनके मित्र। जागरण

संजय वर्मा, पटियाला

वाहनों की तेज रफ्तार इंसानों के लिए तो घातक है ही, साथ ही सड़कों पर दौड़ते बेसहारा पशुओं विशेषकर कुत्तों के लिए खतरनाक होती है। वाहन चालक सड़क पर दौड़ते कुत्तों को बड़ी बेरहमी से टक्कर मारकर चले जाते हैं। इससे कई कुत्तों की मौत हो जाती है और कई ताउम्र के लिए अपंग हो जाते हैं। ऐसे हादसों में जख्मी होने वाले कुत्तों को नई जिंदगी दे रही है गार्जियंस ऑफ वायसलेस संस्था। इस संस्था के स्वयंसेवी कार्यकर्ता पटियाला की सड़कों पर भटकने वाले जख्मी कुत्तों को पहले संस्था के कार्यालय ले जाते हैं। इसके बाद इनको नहलाने और उपचार करने के बाद विदेश में बैठे लोगों को गोद दे देते हैं। संस्था इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेती, बल्कि कुत्ते को गोद लेने वाले को उसके विदेश भेजने के लिए खर्च दिया जाता है। संस्था की इस कवायद से पटियाला के लगभग 89 बेसहारा कुत्तों को अलग-अलग देशों में आशियाना मिल चुका है। संस्था ने ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जर्मन जैसे देशों में भारतीय देसी कुत्ते भेजे हैं।

छोटू और हनु को मिली नई जिंदगी : बात जनवरी 2018 की है। संस्था के सदस्यों को ठंड में ठिठुरता हुआ एक बुरी तरह जख्मी पपी मिला। सदस्यों ने इसका उपचार किया। उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ, तो संस्था के सदस्यों ने उसे अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत की शेलिया ग्लास को गोद दे दिया। शेलिया ने अच्छी तरह देखरेख की। अब छोटू दो साल का हो गया है। शेलिया ग्लास अपने फेसबुक अकाउंट पर छोटू की फोटो शेयर करती हैं। शेलिया ने आठ दिसंबर को छोटू की फोटो शेयर कर उसको जन्मदिन की बधाई भी दी थी। ऐसी ही कहानी हनु की भी है। दो साल पहले वह जून 2017 में कार की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया था। संस्था के सदस्यों ने उसका उपचार किया। इसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर हनु की फोटो शेयर की। वर्जीनिया की ओलीविया ने उसे गोद लिया। अब हनु की जिंदगी आरामदायक हो गई है। ओलिविया ने 16 जून, 2018 को अपने फेसबुक अकाउंट पर हनु की फोटो शेयर की और लिखा कि हनु को गोद लिए एक साल हो गए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि उसे गोद लिया। इसी प्रकार मौली, लाडू और निक्कू को भी विदेश में आशियाना मिल चुका है।

संस्था अच्छा काम कर रही: सिंगला : मॉडल टाउन के पुरुषोत्तम सिंगला बताते हैं कि पॉश एरिया होने के बाद भी यहां सड़कों पर कुत्तों की भरमार थी। इस संस्था को एक जख्मी कुत्ते की सूचना दी गई। वालंटियर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुत्ते का उपचार किया और उसे डॉग लवर को अडाप्ट करवाया। संस्था अच्छा काम कर रही।

बेसहारा पशुओं को खौफ कम करना है काम : पटियाला के साथ ही ऋषिकेश में प्रोजेक्ट चला रही संस्था के पंजाब प्रोजेक्ट हेड पंकज अरोड़ा बताते हैं कि संस्था घायल पशुओं और पक्षियों का इलाज करती है। संस्था लोगों में बेसहारा पशुओं का बढ़ता खौफ दूर करने का काम कर रही है। बेसहारा पशुओं की संख्या कम करने के लिए इलाज के साथ इनकी नसबंदी भी की जाती है। पांच साल पहले शुरू हुई इस संस्था में तीन सदस्य थे, अब छात्र भी जुड़ चुके हैं। स्कॉटलैंड की अमांडा लेसिक कहती हैं कि देखरेख करने से भारतीय कुत्ते खूबसूरत और सेहतमंद रहते हैं। अच्छी परवरिश से वे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।

अमेरिका में की गार्जियंस ऑफ वायसलेस की स्थापना : गार्जियंस ऑफ वायसलेस संस्था की स्थापना अमेरिका में संस्था की अध्यक्ष लुज्मा गोम्स ने की है। पटियाला की सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्तों को लुज्मा गोम्स के सहयोग से विदेशियों ने अडाप्ट किया है। संस्था लावारिस कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लक्ष्य से पटियाला के अलावा पंजाब के दूसरे शहरों में भी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। भारत में इसका संचालन दिल्ली, ऋषिकेश और पटियाला में हो रहा है।

पटियाला, दिल्ली और ऋषिकेश को इसलिए चुना संस्था ने : संस्था के पंजाब प्रोजेक्ट हेड पंकज अरोड़ा बताते हैं कि वह पटियाला के ही रहने वाले हैं, इसलिए संस्था सबसे ज्यादा काम पटियाला में ही करती है। दिल्ली में संस्था का हेड ऑफिस है। संस्था की अध्यक्ष लुज्मा गोम्स भारत घूमने आती हैं। उनको ऋषिकेश पसंद है। वहां सड़कों पर लावारिस पशुओं को दयनीय हालत में देखकर उन्होंने अपनी मुहिम चलाने का फैसला लिया। बकौल पंकज, लुज्मा गोम्स कहती हैं कि ऋषिकेश जैसे पर्यटक स्थल पर सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। उस पर लावारिस पशुओं की भरमार नहीं होनी चाहिए।

हरिद्वार–देहरादून हाईवे पर फ्लाईओवर ने छीना प्रवासी परिंदों का बसेरा

दीपक जोशी, रायवाला (देहरादून)

हरिद्वार-देहरादून हाईवे के चौड़ीकरण ने प्रवासी परिंदों का प्राकृतिक वास स्थल भी छीन लिया है। बात हो रही है राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) से होकर बहने वाली सौंग नदी की। इस नदी में बन रहे नए फ्लाईओवर की वजह से नदी की धारा परिवर्तन की गई है, जिसका सीधा असर प्रवासी परिंदों के प्राकृतिक वास स्थल पर पड़ा है। धारा परिवर्तन से नदी में प्राकृतिक रूप से बनने वाली कई झील सूख गई हैं।

इन दिनों सौंग नदी में सत्यनारायण मंदिर के पास फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। यह क्षेत्र गौहरी-मोतीचूर वन्य जीव गलियारा भी है। फ्लाईओवर के लिए सौंग नदी की धारा परिवर्तित की गई, जिसका असर प्रवासी परिंदों के प्राकृतिक वास स्थल पर भी पड़ा। नदी में कई जगह प्राकृतिक रूप से बनी गहरे पानी की झील थीं, जो इस परिवर्तन से सूख गईं। इन जगहों पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी परिंदे आते रहें हैं, लेकिन इस बार सौंग नदी के तट वीरान हैं। यह स्थिति तब है, जब दुनियाभर में जैवविविधता व वन्य जीव संरक्षण के लिए चिंता जताई जा रही है।

हरिद्वार–देहरादून हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए नदी की धारा को परिवर्तित किए जाने से कुछ इस तरह सूख गई है सौंग नदी। जागरण

नवंबर से मार्च तक प्रवास करते हैं मेहमान परिंदे : शीतकाल में मध्य एशिया से हजारों किमी की यात्रा कर चकोर, वॉल क्रीपर, सैंड पाइपर, जल काग, सुर्खाब आदि विभिन्न प्रजाति के प्रवासी परिंदे राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रवास के लिए आते हैं। जो सौंग व गंगा नदी के किनारों पर नंवबर से लेकर मार्च तक रहते हैं।

बिना अनुमति बदली गई धारा : वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के बिना पार्क क्षेत्र में नदी की धारा में बदलाव या छेड़छाड़ नहीं हो सकती। पार्क सूत्रों के अनुसार फ्लाईओवर के लिए सौंग नदी की धारा परिवर्तन को अनुमति नहीं ली गई। हालांकि, वन्य जीव प्रतिपालक आरटीआर दिनेश प्रसाद उनियाल का कहना है कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यदि सचमुच नदी की धारा परिवर्तित की गई है तो इसे दिखवाया जाएगा।

आग के छल्ले के समान नजर आएगा सूर्य ग्रहण

रमेश चंद्रा, नैनीताल

▸ **26 दिसंबर को देश के कुछ ही हिस्सों में दिखेगा वलयाकार ग्रहण**

साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आग के छल्ले के समान वलयाकार होगा। भारत में 10 वर्ष बाद वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय घटना दक्षिण भारत के कुछ ही क्षेत्रों में देखा जा सकेगा जबकि अन्य हिस्सों से आंशिक सूर्यग्रहण नजर आएगा।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के पूर्व निदेशक डॉ. वहाबउद्दीन ने बताया कि 26 दिसंबर को लग रहा सूर्य ग्रहण सुबह लगभग आठ बजे शुरू हो जाएगा और दोपहर बाद 1.35 बजे समाप्त हो जाएगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने में बेहद सुंदर नजर आता है। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है। सूर्य का अंदरूनी भाग तो छिप जाता है, लेकिन बाहरी भाग खुला रह जाता है। इसके चलते यह आग के छल्ले के समान नजर आने लगता है और देखने में मनमोहक लगता है। इस ग्रहण को 'रिंग ऑफ फायर' भी कहा जाता है। भारत में वलयाकार ग्रहण तमिलनाडु, केरल व बेंगलुरु के कन्नूर, कोजिकोड, कोयंबटूर, डिंगीगुना, मदुरई व थनजावुर में नजर आएगा, जबकि देश के शेष हिस्सों में आंशिक दिखेगा।

सूर्य और चांद की स्थिति से लगता है ग्रहण

पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी के बढ़ने से वलयाकार ग्रहण होता है। इसमें चंद्रमा व धरती की दूरी इतनी अधिक होती है कि चंद्रमा सूर्य को पूर्णरूप से ढक नहीं पाता है और जब धरती के नजदीक होता है तो उसका आभासीय आकार बड़ा होता है। जब चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा धरती के जितने करीब होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। सूर्य ग्रहण चार प्रकार के होते हैं। आंशिक, पूर्ण, वलयाकार व हाईब्रिड। अलग-अलग परिस्थितियों में यह ग्रहण बनते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण सूर्य ग्रहण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सूर्य के रहस्यों को वैज्ञानिक समझने के लिए अध्ययन करते हैं। वलयाकार ग्रहण के दौरान धरती व चंद्रमा के बीच की दूरी की गणना व आकार आदि वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

जागरण विशेष

चिंतपूर्णी की दो पंचायतों में सफल रहा प्रयोग, पौधों पर आए फल, एक पौधे से होती है 250 से 300 रुपये की आमदनी, किसानों को मुफ्त बांटे जा रहे कॉफी के पौधे

ऊना में कॉफी बढ़ाएगी किसानों का जायका

नीरज पराशर, ऊना

हिमाचल प्रदेश के ऊना के चिंतपूर्णी क्षेत्र में जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं के कारण खेती से मुंह मोड़ चुके किसानों के लिए कॉफी की खेती नई उम्मीद लेकर आई है। इससे बंजर खेत लहलहाने लगे हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की आस जगी है।

धर्मसाल महंता और धर्मसाल महंता (खास) में कॉफी के करीब दो हजार पौधे लगाए हैं। इन पौधों की सफलता दर 90 प्रतिशत है। सेवानिवृत्त अध्यापक अश्वनी कुमार ने चार वर्ष पूर्व कॉफी के दो सौ पौधे लगाए थे। इन पर फल आ चुका है। उन्होंने पिछले वर्ष 300 पौधे और लगाए। अब इस क्षेत्र के शंभू दत्त, किकर सिंह, सतीश कुमार और निक्कू राम भी कॉफी की खेती कर रहे हैं। कॉफी के पौधे कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश का चाय तकनीकी कार्यालय पालमपुर निःशुल्क दे रहा है।

25 हेक्टेयर क्षेत्र हुआ आबाद : क्षेत्र में करीब छह हजार हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी थी। अब करीब 25 हेक्टेयर पर कॉफी की खेती हो रही है। बंदर और जानवर कॉफी के पौधे को नहीं खाते हैं। पानी की जरूरत नहीं होती। इस कारण यह खेती आसान है। आमदनी में इजाफा होने व बंदरों से नुकसान की आशंका कम होने से किसान इसमें रुचि ले रहे हैं।

धर्मसाल महंता में कॉफी के पौधे के साथ अश्वनी कुमार। जागरण

कॉफी के लिए अनुकूल

सैंपल सर्वे में धर्मसाल महंता क्षेत्र की जमीन और जलवायु कॉफी की खेती के लिए अनुकूल है। कॉफी का पौधा वहां होता है, जहां सूर्य की रोशनी कम और सीधी नहीं पड़ती। यहां ऐसा ही है।

> कॉफी के पौधे पर वर्ष में एक बार फल लगते हैं। एक पौधे से करीब एक किलोग्राम पैदावार होती है। एक किलोग्राम फल की कीमत 250 से 300 रुपये है। पालमपुर और दिल्ली की दो कंपनियां किसानों के उत्पाद खरीदेंगी।
>
> **–प्यार सिंह, टी प्रमोशन अधिकारी, पालमपुर**

> इस क्षेत्र के किसानों का रुझान कॉफी की तरफ बढ़ा है। सर्दी में कॉफी के पौधों को पाले से बचाना पड़ता है। पौधों पर सीधी धूप न पड़े तो उत्पादन बंपर हो सकता है।
>
> **– अश्वनी कुमार, किसान, धर्मसाल महंता (खास) पंचायत**

> उजाड़ के कारण जमीनें खाली छोड़ चुके किसान इस खेती से उत्साहित हैं। कृषि विभाग पालमपुर ने कॉफी की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर काम किया है।
>
> **–गुरमीत कौर, पंचायत प्रधान, धर्मसाल महंता (खास)**

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी संभव है। रात के तापमान में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर दिन सर्द बना रहेगा। सुबह अनेक स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहेगा।

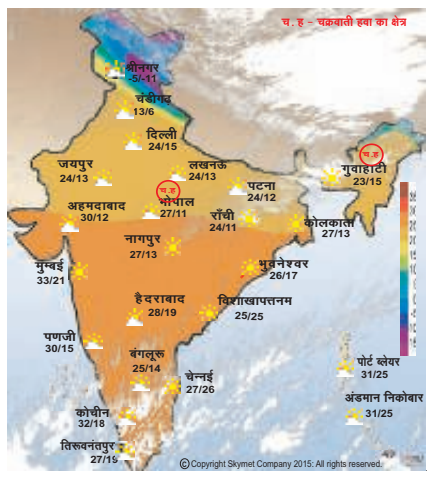

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/21/आंबा	अहमदाबाद	28/15/सा
कोलकाता	28/14/सा	बड़ौदा	29/17/आंबा
चेन्नई	26/26/सा	नागपुर	29/16/सा
हैदराबाद	29/19/सा	इन्दौर	28/17/सा
बंगलूरू	26/17/आंबा	राँची	26/14/आंबा
त्रिवेन्द्रम	26/20/आंबा	पटना	26/15/सा
गुवाहाटी	24/15/आंबा	जमशेदपुर	27/14/सा
गंगटोक	09/-2/आंबा	पुणे	30/18/सा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
सोमवार 16 दिसंबर 2019
14
www.jagran.com

सोवियत संघ से अलग हुआ कजाखस्तान

आज ही के दिन सोवियत संघ से अलग होकर कजाखस्तान अलग देश बना था। नुरसुल्तान नजरबायेव ने राष्ट्रपति चुनाव निर्विरोध जीता। इसी के बाद कजाखस्तान सोवियत संघ से अलग हुए देशों के संगठन का हिस्सा बना।

भारतीय सेना के शौर्य का विजय दिवस

आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने वाली 1971 की जंग में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से अलग देश बना।

'सूफी की सुल्तान' पदवी से चर्चित हैं गायिका हर्षदीप कौर

हिंदी और पंजाबी गायिका हर्षदीप कौर का जन्म आज ही के दिन 1986 में दिल्ली में हुआ था। 16 साल की उम्र में पहला बॉलीवुड गाना 'सजन मैं हारी' से चर्चित हुईं। सूफी की सुल्तान कही जाने वाली ये चुनिंदा गायकों में हैं, जिन्होंने किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए गाना गाया है। ऑस्कर विजेता निर्देशक डैनी बॉयल की फिल्म '127 ऑवर्स' में अपनी आवाज दी है। दिलबरो गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का आइफा और स्क्रीन अवॉर्ड मिला। उन्हें संगीत अपने पिता सविंदर सिंह से विरासत में मिला है, जिनका संगीत वाद्ययंत्रों का कारखाना है। इन्होंने 2015 में मनकीत सिंह से शादी की।

नए बैंडेज से फटाफट सही होगा फ्रैक्चर

मिलेगी राहत ▶ तेजी से रक्त वाहिकाओं का निर्माण भी हो सकेगा

शरीर के स्वयं चिकित्सा करने वाले अणुओं को इकट्ठा रखता है यह बैंडेज

न्यूयार्क, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने एक ऐसे बैंडेज को विकसित किया है जो फ्रैक्चर के स्थान पर शरीर के स्वयं से उपचार करने वाले अणुओं को इकट्ठा रखता है। यह खोज प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया को तेज करने के नए तरीकों को जन्म दे सकती है।

एडवांस मैटेरियल्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि नए बैंडेज का चूहों में प्रयोग करके भी देखा गया है। इसमें पाया गया कि इसकी मदद से चूहों में केवल तीन सप्ताह में नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण में मदद मिली साथ ही हड्डियों की बेहतर मरम्मत भी हुई।

अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी सहित अन्य शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि यह विधि अभी तक मौजूद सभी अन्य उपचार विधियों की तुलना में ज्यादा तेजी और बेहतर ढंग से काम करती है। दरअसल यह खोज पुरानी खोज पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि रासायनिक कैल्शियम फास्फेट से बने बायोमैटेरियल्स हड्डी की मरम्मत और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देते हैं।

ड्यूक यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन की सह लेखक शायनी वर्गीज ने पाया था कि जैविक अणु 'एडेनोसिन' हड्डी के विकास को बढ़ाने में विशेष रूप से बड़ी भूमिका निभाता है।

वर्गीज और उनकी टीम ने पाया कि शरीर में चोट लगने पर स्वाभाविक रूप से एडेनोसिन अणुओं की चोट वाली जगह पर बाढ़ सी आ गई, लेकिन यह क्रिया ज्यादा देर तक नहीं रही। वर्गीज ने बताया कि एडेनोसिन शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य हड्डी की मरम्मत करना नहीं है। इसलिए बिना किसी साइड इफेक्ट के एडेनोसिन को चोट वाली जगह पर रोककर रखना बड़ा काम था। इसलिए शोधकर्ताओं ने एक ऐसा बैंडेज बनाया जो फ्रैक्चर की जगह लगाया जा सके। इस बैंडेज में एडेनोसिन अणुओं को पकड़े रखने के लिए बोरोनैट मॉलीक्यूल का उपयोग किया गया है।

अणुओं के बीच के बंधन हमेशा के लिए नहीं रहते हैं इसलिए यह बैंडेज एडेनोसिन को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। नतीजतन एडेनोसिन के अणु धीरे-धीरे रिलीज होने लगते हैं।

'एडवांस मैटेरियल्स' जर्नल में प्रकाशित किया गया है अध्ययन। प्रतीकात्मक

चूहों पर किया गया प्रयोग

शोधकर्ताओं ने विकसित किए गए नए बैंडेज का चूहों पर परीक्षण भी किया। शोधकर्ताओं ने दो चूहों के हड्डियों के टूटने पर अलग-अलग उपचार दिया। एक चूहे को पुरानी विधि तो दूसरे को नए विकसित बैंडेज से उपचार दिया गया। इसमें पाया गया कि जिन चूहों में नए बैंडेज को बांधा गया था उनका उपचार तेज गति से और बेहतर हो रहा था। तीन हफ्ते बाद ऐसे चूहों में रक्त वाहिकाओं का निर्माण बेहतर तरीके से हुआ हड्डी का जोड़ भी अन्य से अच्छा रहा।

ध्रुवीय ज्योति से मंगल में नष्ट हो रहे पानी का चलेगा पता

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि मंगल ग्रह पर ध्रुवीय ज्योति (अरोरा) के माध्यम से नष्ट हो रहे पानी का पता लगाया जा सकता है। ध्रुवीय ज्योति इस लाल ग्रह पर उठने वाली रोशनी का सबसे आम रूप है। इसे सबसे पहले नासा के मावेन स्पेसक्राफ्ट ने 2016 में देखा था।

जियोफिजिकल रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि पृथ्वी पर ध्रुवीय क्षेत्रों के पास आमतौर पर रात में आकाश में रंगीन रोशनी को देखा जाता है, जिसे ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। हालांकि, अमेरिका में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर (जीएसएफसी) के शोधकर्ताओं ने कहा कि मंगल ग्रह पर इस घटना को प्रोटॉन अरोरा कहा जाता है। यह मंगल में दिन के समय होता है। कहा गया कि इसे मानव आंख से देखना संभव नहीं है, इसे मावेन स्पेसक्राफ्ट में लगे अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्टोग्राफ उपकरण के जरिये पता लगया गया है। मावेन स्पेसक्राफ्ट इस बात की जांच करता है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल और पानी कितना खत्म हो चुका है।

इस तरह लगाया जा सकता है पता : शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रोटॉन अरोरा अप्रत्यक्ष रूप से मंगल ग्रह पर पानी से उत्पन्न हाइड्रोजन से बनता है। यह पानी के खत्म होने की प्रक्रिया होती है। इसलिए इस अरोरा (ध्रुवीय ज्योति) की मदद से खत्म हो रहे पानी को ट्रैक किया जा सकता है।

इस तरह बनती है ध्रुवीय ज्योति : शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रोटॉन अरोरा तब बनता है जब सौर हवाओं से निकले सब एटामिक पार्टिकल, प्रोटॉन मंगल के ऊपरी वायुमंडल से टकारते हैं। इसके बाद ये प्रोटॉन मंगल के वातावरण में मौजूद हाइड्रोजन के अणुओं से इलेक्ट्रॉन चुराकर प्राकृतिक अणुओं में बदल जाते हैं। यह पक्रिया जब तेजी से होती है एक पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित होता है।

स्पेक्ट्रम

पानी से उत्सर्जित हाइड्रोजन से मंगल पर निकलती है रंग-बिरंगी रोशनी

प्रतीकात्मक

इधर-उधर की

फैमिली फोटो के लिए करनी पड़ी मशक्कत

वेल्स, एजेंसी : एक कुत्ते या बिल्ली को सामने बिठाकर उसकी फोटो खींचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब 17 कुत्ते-बिल्लियों की एक साथ फोटो खींचनी हो तो आप परेशानी समझ सकते हैं। दरअसल, कैथी स्मिथ अपने सभी पालतुओं की एक साथ फोटो खींचना चाहती थी। एक परफेक्ट फोटो के लिए कैथी को सात दिन का वक्त लगा। इस दौरान उसे अपने आठ कुत्तों और नौ बिल्लियों को सोफे के ऊपर और आसपास बिठाने और लैंस की ओर दिखाने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी। कैथी ने कहा, जब वह फोटो खींचने में कामयाब रही तो यह मुझे रोमांचित कर रहा था। उसने कहा कि यह किसी पारिवारिक फोटोग्राफ की तरह है। कैथी के मुताबिक कुत्तों को बिठाना आसान था, लेकिन बिल्लियों के साथ अलग मामला था। कैथी इन पालतुओं का बचाव और देखभाल करती हैं। उनके यहां आने वाले लोग इन पालतुओं को देखकर चौंक जाते हैं।

जमैका की टोनी सिंह बनीं मिस वर्ल्ड

लंदन, प्रेट्र : जमैका की 23 वर्षीय टोनी एन सिंह ने इस साल का मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। भारत की सुमन राव (20) सेकेंड रनरअप यानी तीसरे स्थान पर रहीं। राजस्थान की रहने वालीं सीए छात्रा सुमन को इस साल जून में मिस इंडिया वर्ल्ड-2019 चुना गया था।

शनिवार को टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम में टोनी को विजेता घोषित किया गया। उन्हें पिछली मिस वर्ल्ड मैक्सिको की वैनेसा पोंस ने ताज पहनाया। फ्रांस की ऑफली मेजिनो फर्स्ट रनरअप (दूसरे स्थान) पर रहीं। भारतवंशी पिता ब्रैडशॉ सिंह और अफ्रीकी-कैरेबियाई मां जहरीन बेली के घर जन्मीं टोनी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की छात्रा हैं। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने व्हिटनी ह्यूस्टन के हिट गीत 'आइ हैव नथिंग' गाया, जिस पर दर्शकों ने उन्हें हाथोंहाथ लिया।

मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद : टोनी ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझ पर विश्वास जताने के लिए सभी जमैकावासियों का आभार व्यक्त करती हूं। मेरा दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया है। परिवार और दोस्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मां (जहरीन) मैं आपसे बहुत-बहुत प्यार करती हूं। आप मेरी ताकत हैं, आप ही मेरी प्रथम समर्थक और चियरलीडर हैं। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं।' टोनी ने दुनियाभर की लड़कियों से स्वयं पर और अपने सपनों पर विश्वास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम और योग्य हैं। यह ताज मेरा नहीं बल्कि आपका है।' टोनी जमैका की चौथी प्रतियोगी हैं, जिन्होंने मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। 1963, 1976 और 1993 में जमैका की सुंदरियां यह खिताब जीत चुकी हैं।

भारतवंशी पिता की संतान हैं टोनी

भारत की सुमन राव सेंकेंड रनरअप रहीं

मिस वर्ल्ड 2018, मेक्सिको की वनेसा पान्स डि लियोन ने टोनी-एन सिंह को ताज पहनाया। प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप फ्रांस की ओफिली मेजिनो (बाएं) और सेकेंड रनर अप भारत की सुमन रतन सिंह राव (दाएं) रहीं। एएफपी

डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लांच किया आधिकारिक टिकटॉक चैनल

सैनफ्रांसिस्को, आइएएनएस : बाइटडांस टेक्नोलॉजी के स्वामित्व वाली चाइना की शार्ट वीडियो मेकिंग एप टिकटॉक के साथ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) ने करार किया है। इसके तहत डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने टिकटॉक चैनल पर अन्य दैनिक सामग्री के माध्यम से इन-रिंग मैचों के साथ-साथ बैकस्टेज एक्शन के क्षणों को साझा करेगा।

साझेदारी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई 30 से अधिक सुपरस्टार और 'हॉल ऑफ फैमर्स' के लिए प्रवेश थीम उपलब्ध करा रहा है। इसमें 'स्टोन कोल्ड' स्टीव ऑस्टिन, द अंडरटेकर, अल्टीमेट वॉरियर, बैकी लिंच, जॉन सीना और साशा बैंक्स शामिल हैं।

एडवांस मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जयार डोनलन ने गत दिवस कहा, 'यह साझेदारी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटेंट के साथ एक नए स्तर की पेशकश करता है, जिससे कि टिकटॉक समुदाय को डब्ल्यूडब्लयूई की विश्व प्रसिद्ध सुपरस्टार से जुड़ी अपनी खुद की साझा कहानियों को बनाने में मदद मिल सकेगी।'

अंतरिक्ष मिशनों की असफलता से निराश नहीं हों : नासा

नई दिल्ली, आइएएनएस: अंतरिक्ष मिशन असफल होते हैं और वैज्ञानिक समुदाय को इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यह ठीक है कि विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर सका, लेकिन इसके लिए फिर से प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवसाय है। यह बात नासा जेपीएल (जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी) में नवाचार और प्रौद्योगिकी अधिकारी टॉम सोडरस्ट्राम ने कही। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का मलबा मौजूद है और इसमें कई विसंगितयां मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इसका पता नासा और इसरो में से कौन पहले लगाता है। चंद्रयान-2 मिशन की सबसे बड़ी सीख यह है कि इस तरह के मिशन विफल होने के लिए ही होते हैं और नासा से बेहतर इसे कोई और नहीं जानता है। रोवर को सतह पर उतारना बहुत मुश्किल काम है। यह कभी-कभी काम करता है। इसलिए हम हर बार सुपर नर्वस हो जाते हैं। हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर एक भी चीज गलत हो गई तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। सोडरस्ट्राम ने कहा कि यह एक कठिन व्यवसाय है और हम इसे सिर्फ इसलिए करना बंद नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे एक या दो बार रोवर सफलतापूर्वक सतह पर नहीं उतर सके। उन्होंने कहा कि जब हम चांद पर गए थे तो कई बार असफल हुए थे, लेकिन अंततः हम इसमें सफल हुए। इधर, इसरो अध्यक्ष सिवन ने कहा कि उसके अपने आर्बिटर ने दुर्घटनाग्रस्त विक्रम लैंडर का पता लगा लिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसरो नासा द्वारा किए गए दावों का खंडन नहीं करेगा।

शोध अनुसंधान

कैंसर के इलाज में सहायक हो सकते हैं एंटीबायोटिक

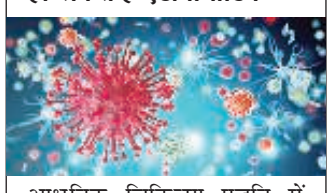

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एंटीबायोटिक दवाओं को बेहद अहम माना जाता है। विभिन्न संक्रमण से निपटने में इनका इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैंसर के इलाज में रेडिएशन से पहले यदि मरीज को एंटीबायोटिक दवा दे दी जाए, तो इलाज और प्रभावी हो सकता है। इससे शरीर की क्षमता बढ़ती है। चूहे पर प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटीबायोटिक देने से कैंसर कोशिकाओं को मारने की शरीर की क्षमता बढ़ती है। प्रतिरक्षा प्रणाली उन कैंसर कोशिकाओं से बेहतर तरीके से लड़ पाती है, जिन्हें रेडिएशन का निशाना बनाया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली उन कोशिकाओं को निशाना बनाने में भी सक्षम हो पाती है, जो शरीर के अन्य हिस्सों में होती हैं और रेडिएशन से बची रह जाती हैं।

- एएनआइ

बुढ़ापे के लक्षणों से बचाती है अल्जाइमर की दवा

प्रयोग के स्तर पर अल्जाइमर के इलाज में सक्षम पाई गई दो दवाएं बुढ़ापे के लक्षणों से बचाने में भी कारगर हैं। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ता जाता है। 65 साल की उम्र के बाद हर पांच साल में खतरा दोगुना हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए हैं कि उम्र बढ़ने से दिमाग में ऐसा क्या होता है, जो अल्जाइमर का कारण बनता है। हाल में वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर के इलाज के लिए दो घटकों सीएमएस121 और जे147 की खोज की है। ये दोनों तत्व बुढ़ापे और अल्जाइमर से पड़ने वाले दबाव में भी दिमाग के न्यूरॉन को जीवित रखने में सफल रहे हैं। अब इन दोनों तत्वों को बुढ़ापे के लक्षणों से भी बचाने में कारगर पाया गया है।

- एएनआइ

लाइट शो

रूस की राजधानी मास्को के गोर्की पार्क में नववर्ष और क्रिसमस के उपलक्ष्य में विशाल कलाकृतियां स्थापित की गई हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र बनी हुई हैं। इन्हें हजारों एलइडी लाइटों से सजाया गया है। इसके अलावा रेड स्क्वायर, सोलोन्की पार्क को भी लाइटों से सजाया गया है। यहां नववर्ष के जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आतिशबाजी शो भी खास आकर्षण हैं। एएफपी

जलवायु बचाने के लिए प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रविवार को जलवायु परिवर्तन रैली को लेकर रेड रेबेल्स ग्रुप के सदस्यों ने सिडनी ओपेरा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लाल रंग की खास तरह की ड्रेस पहनकर इसमें शामिल हुए। यह एक्टिंक्शन रिबेलियएन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो इंग्लैंड सहित कई देशों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की ओर ध्यान दिलाने के लिए आंदोलनरत है। रेड रेबेल्स के सदस्यों ने प्रदूषण रोकने के लिए सरकार से ठोस उपाय किए जाने की मांग की। पिछले दिनों जंगलों में लगी आग की वजह से बड़े हिस्से में धुंध और धुआं छा जाने से लोगों को घुटन महसूस होने लगी थी। एएफपी

स्क्रीन शॉट

'बाहुबली' के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा : राम्या कृष्णन

सात सवाल

सुपरहिट हिट फिल्म 'बाहुबली' में शिवगामी का किरदार निभाने के बाद राम्या कृष्णन अपने करियर से संतुष्ट हैं। वह इन दिनों एमएक्स प्लेयर पर वेब शो 'क्वीन' में नजर आ रही हैं, जिसमें वह शक्ति शेषाद्रि का किरदार निभा रही हैं।

• 'बाहुबली' की सफलता के बाद जीवन किस तरह बदला है? लोग कहते हैं कि चालीस पार की हीरोइनों को जल्दी काम नहीं मिलता है...?

- एक छोटे से ब्रेक के बाद मैंने 'बाहुबली' के लिए शूटिंग करनी शुरू की थी, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 'बाहुबली' के बाद मुझे सशक्त किरदार ऑफर हो रहे हैं। अब कलाकारों के पास बहुत सारे अवसर हैं। फिल्ममेकर्स महिलाओं को भी अहम किरदार में कास्ट कर रहे हैं।

• तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने करियर की शुरुआत आपकी ही तरह कम उम्र में की थी। क्या इन बातों ने आपको यह किरदार करने के लिए प्रेरित किया?

- इस किरदार में जयललिता की झलक होगी, लेकिन यह कहानी अनिता शिवकुमारन की किताब पर आधारित है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। उसमें मुख्य किरदार शक्ति शेषाद्रि का है, जो मैं निभा रही हूं। अगर वह आपको जयललिता की याद दिलाता है तो अच्छी बात है। मैं शक्ति शेषाद्रि के किरदार से पूरी तरह से जुड़ी हूं। कई सारी घटनाएं हैं, जो दिल को छूने वाली और खूबसूरत हैं।

• कंगना रनोट भी जयललिता की बायोपिक कर रही हैं। ऐसे में आप के बीच तुलना होगी।

- हां, लेकिन कंगना जयललिता की बायोपिक कर रही हैं, लेकिन मैं उनकी बायोपिक नहीं कर रही हूं। यह एक बड़ा अंतर है। तुलना करना न करना दर्शकों पर निर्भर करता है।

• आप दक्षिण भारत से हैं। जयललिता को राजनेता के तौर पर कैसे देखती हैं?

- जब मैंने कन्नड़ फिल्म 'नीलांबरी' का किरदार किया था, तो लोगों ने उसकी तुलना भी जयललिता से की थी। मैं उनकी बड़ी प्रशंसक हूं। ऐसा किरदार करना, जो उनके जैसा हो या उनकी याद दिलाता हो, उस पर मुझे गर्व महसूस होता है।

• जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? शक्ति के जीवन में भी कई चुनौतियां हैं...?

- बहुत सारी चुनौतियां हैं। शक्ति के बारे में जानने के बाद मैं उनसे प्यार करने लगी हूं। किस्मत और उसके जीवन ने एक साधारण-सी लड़की को चुनौतियों के सामने धकेल दिया। वह उन कठिनाइयों से बाहर आकर एक सशक्त महिला की तरह लोगों के सामने खड़ी होती है।

• आपको लगातार सशक्त किरदार मिल रहे हैं?

- पहले से ज्यादा मुझे अपने करियर का यह वक्त ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे चुनौतीपूर्ण किरदार मिल रहे हैं। दिलचस्प किरदार ऑफर हो रहे हैं।

-स्मिता श्रीवास्तव

अभिनय में वापसी के लिए तैयार हैं तनुश्री दत्ता

पिछले साल हैशटैग मी टू मूवमेंट से बॉलीवुड सहित पूरी दुनिया में सनसनी मचाने वाली अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को इस आंदोलन से क्या मिला और क्या खोया, इसका जवाब तो सिर्फ उन्हीं के पास होगा। बहरहाल, अब खबर यह है कि तनुश्री जल्द ही बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाली हैं। इसके लिए वह जिम में पसीना बहा रही हैं। खबर है कि हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एक डिजिटल सीरीज के लिए उनसे संपर्क किया है। सूत्र के अनुसार, 'इसके लिए तनुश्री ने डांस क्लास भी ज्वॉइन कर ली है। वह नियमित रूप से स्वीमिंग, योग और साइकिलिंग के अलावा दूसरे वर्कआउट भी कर रही हैं, ताकि वेब सीरीज के लिए खुद को फिट कर सकें। यही नहीं, तनुश्री मेडिटेशन और आध्यात्मिक क्लासेस भी ले रही हैं, ताकि मानसिक रूप से भी दृढ़ हो सकें।' उन्होंने कहा कि खुद को सक्षम बनाने का प्रयास कर रही हूं।

बोनी कपूर की तमिल फिल्म में अजित के साथ होंगी यामी

काफी दिनों से चर्चा थी कि बॉलीवुड के लोकप्रिय निर्माता-निर्देशक बोनी कपूर दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार अजित कुमार को लेकर फिल्म 'वलिमई' बनाने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन एच विनोद करेंगे। हालांकि अपरिहार्य कारणों से फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। हाल ही में बोनी कपूर ने यह जानकारी भी दी थी कि अजित कुमार इस फिल्म में पुलिस अधिकारी का किरदार निभाएंगे। पर, तब तक फिल्म की अभिनेत्री का नाम नहीं पता चला था। अब चर्चा है कि बोनी कपूर के प्रोडक्शन वाली दूसरी तमिल फिल्म में यामी गौतम अजित के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी। इससे पहले बोनी कपूर ने यह कहा था कि इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी और यह 2020 में दिवाली पर रिलीज की जाएगी। अजित इसमें पुलिस अधिकारी का किरदार निभाएंगे।

एलनाज ने अनाथ बच्चों को दान किए कपड़े

हाल ही में सुपरहिट हुई वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' में अपने किरदार से चर्चित हुईं अभिनेत्री एलनाज नौरोजी सामाजिक कामों में भी सक्रिय रहती हैं। हाल में उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े दान किए। वह बताती हैं, 'मेरा पालन-पोषण काफी अच्छी स्थिति में हुआ, लेकिन कुछ भी खरीद लूं, ऐसी आजादी नहीं मिली। मैंने जब कमाना शुरू किया तो दान करने की आदत भी डाल ली। कई वर्षों से मैं अपने कपड़े दान करती आ रही हूं। हमारे देश में कई परिवार ऐसे हैं, जिनके पास क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ला सकूं। मैं समर्थ लोगों से कहूंगी कि वे भी पैसे, कपड़े या खाना गरीबों को दान कर सकते हैं।' अभिनेत्री ने बताया कि वह जब रेस्तरां में खाने जाती हैं और प्लेट में कुछ बच जाता है, तो वे उसे पैक करवा लेती हैं और बाहर आकर भूखों को दे देती हैं। उनका मानना है कि छोटे-छोटे प्रयासों से दुनिया बेहतर बन सकती है।

चिंताजनक

निम्न और मध्यम आय वाले देशों के हालात चिंताजनक, ज्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से रोगजनकों से लड़ने की क्षमता हो रही कम

एंटीबायोटिक के अधिक इस्तेमाल से खतरे में बच्चे

बोस्टन, प्रेट्र: निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बच्चे अपने जीवन के पहले पांच वर्षों के दौरान औसतन 25 तरह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। यह मात्रा इतनी अधिक है कि इससे रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है और दुनियाभर में एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी बढ़ सकता है।

पहले के अध्ययनों में यह बताया गया है कि दवा प्रतिरोध जिसे एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंट कहते हैं, इसकी वजह से दुनिया में प्रति वर्ष हजारों लोगों की मौत होती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो 2050 तक इसकी वजह से प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच जाएगी।

अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित टीम ने कहा कि इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक दुनियाभर में एंटी बायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग है।

उन्होंने बताया कि उच्च आय वाले देशों में एंटीबायोटिक के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में खासकर बच्चों के बीच इन दवाओं के सेवन के बारे में बहुत कम जानकारी है।

प्रतीकात्मक

उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अफ्रीकी देश तंजानिया में 90 फीसद बच्चे जब अस्पताल जाते हैं उन्हें एंटीबायोटिक की एक फुल डोज दी जाती है, जबकि असल में उनको जरूरत केवल उसके पांचवे हिस्से की होती है।

'लैंसेट एंफेक्शियस डिसीज' नामक जर्नल में प्रकाशित अपनी तरह के पहले अध्ययन में शोधकर्ताओं ने निम्न और मध्यम आय वाले आठ देशों में बच्चों को दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स को देखा। इन देशों में नेपाल, नामीबिया, केन्या और हैती भी शामिल थे।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर और इस अध्ययन की सह लेखक जेसिका कोहेन ने बताया कि इस अध्ययन के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स की खपत के बारे व्यापक जानकारी मिली है। अध्ययन से पता चलता है कि इन देशों में बच्चों को पांच साल की उम्र में ही 25 तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। परिणामों से पता चलता है कि औसतन एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल सांस की बीमारी वाले बच्चों के हर पांच मामले में चार को, दस्त के 50 प्रतिशत मामले में और मलेरिया वाले बच्चों में 28 प्रतिशत मामलो में किया गया। हालांकि, शोधकर्ताओं ने बताया कि इन देशों में भी एंटीबायोटिक की खपत के मामले भिन्न-भिन्न हैं। जैसे कि सेनेगल में एक बच्चे को पांच वर्ष की उम्र तक प्रत्येक वर्ष एक डोज एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी। वहीं युगांडा में यह आंकड़ा 12 तक था। शोधकर्ताओं ने बताया कि उच्च आय वाले देशों जैसे कि यूरोप में प्रत्येक बच्चा हर साल एक डोज से भी कम एंटीबायोटिक लेता है।